



■ बजट : सता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध बरकरार - 7



■ केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बोली-अधिक आयकर संग्रह मध्य वर्ग के आगे बढ़ने का सबूत- 10



■ बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं के बीच 13वें आम चुनाव के लिए हुआ मतदान - 11



■ इटली ने नेपाल को रौंदकर आईसीसी टूर्नामेंट में जीत का खाता खोला - 12

आज का मौसम
 26.0° अधिकतम तापमान
 11.0° न्यूनतम तापमान
 सूर्योदय 06.46
 सूर्यास्त 06.00

आमृत विचार

एक सम्पूर्ण दैनिक अखबार

www.amritvichar.com

2 राज्य | 6 संस्करण

■ लखनऊ ■ बरेली ■ कानपुर ■ मुरादाबाद ■ अयोध्या ■ हल्द्वानी

शुक्रवार, 13 फरवरी 2026, वर्ष 36, अंक 9, पृष्ठ 12+4 ■ मूल्य 6 रुपये

परेशान नहीं कर पाएंगे रिकवरी एजेंट आरबीआई के नए सख्त नियम लागू

मुंबई, एजेंसी

बैंक के लिए कर्ज वसूली करने वाले रिकवरी एजेंट अब परेशान नहीं कर पाएंगे क्योंकि आरबीआई ने बैंक एजेंटों की नियुक्ति और उनके कामकाज के नियमन के लिए गुरुवार को नियमों का मसौदा जारी किया। इसमें एजेंट के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य करने और कर्जदारों को किए जाने वाले सभी फोन कॉल की रिकॉर्डिंग का प्रावधान है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि वसूली एजेंट द्वारा उधारकर्ता को किए गए सभी फोन कॉल को रिकॉर्ड किया जाए। इसके साथ

● कर्ज वसूली एजेंटों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य, फोन कॉल की रिकॉर्डिंग संबंधी नियमों का मसौदा जारी



वसूली के लिए उधारकर्ता के घर जाने पर भी अपना आचरण संयमित रखेगा। आरबीआई इस पर भी विचार कर रहा है कि वसूली एजेंटों के लिए भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आईआईबीएफ) द्वारा संचालित 'ऋण वसूली प्रशिक्षण' को अनिवार्य किया जाए। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक में एजेंटों के आचरण को नियमित करने के लिए कदम उठाने की बात कही थी। पहले ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें वसूली एजेंट के खराब व्यवहार से कर्जदारों को काफी परेशानियां उठानी पड़ीं।

यदि गिरफ्तारी विधि सम्मत नहीं तो न्यायिक हिरासत भी अवैध

विधि संवाददाता, लखनऊ

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि अभियुक्त को गिरफ्तारी विधि सम्मत नहीं है तो मजिस्ट्रेट द्वारा उसे न्यायिक हिरासत पर लेने का आदेश भी वैध नहीं उठराया जा सकता। इन दिव्यणियों के साथ कोर्ट ने पाँक्सो के एक मामले में गिरफ्तार अभियुक्त की न्यायिक हिरासत को अवैध करार देते हुए खारिज कर दिया है तथा अभियुक्त को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन व न्यायमूर्ति बबीता रानी की खंडपीठ ने प्रतापगढ़ निवासी शिवम चौरसिया की ओर से उसके भाई द्वारा दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को मंजूर करते हुए पारित किया है। याचिका में कहा गया था कि याची को दुराचार व पाँक्सो तथा अन्य आरोपों में अभियुक्त बनाते हुए प्रतापगढ़ के कंधई थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। आरोप है कि वादी की 17 वर्षीय पुत्री को बहलफुसला कर याची/अभियुक्त ने शारीरिक संबंध बनाए तथा ब्लैकमेल



● बिना कारण बताए गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

किया। दलील दी गई कि 28 जनवरी 2026 को याची को थाने पर बयान देने के लिए बुलाया गया, वह वहाँ पहुँचा तो उससे अरेस्ट मेमो पर हस्ताक्षर करा लिए गए। गिरफ्तार कर अगले दिन संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से मजिस्ट्रेट ने भी बिना यह देखे कि अरेस्ट मेमो में याची के गिरफ्तारी के किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया है, याची को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया। याचिका का राज्य सरकार के अधिवक्ताओं शिवनाथ तिलहरी व अनुराग वर्मा ने विरोध करते हुए दलील दी कि गिरफ्तारी के बाद यदि मजिस्ट्रेट ने रिमांड स्वीकार कर लिया है तो यदि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कोई त्रुटि रह भी गई है तो वह विलुप्त मान ली जाएगी। हालाँकि कोर्ट इस दलील दे सहमत नहीं हुई।

पंचायत चुनाव से पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा: सरकार

लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित पर जवाब देते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पंचायत चुनाव से पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया जाएगा। साथ ही संबंधित कानून के तहत रिपोर्ट के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। सरकार की ओर से आए उक्त जवाब पर कोर्ट ने संबंधित याचिका को निस्तारित कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति एके चौधरी की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया था कि अक्टूबर 2025 में पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिसे एक वर्ष का कार्यकाल विस्तार भी दिया गया है। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जयश्री लक्ष्मण राव पाटील मामले में समर्पित आयोग का गठन कर, उक्त आयोग के सर्वे व रिपोर्ट के आधार पर ही स्थानीय चुनावों में आरक्षण लागू किए जाने का आदेश दिया था। दलील दी गई कि अप्रैल व जुलाई 2026 के मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं, बावजूद इसके अब तक एक समर्पित आयोग का गठन नहीं किया जा सका है। यह भी दलील दी गई कि 6सदस्यीय आयोग के गठन का मामला कैबिनेट के समक्ष विचारधीन है।

ब्रीफ न्यूज

दूरदर्शन की पूर्व समाचार वाचिका सरला माहेश्वरी का निधन

नई दिल्ली। दूरदर्शन की पूर्व समाचार वाचिका सरला माहेश्वरी का गुरुवार को यहां निधन हो गया। वह 71 वर्ष की थीं। वह 1980 और 1990 के दशक में टीवी समाचार जगत के सबसे जाने-माने चेहरों में से एक थीं और जिनकी शांत शैली आज के टेलीविजन समाचार बुलेटिन के शोरगुल से बिल्कुल अलग थी। माहेश्वरी 1976 से लेकर 2005 तक टीवी समाचारों का जाना-पहचाना चेहरा थीं। उनके साथ सलमा सुल्तान, मीनू तलवार, शम्मी नारायण, गीतांजलि अय्यर, नीति रविंद्रन और अन्य भी थीं। उनका नाम सुनते ही प्रसारण जगत और उसके श्वेत-श्याम से रंगीन प्रसारण में परिवर्तन की याद ताजा हो जाती है।

ब्राजील के राष्ट्रपति 18 को पांच दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे

नई दिल्ली। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिलवा 18 फरवरी को भारत की पांच दिवसीय यात्रा पर आएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लुला की राजकीय यात्रा से दोनों देशों की द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। साथ ही द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने बताया कि मोदी 21 फरवरी को राष्ट्रपति लुला से मिलेंगे और दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे।

असम राइफल्स श्वान दस्ते में भारतीय नस्ल के कुत्तों को करेगा शामिल

जोरहाट। केंद्र सरकार के स्वदेशीकरण के आह्वान को मजबूती प्रदान करते हुए असम राइफल्स अपने अभियानों को अंजाम देने के लिए दस्ते में भारतीय नस्ल के कुत्तों को शामिल करने की योजना बनाई है। कमांडिंग ऑफिसर लीफ्टनैंट कर्नल अलोक ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत 'तंगखुल हर्ड' नस्ल के कुत्तों को श्वान दस्ते में शामिल कर लिया है।

रेरा को समाप्त कर देना चाहिए, यह दागी बिल्डरों के लिए काम कर रहा सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा- जिनके लिए रेरा बनाया वे पूरी तरह से निराश और हताश

● कोर्ट की सख्त टिप्पणी से रियल एस्टेट सेक्टर में मची हलचल

नई दिल्ली, एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सभी राज्यों के लिए रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के गठन पर पुनर्विचार करने का यह सही समय है क्योंकि यह संस्था दागी बिल्डरों को सुविधा प्रदान करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। प्रधान न्यायाधीश सुर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि जिन लोगों के लिए रेरा बनाया गया था, वे पूरी तरह से निराश और हताश हैं। पीठ ने जोर देकर कहा कि अगर इस संस्था को समाप्त कर दिया जाए तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। पीठ ने हिमाचल प्रदेश सरकार को रेरा के कार्यालय को अपनी पसंद के स्थान पर स्थानांतरित करने की अनुमति देते हुए ये टिप्पणियां कीं। हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य द्वारा दायर याचिका पर पीठ ने नोटिस जारी किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जो राज्य के रेरा कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने से संबंधित था।



उच्च न्यायालय ने इससे पहले रेरा कार्यालय के स्थानांतरण से संबंधित जून 2025 की अधिसूचना पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। बाद में, 30 दिसंबर 2025 को अपने आदेश में, उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश को जारी रखने का निर्देश दिया। उच्चतम न्यायालय ने 30 दिसंबर के उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगा दी है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, दागी बिल्डरों को सुविधा देने के अलावा यह संस्था (रेरा) कुछ नहीं कर रही है। बेहतर होगा कि इस संस्था को समाप्त कर दिया जाए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है... अब समय आ गया है कि सभी राज्य इस प्राधिकरण के

किसी को अरावली को छूने की अनुमति नहीं देंगे

नई दिल्ली। शीर्ष कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अरावली की पर्वतमाला की परिभाषा स्पष्ट किए जाने तक हरियाणा सरकार को जंगल सफाई पर विस्तृत योजना प्रस्तुत करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश सुर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि अरावली पहाड़ियों से संबंधित मुख्य मामले पर विचार करते समय 'जू सफाई' के मुद्दे पर भी संज्ञान लिया जाएगा। हरियाणा का पक्ष रखने के लिए पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने सफाई परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को 10,000 एकड़ से संशोधित करके 3,300 एकड़ से अधिक कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे केवल इतना चाहते हैं कि उन्हें डीपीआर को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के समक्ष समीक्षा के लिए प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। पीठ ने कहा, हम विशेषज्ञ नहीं हैं। अरावली की परिभाषा विशेषज्ञ तय करेंगे। सीईआई ने कहा कि अरावली केवल हरियाणा या राजस्थान की ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो कई राज्यों से होकर गुजरती है। उन्होंने हरियाणा सरकार के वकील से कहा, हम जू सफाई के मुद्दे पर मुख्य मामले के साथ ही विचार करेंगे। इस पर हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि मुख्य मामला बिल्कुल अलग है और जंगल सफाई का मुद्दा अलग है। पीठ ने इसपर टिप्पणी की, कभी-कभी, सीईसी अनुमति देने में बहुत बुनियाद रखी अपनता है। अगर हम अनुमति देते हैं, तो वे बहुत ही आकर्षक तस्वीर पेश करेंगे कि ये पेड़, वन्यजीव और जंगल हैं। सीईआई सुर्यकांत ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की राय आने के बाद वह सफाई परियोजना पर विचार करेंगी।

गठन पर ही पुनर्विचार करें। राज्य सरकार ने अधिवक्ता सुगंधा आनंद के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी याचिका में कहा कि हिमाचल प्रदेश रेरा कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने का निर्णय शिमला शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिए लिया गया था, और यह पूरी तरह से प्रशासनिक कारणों पर आधारित था। प्रतिवादी की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि प्राधिकरण जिन परियोजनाओं से संबंधित मामलों को देखता है, उनमें से 90 प्रतिशत शिमला, सोलन, परवानू और सिरमौर में हैं, जो अधिकतम 40 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। उन्होंने कहा कि रेरा के समक्ष लंबित शिकायतों में से लगभग 92 प्रतिशत इन्हीं जिलों से हैं।

बिजली-कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा में तीखी बहस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: विधानसभा में गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बिजली आपूर्ति, कानून व्यवस्था, किसान और बजट के मुद्दों पर सदन का माहौल बार-बार गरमाया। ऊर्जा मंत्री और सपा नेता शिवपाल सिंह यादव के बीच तीखी बहस केंद्र में रही। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत होते ही भाजपा विधायकों ने सरकार की उपलब्धियों का बखाना किया। भाजपा विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में शिक्षा, कानून व्यवस्था और निवेश का माहौल बेहतर हुआ है। उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में सुविधाओं, बेहतर भवनों और निवेशकों के बढ़ते भरसे को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। सदन में सबसे तीखी बहस ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव के बीच हुई। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रोएम सूर्य घर योजना सहित कई केंद्रीय योजनाओं में देश में अग्रणी है और आज प्रदेश में कहीं 24 तो कहीं 21 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब सपा कानून व्यवस्था और बिजली की बात करती है तो हंसी आती है। इस पर शिवपाल सिंह यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल में भी बिजली और सड़क के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम हुआ था।

● ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और सपा नेता शिवपाल यादव आमने-सामने



ऊर्जा मंत्री एके शर्मा एवं सपा विधायक शिवपाल सिंह

किसान, डीजल व अधिग्रहण पर सरकार का जवाब

किसानों की बढ़हली, डीजल की कीमत और जमीन अधिग्रहण को लेकर सपा विधायक अनिल प्रधान ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज, मौसम की मार और आवारा पशुओं से परेशान हैं, वहीं खाद के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। जवाब में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यूपी में डीजल पर वेट देश के कई राज्यों की तुलना में कम है और डीजल की कीमतों परियम बंगाल, केरल और तमिलनाडु सहित करीब 20 राज्यों से कम है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय में डीजल और लागत घटाने के लिए सरकार लगातार योजनाओं पर काम कर रही है। भूमि अधिग्रहण पर उन्होंने कहा कि किसानों से संवाद कर बाजार दर पर मुआवजा दिया जाता है।

देशव्यापी हड़ताल का मिलाजुला असर, बैंकिंग सेवाएं सुचारू रहीं

नई दिल्ली। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मंच की सरकार की नीतियों के खिलाफ गुरुवार को आहूत एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का सामान्य जनजीवन पर खास असर नहीं पड़ा। श्रमिक संगठनों ने कई राज्यों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। कुछ जगहों पर श्रमिक हड़ताल में समर्थन दिखाने के लिए कार्यस्थल पर देर से पहुंचे। उत्तर प्रदेश ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, गोवा सहित कई राज्यों में इसका मिला-जुला असर



देखने को मिला। श्रमिक संगठनों ने दावा किया कि हड़ताल में 30 करोड़ से अधिक श्रमिकों, किसानों और अन्य वर्गों ने भाग लिया। बैंकिंग सेवाएं भी सुचारू रूप से चलती रहीं।

एक्सप्रेस-वे पर टोल दरों में कटौती, 15 से लागू

नई दिल्ली। सरकार ने चालू राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के उपयोगकर्ताओं के लिए टोल शुल्क कम करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों में संशोधन किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार को बयान में कहा कि संशोधित नियम 15 फरवरी से लागू होंगे। मंत्रालय ने कहा, इसके तहत यदि कोई राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे शुरू से अंत तक पूरी तरह चालू नहीं है, तो उसके केवल तैयार हिस्से पर सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुसार कम दर टोल शुल्क लिया जाएगा।

114 राफेल विमानों को खरीदने की मंजूरी

नई दिल्ली, एजेंसी

रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद के काफी समय से लंबित प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएफपी) ने रक्षा बलों की युद्ध तत्परता बढ़ाने के लिए कुल 3.60 लाख करोड़ रुपये के सैन्य उपकरणों के पूंजीगत अधिग्रहण को मंजूरी दी। राफेल विमानों की खरीद को मंजूरी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल

मैक्रों को भारत यात्रा से ठीक चार दिन पहले मिली। इस सौदे को हालांकि अंतिम रूप देने के लिए औपचारिक अनुबंध इस साल के अंत से पहले होने की संभावना नहीं है। अप्रैल 2019 में, भारतीय वायुसेना ने लगभग 18 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से 114 बहु-भूमिका लड़ाकू विमान (एमआरएफए) की खरीद के लिए एक आरएफआई (सूचना के लिए अनुरोध), या प्रारंभिक निविदा जारी की। इस परियोजना के अन्य दावेदारों में लॉकहीड मार्टिन का एफ-21, बोईंग का एफ/ए-18 और यूरोफाइटर टाइफून शामिल थे। भारतीय

तटरक्षक बल को कानपुर एचएएल से मिलेंगे 8 डोनिर्यर 228 विमान

रक्षा मंत्रालय ने एचएएल के साथ 2,312 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस अनुबंध पर यहां एचएएल के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन, कानपुर के साथ हस्ताक्षर किए गए। वायुसेना के लड़ाकू स्व्वाइन की संख्या आधिकारिक तौर पर स्वीकृत 42 की संख्या से घटकर 31 रह गई है।

लोढ़ा डेवलपर्स के पूर्व निदेशक मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लोढ़ा डेवलपर्स के पूर्व निदेशक राजेंद्र लोढ़ा को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने यह कार्रवाई 85 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है। पिछले वर्ष सितंबर में लंबी जांच के बाद लोढ़ा गुप के पूर्व निदेशक व कई अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्रॉपर्टी से संबंधित जांच कर रही थी। इस दौरान राजेंद्र लोढ़ा समेत कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद ईडी ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। ईडी के मुताबिक राजेंद्र लोढ़ा पर कंपनी से जमीन अधिग्रहण के नाम पर करोड़ों रुपये की हेराफेरी का आरोप है। पुलिस ने इस संबंध में करीब चार दर्जन से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किये। इनमें से सात ने मजिस्ट्रेट के सामने भी

● प्रवर्तन निदेशालय ने 85 करोड़ के घोटाले में की कार्रवाई, सितंबर 2025 में दर्ज हुई थी राजेंद्र लोढ़ा समेत कई पर एफआईआर

बयान दर्ज करा दिया है। गवाहों में राजेंद्र लोढ़ा का चालक भी शामिल हैं। उनसे बताया था कि नकदी एक आरोपी को ले जाकर दी थी। इसके अलावा फोटो व बोरीवली में एक करोड़ रुपये जुटाकर राजेंद्र को दिये थे। जांच में सामने आया कि कंपनी ने जमीन को कम दाम पर राजेंद्र लोढ़ा के बेटे की कंपनी को ट्रांसफर किया था। राजेंद्र के लेन-देन का रिकार्ड कंप्यूटर व मोबाइल में मिले हैं। जांच में यह भी सामने आया कि सोसीटीवी फुटेज में राजेंद्र के भाई दीपक लोढ़ा को संदिग्ध बैग घर से बाहर ले जाते देखा गया। बैग से नकद लेनदेन और कंपनी के दस्तावेज थे। ईडी के अधिकारी उनको कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी में है।

एसआईआर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नो-मैपिंग और तार्किक विसंगतियों को लेकर बड़े पैमाने पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि छह जनवरी को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची के आधार पर कुल 3 करोड़ 26 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने हैं। इनमें से अब तक लगभग एक करोड़ 9 लाख मतदाताओं को नोटिस निर्गत किए जा चुके हैं। 10 दिन में आपत्ति देनी होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन सूचियों के दौरान नो-मैपिंग से संबंधित 1 करोड़ 04 लाख और तार्किक विसंगतियों से



संबंधित 2 करोड़ 22 लाख मतदाताओं की पहचान की गई है। इन सभी श्रेणियों में आने वाले मतदाताओं की सूचियां संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को उपलब्ध करा दी गई हैं। साथ ही, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन सूचियों को तहसील, पंचायत भवन, वार्ड कार्यालय सहित अन्य सार्वजनिक

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा- 3.26 करोड़ मतदाताओं को भेजे गए नोटिस

नो-मैपिंग के 1.04 करोड़, विसंगतियों के 2.22 करोड़ मतदाता चिह्नित

● दस दिन में आपत्ति का मौका 1.09 करोड़ को भेजे जा चुके हैं नोटिस

स्थलों पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मतदाता इन सूचियों को ऑनलाइन भी देख सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की वेबसाइट के साथ-साथ जनपदवार, विधानसभा-वार और बूथ-वार जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी ये सूचियां उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि

सिईओ रिणवा ने शहरी क्षेत्रों में कामकाजी दंपतियों की सुविधा को देखते हुए अवकाश के दिनों में भी सुनवाई आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मंडलायुक्त (रोल ऑब्जर्वर), जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को सुनवाई केंद्रों का औचक निरीक्षण कर समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रत्येक सुनवाई केंद्र पर हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए निर्देश

नवदीप रिणवा ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनवाई से संबंधित सभी अभिलेखों और आपत्तियों का सुरक्षित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाए। मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सुनवाई केंद्र पर हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मतदाता सूची, नो-मैपिंग एवं तार्किक विसंगतियों से संबंधित सूचियां, फार्म-6, फार्म-7, फार्म-8 तथा घोषणा-पर पत्र्याण अधिकारियों को कार्यदिवस में पूर्वाह्न 10 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रों पर वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची, 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित आलेख्य

विधानसभा में मंत्रियों के जवाब...

2017 से पहले अपराध था उद्योग : नंदी

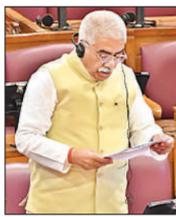


मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी

अमृत विचार, लखनऊ: विधानसभा के बजट सत्र 2026-27 के चौथे दिन औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने सपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में उद्योग की परिभाषा अफहरण, गुंडा टेक्स और अपराध तक सीमित थी, जबकि आज उद्योग की पहचान निवेश, निर्यात और आर्थिक समृद्धि से होती है। विधायकों के तारकित प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री नंदी ने कहा कि 2016-17 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 13.30 लाख करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 30.25 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। इस प्रकार जीएसडीपी में 127 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज हुई है। उन्होंने बताया कि 2018 से अब तक चार ग्राउंड ब्रेकिंग सेमिनारों के माध्यम से 12.10 लाख करोड़ रुपये की लागत से 16,478 औद्योगिक इकाइयों की ग्राउंडिंग हुई, जिनमें से 6,352 इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है।

ओडीओपी से 3.16 लाख को रोजगार : सचान

अमृत विचार, लखनऊ: विधानसभा में प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ओडीओपी) योजना ने प्रदेश के पारंपरिक कारीगरों और उत्पादकों को नई पहचान दी है। उन्होंने बताया कि अब तक 1.31 लाख कारीगरों को नि-शुल्क प्रशिक्षण और टूल किट दी गई है। सहारनपुर में 2275 कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया और 454 लाभार्थियों को 16.26 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी वितरित की गई। मंत्री सचान ने कहा कि वर्ष 2017-18 में प्रदेश का निर्यात 86 हजार करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जिसमें लगभग 50 प्रतिशत योगदान ओडीओपी और हस्तशिल्प उत्पादों का है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 से अब तक ओडीओपी योजना के माध्यम से 3.16 लाख लोगों को रोजगार मिला है और इसकी सफलता को देखते हुए इसे देशभर में लागू किया गया है।



मंत्री राकेश सचान

विधानसभा में गूंजे एआई व किन्नर कल्याण के मुद्दे

बजट सत्र का चौथा दिन : विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बोले, एआई का दुरुपयोग राजनीति के लिए खतरनाक

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को विधानसभा में प्रश्नकाल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। न तो किसी दल ने वॉकआउट किया और न ही कोई सदस्य वेल में आया। कार्यवाही के दौरान किन्नर समुदाय, एआई तकनीक के दुरुपयोग और औद्योगिक निवेश जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

सपा विधायक अतुल प्रधान ने नियम-300 के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एआई एक खतरनाक तकनीक बनती जा रही है और इसके जरिए किसी व्यक्ति की आवाज और चेहरा हूबहू नकल कर गलत संदेश फैलाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने अपने जिले के एसएसपी से शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सपा विधायक के आग्रह पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा- एआई पर लेंगे विधिक राय

इससे पहले सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि इस विषय पर केंद्र सरकार ने 10 फरवरी 2026 को दिशा- निर्देश जारी किए हैं और उन्हीं के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विधिक राय लेने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

किन्नर समुदाय के मुद्दे पर असीम अरुण हुए तल्लख

प्रश्नकाल में सपा विधायक सचिन यादव ने किन्नर (ट्रांसजेंडर) समुदाय से जुड़े मुद्दे को सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि किन्नर समाज के लोगों को शिक्षा, राशन कार्ड, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी समुचित रूप से नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने ट्रांसजेंडर कल्याण आयोग तो बनाया है, लेकिन उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव पुरुष हैं, जिससे इस वर्ग को न्याय मिलना कठिन है।

जवाब देते हुए समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में यह इस तरह का पहला सवाल है। उन्होंने बताया कि थानों में इस समुदाय के लिए अलग सेल बनाई गई है, किन्नर समाज के लोग आज स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं तथा पहचान सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसजेंडर कार्ड बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा के तहत आयुष्मान कार्ड भी उन्हें उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर महोत्सव आयोजित कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।



मंत्री असीम अरुण

मामले का संज्ञान लेने के निर्देश दिए। अध्यक्ष ने कहा कि एआई का दुरुपयोग खासतौर पर राजनीति

में सक्रिय लोगों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

लोकलेखा समिति के तीन प्रतिवेदन विस में पेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

कैग की रिपोर्टों में ऑडिट आपत्तियों के आधार पर किए गए तैयार

अमृत विचार: विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सदन में लोकलेखा समिति (पीएसी) के तीन प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। ये प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्टों में दर्ज ऑडिट आपत्तियों के आधार पर तैयार किए गए हैं। लोकलेखा समिति ने संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली, वित्तीय अनुशासन और सार्वजनिक धन के उपयोग की गहन समीक्षा के बाद अपनी सिफारिशें सदन के पटल पर रखीं।

सदन में प्रस्तुत पहला प्रतिवेदन कैग की उस रिपोर्ट पर आधारित है, जो 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए थी और जिसमें कृषि विभाग से जुड़ी ऑडिट आपत्तियों का उल्लेख है। समिति ने कृषि योजनाओं के क्रियान्वयन, बजट उपयोग और प्रक्रियागत खामियों पर टिप्पणी करते

हुए विभाग से स्पष्ट जवाबदेही तय करने की सिफारिश की है। दूसरा प्रतिवेदन 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष की कैग रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें पंचायती राज विभाग से संबंधित ऑडिट आपत्तियों को शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में ग्राम पंचायतों से लेकर जिला स्तर तक वित्तीय प्रबंधन, कार्यों के निष्पादन और अभिलेखों के रख-रखाव में पाई गई अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया गया है। समिति ने पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता रेखांकित की है। तीसरा प्रतिवेदन 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष की कैग रिपोर्ट पर आधारित है, जो सामान्य (जनरल एवं सोशल सेक्टर) से संबंधित ऑडिट आपत्तियों पर केंद्रित है।

तेल और गरम तासीर वाले पदार्थों का कम सेवन करे विपक्ष, गुस्सा नहीं आएगा : पाठक

विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री ने सपा नेताओं को लिया आड़े हाथ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक विधान परिषद में गुरुवार को प्रश्नकाल में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर सपा सदस्यों को जवाब दे रहे थे। उन्होंने नेता विरोधी दल समेत अन्य सदस्यों को तेल और गरम तासीर वाली पदार्थों का कम सेवन की सलाह देते हुए कहा कि इससे गुस्सा जल्दी आता है और शरीर बीमार होता है।

ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रकृति द्वारा शरीर को अनुमत्य भोज्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए, शारीरिक श्रम जबरन करना चाहिए। कोई काम न हो तो खुद को घर के काम में व्यस्त रखकर स्वस्थ रहें। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गंभीर रोगों से प्रसित रोगियों के लिए लगातार काम कर



सदन में बोलते उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक।

रही है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की सुविधा है। हमारे पास गोरखपुर और रायबरेली में दो एम्स हैं, जो रोगियों का गुणवत्तापूर्ण इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानक विहीन चिकित्सालयों के विरुद्ध विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती रहती है। वर्तमान में प्रदेश में 16520 चिकित्सक तैनात हैं। नए चिकित्सकों की तैनाती भी की जा रही है।

ब्राह्मणों के सम्मान को लेकर उठाए सवाल

अमृत विचार : विधान परिषद में सपा सदस्यों ने पीडीए के साथ ही ब्राह्मण कार्ड भी खेला, प्रश्नकाल में सपा के मुकुल यादव ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को स्नान करने से रोके जाने का मुद्दा उठाया, उन्होंने रामचरित मानस की चौपाई का वाचन करते हुए कहा कि शिक्षा काटना ही ब्राह्मण की मृत्यु समान होता है। प्रदेश में आराजकता का माहौल है, इस पर सत्तापक्ष कहा कि 2015 में सपा सरकार ने उन पर लाठीचार्ज करवाया था।

इलाज डॉक्टरों से मिलता है इमारत से नहीं : विधान परिषद में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सपा सदस्य आशुतोष सिन्हा पर जमकर बरसे। सपा सरकार के कामकाज को कुकर्म बताते हुए गाय-पड़वा की एक देशी कहानी सुनाकर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि सपा ने मेट्रो ही नहीं, अस्पतालों की इमारतें बनवाईं, मगर डॉक्टर की व्यवस्था नहीं की, उनका चलाने का कोई इरादा नहीं था, सिर्फ ठेकेदारी व लूट का खेल खेला गया।

उप मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में सपा के आशुतोष सिन्हा के कन्नौज मेडिकल कॉलेज में हृदय और कैन्सर हास्पिटल में पद व उपलब्ध इलाज के मुद्दे पर जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा कि सिर्फ बिल्डिंग से अस्पताल नहीं चलता। बिल्डिंग बनाकर छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि अभी सहायक शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है, चार साल की सेवाएं देने के बाद ये प्रमोशन के बाद अस्पिस्ट प्रोफेसर और प्रोफेसर बन जाएंगे, शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी।

पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रहेगा: कश्यप



मंत्री नरेंद्र कश्यप

अमृत विचार, लखनऊ: पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विधानसभा में कहा कि योगी सरकार में पिछड़े वर्ग के एक भी पात्र छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा 2 लाख रुपये है, जिसे सरकार निरंतर लागू रखे हुए है। वर्ष 2023-24 से अब तक एक भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित नहीं रहा है। मंत्री कश्यप ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में विभाग का बजट 1286 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर लगभग 3500 करोड़ रुपये हो गया है।

यह लगभग तीन गुना वृद्धि है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 38 लाख छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य रखा गया है और छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार केवल घोषणाओं में नहीं, बल्कि धरातल पर काम करने में विश्वास रखती है।

विवि संशोधन विधेयक पुरस्थापित : उपाध्याय

अमृत विचार, लखनऊ: उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2026 और द्वितीय संशोधन विधेयक 2026 को पुरस्थापित किया। सदन ने बहुमत से दोनों विधेयकों को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इन संशोधन विधेयकों के माध्यम से विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक और शैक्षणिक ढांचे को और सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे शैक्षणिक अनुशासन, जवाबदेही और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा।



उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय

एएम ग्रुप और इन्वेस्ट यूपी के बीच एमओयू 289 एकड़ में कार्बन-फ्री डेटा सेंटर, 2030 तक एक गीगावाट क्षमता से संचालन का लक्ष्य

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप प्रदेश को देश का अग्रणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल हुई है। राज्य सरकार की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी इन्वेस्ट यूपी और एएम ग्रुप के बीच एक गीगावाट हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूट (एचपीसी) एवं एआई हब की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

गुरुवार को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने एएम ग्रुप के प्रतिनिधियों को लेंटर ऑफ इंटर (एलओआई) सौंपा।



एमओयू के प्रतिनिधियों को लेंटर ऑफ इंटर सौंपते यीडा के सीईओ।

यीडा द्वारा सेक्टर-28 में 114 एकड़ और सेक्टर-8डी में 175 एकड़, कुल 289 एकड़ भूमि के लिए एलओआई जारी किया गया है। इस भूमि पर अत्याधुनिक, वैश्विक मानकों वाला एआई एवं हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग हब विकसित किया जाएगा। परियोजना यीडा

क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से स्थापित की जाएगी, जिसमें लगभग 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का प्रस्ताव है। परियोजना के तहत लगभग पांच लाख हाई-परफॉर्मेंस चिपसेट्स से युक्त डेटा सेंटर विकसित किया जाएगा, जो 24x7 कार्बन-फ्री ऊर्जा

पर आधारित होगा। इसके लिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पम्पड स्टोरेज जैसी स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा। पहले चरण का संचालन वर्ष 2028 तक शुरू करने का लक्ष्य है, जबकि वर्ष 2030 तक पूर्ण 1 गीगावाट क्षमता प्राप्त करने की योजना है।

नए बिजली कनेक्शन पर वसूले गए 6016 रुपये समायोजित हों

अमृत विचार, लखनऊ : उप. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नए बिजली कनेक्शनों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर की गई 6016 प्रति उपभोक्ता की अतिरिक्त वसूली के समायोजन और अधिकसित कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन संबंधी नियमों में संशोधन की मांग उठाई है। यह प्रस्ताव परिषद के अध्यक्ष एवं सलाह को रिव्यू पैनल सच कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने विद्युत नि्यामक आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात कर दिया है। परिषद के अध्यक्ष ने गुरुवार को बताया कि 31 दिसंबर से प्रदेश में नई कॉन्स्ट्रक्टा बुक लागू की गई है, लेकिन उससे पूर्व बिना आयोग की अनुमति के स्मार्ट प्रीपेड मीटर के नाम पर प्रति उपभोक्ता 6016 की वसूली की गई।

पायलट प्रोजेक्ट

अमृत विचार : नियोजन विभाग की तरफ से चल रहा अभियान 'एक परिवार एक पहचान' के तहत फैमिली आईडी बनवाने वाले बुजुर्ग लाभार्थियों को वृद्धा पेंशन के लिए न कोई आवेदन करना होगा, न ही कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बल्कि उनकी फैमिली आईडी से उप्र और आय के आधार पर ऑटोमेटिक वृद्धा पेंशन का फार्म भर जाएगा। सिर्फ लाभार्थी की सहमति लेकर उसकी बायोमेट्रिक करारक पेंशन स्वीकृत कर दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग ये नई

लाभार्थियों को नहीं भरना होगा फार्म, पोर्टल कर लेगा ट्रेस

पोर्टल आय और उम्र से करेगा ट्रेस व बायोमेट्रिक
अब आय समेत अन्य प्रमाण पत्र आधार प्रमाणिक बनते हैं। इस आधार पर नया पोर्टल फैमिली आईडी के पेंशन से वंचित लाभार्थियों की उम्र और आय ट्रेस करके उनका ऑटोमेटिक फार्म भरेगा। इसके बाद लाभार्थी की सहमति लेकर उसका बायोमेट्रिक करवा जाएगा। इससे पात्रता संबंधित पूरी जांच भी हो जाएगी। इस योजना का मकसद जरूरतमंदों का बिना दौड़भाग के ऑटोमेटिक पेंशन का फार्म भरकर लाभान्वित करना है।

कल्याण विभाग और साथ फैमिली आईडी का विवरण लिंक होगा। यदि फैमिली आईडी में 60 वर्ष से ऊपर का कोई लाभार्थी पेंशन योजना से वंचित होगा तो उसका विवरण समाज कल्याण विभाग से ट्रेस होकर ऑटोमेटिक फार्म भर जाएगा। इसके अलावा जो पहले से पेंशन पा रहे या अपात्र हैं, उन्हें लाभ

पर्यटन विकास पारदर्शिता के साथ

होगा: जयवीर

अमृत विचार, लखनऊ : विधानसभा के बजट सत्र 2026-27 के चौथे दिन विधान परिषद में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने प्रदेश में पर्यटन विकास को लेकर सरकार की नीति और प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का तथ्यात्मक उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों का विकास निर्धारित गाइडलाइन, बजट की उपलब्धता और निर्विवाद, निःशुल्क भूमि की शर्तों के आधार पर ही किया जाता है। मंत्री ने ललितपुर, सीतापुर, झांसी और मिर्जापुर के धार्मिक एवं आस्था केंद्रों के संबंध में बताया कि बुनियादी पर्यटक सुविधाएं जैसे शौचालय, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और साइनेज ही पर्यटन विभाग के दायरे में आती हैं, जबकि जीर्णोद्धार एवं संरचनात्मक कार्य वर्तमान गाइडलाइन्स में अनुमत्य नहीं हैं।

भाजपा सरकार ने देश का बाजार विदेशियों को सौंप दिया: अखिलेश

अमृत विचार, लखनऊ : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि ये 'डील' वो 'डाल' है, जिसको उस पर बैठने वाला ही काट रहा है। ये डील हमारे देश की सिर्फ खेती-मजदूरी ही नहीं, बल्कि हर तरह के पैदावार-उत्पादन, काम-कारोबार और रोजगार के खिलाफ है। अब भाजपा के वो सगी-साथी कहां भूमिगत हो गये हैं, जो स्वदेशी का नारा लगाते थे। आत्मनिर्भरता की जगह भाजपाइयों को 'परनिर्भरता' का नारा अपना लेना चाहिए। सपा प्रमुख ने गुरुवार को कहा कि भाजपा सरकार ने देश का बाजार विदेशियों को सौंप दिया है। इससे खेती किसानों और किसानों का बड़े पैमाने पर नुकसान होगा।

ब्रह्मोस के संग 'हार्ड पावर' विजन का संदेश



अमृत विचार, लखनऊ : प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने वाली सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 'नए यूपी' की बढ़ती ताकत का संकेत दिया। बजट 2026-27 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कवर इमेज बदल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस संग अपनी

छूटे तीन करोड़ बच्चों को आज खिलाई जाएगी दवा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ
● मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बदली कवर इमेज

फोटो लगाकर 'हार्ड पावर' विजन का संदेश दिया। सोशल मीडिया हैंडल पर मुख्यमंत्री का यह संदेश बताया है कि लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण के जरिए उत्तर प्रदेश एक तरफ रक्षा उत्पादन का उभरता वैश्विक हब हो गया है।

श्रृंगवेरपुर को मिलेगा अयोध्या जैसा वैभव

अमृत विचार, लखनऊ : रामनगरी अयोध्या की तर्ज पर निपादराज की राजधानी श्रृंगवेरपुर को भव्य और आकर्षक रूप दिया जा रहा है। प्रयागराज जिले के इस ऐतिहासिक व पौराणिक स्थल पर निपादराज गुह्य सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण तेज गति से जारी है। उप. संस्कृति विभाग की इस परियोजना की लागत 19.61 करोड़ रुपये है और लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस परियोजना में लगभग 400 लोगों की क्षमता वाला आधुनिक ऑडिटोरियम भी है, जहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऑडिटोरियम में स्टेप स्लैब का काम प्रगति पर है और ब्रिकवर्क पूरा हो चुका है। साथ ही पूरे परिसर में आर्किटेक्चरल व स्ट्रक्चरल कार्य, विद्युत और आंतरिक जल आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है।





मिलते-जुलते नामों, डिज़ाइन व कलर स्कीम से भ्रमित न हों केवल असली होलोग्राम युक्त एम.के. बन्धानी हींग ही खरीदें

पॉप पीढ़ी की विश्वस्तरीय हींग परंपरा पुष्पलोक गोलोकवासी बाबू किशोर चन्द कपूर 'किशोर जी' के आशीर्वाद से अभिसिंचित एम.के. संचालित

एम.के. बन्धानी हींग

श्री के.एम. डिस्ट्रीब्यूटर

50 सालदार गुणवत्ता की गारंटी

विक्रय केंद्र : नारायण प्लाजा, 51/71 नवागंज कानपुर 208001, फोन - 9519456555 9695416555

1,60,152 परिवारों को मिली रोजगार की 'गारंटी'

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

41.36 फीसद महिला श्रमिकों की रही भागीदारी वित्तीय वर्ष में | **21.92** लाख मानव दिवस हुए सृजित प्रदेश में 11 फरवरी तक | **370** परिवार को लखनऊ में गारंटी के 100 दिन काम मिला है

अमृत विचार : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने गांवों में श्रमिकों को रोजगार देकर उनका शहर की तरह पलायन रोकने का प्रयास किया है। वित्तीय वर्ष में अब तक 1,60,152 परिवारों को गारंटी के 100 दिन काम मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। विभागीय आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 11 फरवरी तक 21 करोड़ 92 लाख 17 हजार मानव दिवस सृजित हुए हैं। इनमें 51.82 लाख परिवार ने काम किया है। जबकि 1,60,152 परिवार को लगातार 100 दिन काम मिला है। इसमें महिलाओं की 41.31 फीसद भागीदारी है। अभी फरवरी और मार्च तक रोजगार का आंकड़ा और बढ़ेगा। पिछले वर्ष 2024-25 में मार्च तक सृजित 33 करोड़ 63 लाख 89 हजार मानव दिवस में 65.26 लाख परिवारों ने काम किया था। उस समय महिलाओं की 41.87 फीसद रही। 100 दिन गारंटी के 65.26 लाख परिवार ने काम किया था।



यू बर्दी महिला श्रमिक

2021	22	30.96
2022	23	31.75
2023	24	42.46



इसमें पहले से अधिक बजट और 125 दिन काम के साथ कई प्राविधान किए गए हैं।

विकास को रफ्तार देगा इंफ्रास्ट्रक्चर, योजनाओं को लगे पंख

अमृत विचार, लखनऊ: विकास प्राधिकरणों को अवसरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिला 800 करोड़ रुपये बजट शहर के विकास को रफ्तार देगा। बेहतर रोड व पुल की कनेक्टिविटी से यातायात सुगम होगा तो कई नये प्रोजेक्ट धरातल पर उतारे जाएंगे। इससे नई व पुरानी आवासीय योजनाओं में पंख लगेगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण वर्ष 2026-27 में मास्टर प्लान रोड, प्लाईओवर, ओवरब्रिज, ग्रीन कॉरिडोर, पार्क व संचार जैसी सुविधाएं धरातल पर उतारने की योजना बना रहा है। इससे एक तरफ यातायात सुगम होगा और समय की बचत होगी। रोड कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। नई व पुरानी योजनाओं तक आनाजाना आसन और आसन हो जाएगा। इन कार्यों में बजट आवंटित होते ही किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। नये वित्तीय वर्ष में एलडीए कई नई टाउनशिप भी लागू। इसके अलावा बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाने का भी खाका तैयार किया है। योजनाओं की बुकिंग भी शुरू हो गई है। गरीब व मध्यम वर्ग के लिए कई आवासीय व भूखंड की योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। अवसरचना के इन योजनाओं को पंख लगेगे।



इससे एक तरफ यातायात सुगम होगा और समय की बचत होगी। रोड कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। नई व पुरानी योजनाओं तक आनाजाना आसन और आसन हो जाएगा। इन कार्यों में बजट आवंटित होते ही किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। नये वित्तीय वर्ष में एलडीए कई नई टाउनशिप भी लागू। इसके अलावा बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाने का भी खाका तैयार किया है। योजनाओं की बुकिंग भी शुरू हो गई है। गरीब व मध्यम वर्ग के लिए कई आवासीय व भूखंड की योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। अवसरचना के इन योजनाओं को पंख लगेगे।

न्यूज ब्रीफ

मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सपने सौंपा जापन

अमृत विचार, लखनऊ: सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जापन देकर मांग की है कि जिलों में भाजपा के लोग फार्म-7 के जरिए जिलाधिकारी पर दबाव बनाकर सपा समर्थकों में पीडीए व मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटवा रहे हैं। जापन में मांग की है कि सभी फार्म-7 तत्काल निरस्त किये जायें और मिथ्या (फाल्स) के आधार पर आवेदक के रूप में हस्ताक्षर करने वालों तथा बल्क में फार्म-7 जमा करने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए, जिससे एफआईआर प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष सम्पन्न हो सके। कन्नौज, इटावा, बस्ती, प्रयागराज, मेरठ, मिर्जापुर, आगरा, गोरखपुर, देवरिया, बुलंदशहर आदि अधिकांश जिलों के मामले में साक्ष्य दिए हैं।

चौधरी अजित सिंह की जयंती मनाई

अमृत विचार, लखनऊ: राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह की 87वीं जयंती 'सेवा सद्भावना दिवस' के रूप में मनाई गई। प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे, राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष वसीम हेदर व आदित्य विक्रम सिंह, प्रदेश महासचिव रमावती तिवारी सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। संचालन रोहित अग्रवाल ने किया। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि चौधरी अजित सिंह का जीवन किसानों, मजदूरों और कमजोर वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित रहा।

डिपो निर्माण से परियोजना को गति मिलेगी

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

डिपो में अत्याधुनिक तकनीक और पर्यावरण संरक्षण

वसंत कुंज डिपो ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पर चलने वाली ट्रेनों के रखरखाव, जांच और पार्किंग का मुख्य केंद्र होगा। इसे ट्रांसपोर्ट नगर डिपो की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। डिपो में फिट व्हील लेथ मशीन, फुली ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइज्ड पिट, मोबाइल जैक मशीन और बोगी टर्न टेबल जैसे अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। इसके साथ ही डिपो में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। यहां सोलर पैनल, इयूल लैंडिंग सिस्टम, सीवेज और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी-ईटीपी) लगाए जाएंगे।

परियोजना की लागत और समयसीमा

ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर परियोजना की कुल अनुमानित लागत 5801.05 करोड़ रुपये है। यह चारबाग से वसंत कुंज तक 12 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 7 भूमिगत और 5 एलिवेटेड स्टेशन प्रस्तावित हैं। निर्माण कार्य शुरू होने के बाद इससे पांच वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपीएमआरसी के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने कहा कि डिपो का दूसरा टेंडर जारी नहीं होने से परियोजना क्रियान्वयन की दिशा में मजबूती आई है।

कैंसर संस्थान में गरीब मरीजों का इलाज फंसा, बजट खत्म होने की नौबत

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ



अमृत विचार : चक्र गंजरिया स्थित कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में गरीब मरीजों का इलाज फंसा गया है। असाध्य योजना के तहत गरीब मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। बजट खत्म होने से यह नौबत आई है। संस्थान प्रशासन ने उच्च अधिकारियों को कई पत्र लिखे। लेकिन एक माह बाद भी अब तक बजट संस्थान को नहीं मिला है। इसका खामियाजा गरीब कैंसर मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। कैंसर संस्थान की ओपीडी में प्रतिदिन 500 से अधिक मरीज आ रहे हैं। लगभग 300 बेड हैं। ज्यादातर बेड भरे रहते हैं। प्रदेश भर से कैंसर पीड़ित संस्थान में इलाज के लिए आ रहे हैं। संस्थान में गरीब मरीजों के लिए कई तरह की सरकारी योजनाओं का संचालन हो रहा है। इसमें पंडित दीन दयाल उपाध्याय, आयुष्मान, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री राहत कोष व असाध्य योजना शामिल है। सितंबर 2022

मुफ्त इलाज के लिए गरीब मरीज भटक रहे

बीते करीब एक माह से संस्थान में असाध्य योजना का बजट खत्म हो गया है। इससे संस्थान में हाहाकार मच गया है। कई कैंसर मरीजों का इलाज प्रभावित हो गया है। मरीज संस्थान में मुफ्त इलाज की खातिर चक्कर लगा रहे हैं। अधिकारियों से फारियाद कर रहे हैं। उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। कई मरीजों का इलाज प्रभावित है। किसी के रीडियोथेरेपी रुकी है तो किसी मरीज की कीमती थैरेपी की डोज नहीं लग पा रही है। वहीं कई मरीजों की महंगी पेट स्कैन व सीटी स्कैन जैसी जांच नहीं करा पा रहे हैं।

पांच करोड़ का भेजा प्रस्ताव

संस्थान के अधिकारियों का कहना है कि पांच करोड़ रुपये का प्रस्ताव उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। कई रिमांडर भी भेजे जा चुके हैं। लेकिन उच्च अधिकारियों ने अभी तक बजट संस्थान नहीं भेजा है। उच्च अधिकारियों की सुस्ती का खामियाजा बेबस मरीजों को भुगतना पड़ रहा है।

से कैंसर संस्थान में योजना शुरू हुई। योजना में अब तक 130 मरीज पंजीकृत हैं। 2024-25 में शासन ने असाध्य योजना के मरीजों के लिए एक करोड़ का बजट भेजा था। बजट खत्म हो गया। जरूरी कागजी कार्रवाई शासन में कर दी गई है।

त्योहारों पर अराजकता बर्दाश्त नहीं : योगी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

रंग में भंग डालने वालों से सख्ती से निपटने का दिया निर्देश



यात्रियों की सुरक्षा: योगी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रमुख शिवधामों वाराणसी, मेरठ, लखीमपुर खीरी और बाराबंकी में दर्शन-पूजन की तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमें 24x7 सक्रिय रहें। महिला सुरक्षा के लिए पर्याप्त महिला पुलिस बल तैनात हो। यातायात और पार्किंग की सुचारु व्यवस्था हो।

ध्वनि नियंत्रण और नई परंपराओं पर रोक: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि धर्मस्थलों पर ध्वनि-विस्तारक यंत्रों की आवाज परिसर से बाहर न जाए। रात्रि 10

परीक्षाएं, रमजान और जनगणना पर सतर्कता

मुख्यमंत्री योगी ने 18 फरवरी से शुरू हो रही माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन कराने के निर्देश दिए गए। परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। रमजान माह और संभावित 21 मार्च को ईद पर्व के मद्देनजर धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित कर शांति और सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया गया। साथ ही आगामी जनगणना के प्रथम चरण की तैयारियों समग्र से पूरी करने के निर्देश दिए गए।

बजे के बाद डीजे और तेज ध्वनि उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में कोई नई परंपरा प्रारंभ न की जाए। धर्मस्थलों के आसपास बढ़ती भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने और संबंधित व्यक्तियों के पुनर्वास की योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए।

सेमीकंडक्टर परियोजना की मुख्यमंत्री ने की समीक्षा

अमृत विचार, लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (योजा) क्षेत्र में फॉक्सकॉन द्वारा प्रस्तावित प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर पार्क के विकास कार्यक्रम की समीक्षा की। करीब 48 एकड़ पर लम्बाया चार हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस सेमीकंडक्टर पार्क को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना को आधुनिक तकनीक और वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित किया जाए। साथ ही इसके क्रियान्वयन में सभी आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि राज्य में निवेश आकर्षित हो और रोजगार के अवसर बढ़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना से स्थानीय लोगों को अधिकतम लाभ मिले, इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। बताया गया कि सेमीकंडक्टर पार्क के निर्माण से लगभग तीन हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

जागरूकता

अमृत विचार: धारदार/प्रतिबंधित मांझे के उपयोग से हो रही दुर्घटनाओं एवं जनहानि की संभावनाओं को रोकने के लिए गुरुवार को मांझा बेचने वाले और पतंग उड़ाने वाले लोगों के साथ एक बैठक चौक कोतवाली में की गई। डीसीपी पश्चिम

विश्वजीत श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस बैठक में लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र, चौक क्षेत्र के पार्षद अनुपम मिश्रा, पतंग एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, विभिन्न सामाजिक एवं क्लब संगठनों के प्रतिनिधियों और क्षेत्रीय पतंग प्रेमियों ने भाग लिया। बैठक में सीओ चौक, सीओ

चौक कोतवाली में हुई बैठक में पतंगबाज और विक्रेताओं ने ली शपथ

धारदार-प्रतिबंधित मांझे के प्रयोग और बिंदी पर पुलिस और लखनऊ व्यापार मंडल ने जताई चिंता, किया लोगों को जागरूक

बाजारखाली की मौजूदगी रही। बैठक में धारदार एवं प्रतिबंधित मांझे के उपयोग से हो रही दुर्घटनाओं एवं जनहानि की संभावनाओं पर चिंता जताते हुए पतंग उड़ाने वाले लोगों, संस्थाओं और पतंग विक्रेताओं को सामूहिक रूप से शपथ दिलाई गई कि वह आज से किसी भी प्रकार के धारदार अथवा प्रतिबंधित मांझे का प्रयोग नहीं करेंगे और न ही उसकी विक्री करेंगे। सभी पतंग प्रेमियों ने अपनी स्वेच्छा से अपने पास उपलब्ध ऐसे मांझे को पुलिस प्रशासन के



डीसीपी पश्चिम की अध्यक्षता में चौक कोतवाली लखनऊ परिसर में जनसुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक। समक्ष जमा कराया। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) ने अपने संबोधन में कहा कि धारदार एवं प्रतिबंधित मांझे का प्रयोग विधि विरुद्ध होने के साथ-साथ जनसुरक्षा के लिए अत्यंत घातक है। इसके कारण पूर्व में अनेक दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिनमें आम नागरिकों, दोपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को गंभीर क्षति पहुंची है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि शासन एवं प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित मांझे के क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसे मांझे का उपयोग अथवा भंडारण किए जाने पर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। लखनऊ व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने कहा जनसुरक्षा सर्वोपरि है। पार्षद अनुपम मिश्र ने नागरिकों से अपील की कि वे जागरूकता का संदेश व्यापक स्तर पर प्रसारित करें तथा सुरक्षित एवं साधारण धागे ही उपयोग करें।

न्यूज़ ब्रीफ

चोरी करने वाले दो किशोर समेत चार धरे गए

अमृत विचार, लखनऊ: जिला गन्ना अधिकारी बाराबंकी समेत दो के निर्माणधीन मकान में चोरी करने वाले दो चोरों को गोमतीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिराहों में शामिल दो किशोरों को भी पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से छह बंदल तार बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों में शुभम कनौजिया उर्फ मोंटू निवासी रायबरेली हालपता सरस्वती अपार्टमेंट गोमतीनगर विस्तार और राकेश निषाद उर्फ सूर्य निवासी छत्तीसगढ़ हालपता ग्यारी गोमतीनगर हैं।

दहेज हत्या में पति गिरफ्तार

अमृत विचार, लखनऊ: दहेज में स्कॉर्पियों व दो लाख रुपये की मांग से परेशान होकर ललिता ने खुदकुशी की थी। मोहनलालगंज पुलिस ने आरोपी पति राममिलन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भद्रेसुवा में रहने वाले राम मिलन की पत्नी ललिता का शव कमरे में साड़ी के सहारे छत के कुंडे से लटकता हुआ मिला था। मृतका के भाई मनोज कुमार ने दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराया थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैमिग की पुष्टि हुई थी।

किसानों की आय बढ़ाने पर जोर: मौर्य

अमृत विचार, लखनऊ: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र किसानों, उद्यमियों और युवाओं की आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत दी जा रही सुविधाओं और अनुदानों की व्यापक जानकारी देकर अधिक से अधिक उद्यम स्थापित कराए जाएं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में इस सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

बैंक ऑफ बड़ौदा का शटर गिरा खाताधारक बैठे धरने पर

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: जाली एफडी मामले में पारा स्थित शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय परिसर में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में गुरुवार सुबह ग्यारह बजे खाताधारकों ने बैंक बंद कर धरना शुरू कर दिया। अपनी मेहनत की कमाई को लेकर चिंतित ग्राहक शाखा के सामने बैठ गए। रकम वापस दिलाने की मांग पर अड़ गए। आरोप है कि खातों से जुड़े लेनदेन में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और इस पूरे प्रकरण में बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों की संलिप्तता की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

पृथक आबकारी निर्यात नीति लागू

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: राज्य सरकार ने उद्योग, कृषि और निर्यात को नई गति देने के उद्देश्य से पहली बार पृथक आबकारी निर्यात नीति लागू की है। यह नीति तीन वित्तीय वर्षों के लिए तैयार की गई है और इसके माध्यम से एथनॉल व पेय मदिरा के निर्यात को प्रोत्साहन देने के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह जानकारी आबकारी मंत्री नीतिन अग्रवाल ने गुरुवार को दी। उन्होंने बताया कि नीति के प्रमुख उद्देश्यों में स्थानीय कृषि से जुड़े अनाज एवं फल आधारित एथनॉल और अन्य उत्पादों के उत्पादन

महिला अधिवक्ता पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास

अमृत विचार, लखनऊ: जानकीपुरम विस्तार में घर के सामने खड़ी पिकअप हटाने को लेकर महिला अधिवक्ता का चालक से विवाद हो गया। अधिवक्ता ने चालक पर अभद्रता करने और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जानकीपुरम विस्तार निवासी अधिवक्ता मधुलिका यादव ने बताया कि वह बुधवार शाम करीब 5-30 बजे अपने जूनियर अधिवक्ता संग घर लौटी थीं। उनके घर के गेट के सामने सोलर ऊर्जा का सामान लदी एक सफेद रंग की पिकअप खड़ी थी। जूनियर ने चालक से गाड़ी हटाने को कहा तो उसने इंकार कर दिया। आरोप है कि जब अधिवक्ता खुद गाड़ी हटवाने पहुंची तो चालक ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस पिकअप चालक रमेश पांडेय को थाने ले आई। जांच की जा रही है।

पारा पुलिस ने मौके पर स्थिति संभालने का प्रयास किया और प्रदर्शनकारियों को शांत कराने की कोशिश की। लेकिन, खाताधारक अपनी मांगों पर डटे रहे। एहतियात के तौर पर परिसर में पुलिस बल

तैनात कर दिया गया है। दिनभर चली नोकझोंक के बाद मुख्य शाखा से महिला कर्मचारियों ने पहुंचकर आशवासन दिया कि शुक्रवार को सभी वरिष्ठ अधिकारी बैंक पहुंचकर उनकी समस्या का समाधान करेंगे।

सड़क हादसों में वृद्ध सहित तीन लोगों की मौत

कार्यालय संवाददाता, उन्नाव

अमृत विचार। अलग-अलग क्षेत्रों में तेज रफ्तार वाहनों की टक्कर से तीन व्यक्तिओं की मौत हो गई। वहीं अन्य सड़क हादसों में कावड़ियों सहित अन्य लोग गंभीर घायल हो गए हैं। संबंधित क्षेत्रों की पुलिस ने जांच कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा है। पुरवा कोतवाली क्षेत्र के तुसरौर गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद (70) पुत्र रामेश्वर मिश्रा गुरुवार सुबह करीब पांच बजे शीघ्र क्रिया के लिए सड़क पार कर रहे थे। तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। खेत में पानी लगा रहे गांव के युवक मुकेश ने बताया कि हादसे के बाद जब कोई पहुंचता

लोडर की टक्कर से रायबरेली के युवक की मौत

उन्नाव, अमृत विचार। रायबरेली के रसुआपुर दुबाई गांव के मजरा टाकुरपुर सविन मिश्रा (32) पुत्र विनोद कुमार बुधवार को बिहार कस्बा में एक शादी में शामिल होने आया था। जहां से देर रात लौटने समय बिहार थानाक्षेत्र के उन्नाव-लालगंज हाइवे पर आकमपुर के पास लोडर ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। इसमें वह गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने उसे पीएचसी सुमेरपुर पहुंचाया। जहां डॉक्टर सुनील कुमार ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंचे मां साधना बेहाल हो गई। सविन तीन भाई व तीन बहनों में बड़ा था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। भाई की मौत की खबर मिलते वध घर के निकले हैं। एसओ राहुल सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर अगे की कार्रवाई की जाएगी।



तभी पीछे से आया अज्ञात वाहन ने शव को रौंदते हुए करीब 2 किमी आगे बिल्लेश्वर मंदिर तक घसीटता ले गया। इससे शव

क्षत-विक्षत हो गया। हादसे की खबर मिलते पत्नी बितना, बेटे रामकिशोर, श्याम किशोर बेहाल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुरवा कोतवाली प्रभारी अमरनाथ यादव ने बताया कि बेटे की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।



समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारी।

क्षेत्रीय प्रबंधक ने की यातायात अधिकारियों की समीक्षा बैठक

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में क्षेत्र में तैनात यातायात निरीक्षकों व सहायक यातायात निरीक्षकों की समीक्षा

बैठक आयोजित की गई। बैठक में बसों की सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। मार्गों पर ब्रेथ एनालाइजर से चालकों व परिचालकों का एल्कोहल परीक्षण अनिवार्य रूप से करने को कहा

वाहन की टक्कर से

बाइक सवार 3 घायल

ओरास, उन्नाव। ओरास थाना क्षेत्र में गुरुवार को अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार तीन लोग घायल हो गए। घायलों में एक वृद्ध की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। मुसलावा गांव निवासी राज (17) पुत्र ब्रजकिशोर, रामजीवन (65) पुत्र बदी तथा कासिमपुर थाना क्षेत्र के रामपुर भटौली निवासी आशीष (22) पुत्र दीपू एक ही बाइक से भटौली गांव जा रहे थे। ओरास-कबरोई मार्ग पर धानमऊ गांव के पास पहुंचते ही किसी वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। रामजीवन को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है।

अनियंत्रित लोडर पेड़ से टकराया

5 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल

बांगरमऊ, अमृत विचार। बेहटामुजावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत संडीला मार्ग पर बुधवार देर रात लोडर चालक को अचानक झपकी आने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में खड़े पेड़ से जा टकराया। हादसे में लोडर पर सवार पांच कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

कनौज के थाना गुरुसहायगंज क्षेत्र से करीब डेढ़ दर्जन कांवड़ियों का एक जत्था बाराबंकी स्थित बाबा लोधेश्वर महादेव धाम जल चढ़ाने गया था। बुधवार देर रात सभी कांवड़िए लोडर में सवार होकर वापस अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही उनका वाहन बांगरमऊ-संडीला मार्ग पर

स्थित माखन खेड़ा गांव के पास पहुंचा, चालक को नींद की झपकी आ गई और तेज रफ्तार लोडर सीधे पेड़ से जा भिड़ा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लोडर के परखच्चे उड़ गए और चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों में कोशल (31), उषेंद्र (30), कल्लू (38) निवासी हजरतपुर, कनौज, नीतीश (25) निवासी खुदलापुर, कनौज, मनोज (चालक) निवासी सादुल्लापुर, बाराबंकी शामिल हैं। सभी घायलों को बांगरमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। डॉक्टरों ने घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दे दी है।

सोशल मीडिया पर गांजा बेचने

का वीडियो वायरल, जांच शुरू

शुक्लागंज (उन्नाव), अमृत विचार। गुरुवार को सोशल मीडिया पर गांजा बेचने का एक वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। करीब 44 सेकेंड के इस वीडियो में एक युवक झोले में कथित रूप से गांजा रखे दिखाई दे रहा है। इसी दौरान तीन अन्य युवक वहां पहुंचते हैं और विरोध करते हुए उसका वीडियो बनाने लगते हैं। वीडियो में युवक कहते सुनाई दे रहे हैं कि खुलेआम गांजा बेचा जा रहा है। वे झोला दिखाए और पुष्टि निकालने की बात कहते हुए पुलिस से शिकायत करने की बात भी कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद गंगाघाट कोतवाली पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है। कोतवाली प्रभारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि वीडियो कब और कहाँ का है, इसकी पुष्टि की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि आपका अमृत विचार अखबार नहीं करता है।

भविष्य संवराने की उम्र में टोल प्लाजा पर बूट पॉलिश कर लोगों के जूते चमका रहे बच्चे

नवाबगंज, अमृत विचार।

कानपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो दावों और हकीकत के बीच की खाई को बचा कर रही है। यहां नवाबगंज टोल प्लाजा के पास दो मासूम बच्चे अपने कंधों पर भारी बैग लटकाए राहगीरों के जूते पॉलिश करते नजर आए।

जिस उम्र में इन हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए थे, उनमें आज गरीबी ने पॉलिश की डिविया और ब्रश थमा दिया है। करीब 10 से 12 साल के ये दो बच्चे धूप और धूल के बीच पूरे दिन ग्राहकों का इंतजार करते हैं। एक बच्चा बड़ी कुशलता से जूते चमकाता है, तो दूसरा आने-जाने वाले लोगों से काम के लिए गुजारिश करता है। जब



टोल पर पॉलिश का बैग लिए बच्चे।

किसी राहगीर ने उनसे स्कूल जाने के बारे में पूछा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था सिर्फ एक फीकी मुस्कान और झुकी हुई नजरें थीं, जो उनकी बेवसी

को बचा कर रही थीं। प्रदेश सरकार और केंद्र की 'सर्व शिक्षा अभियान' जैसी योजनाएं हर बच्चे को स्कूल पहुंचाने का कहरा हैं। लेकिन टोल प्लाजा जैसे व्यस्त और संवेदनशील स्थान पर इन बच्चों का खुलेआम बाल श्रम करना प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आर्थिक तंगी ने इन परिवारों को इतना लाचार कर दिया है कि वे बच्चों के भविष्य की बलि देने को मजबूर हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि जब तक प्रशासन इन बच्चों को चिह्नित कर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से नहीं जोड़ता, तब तक बाल संरक्षण की बातें केवल कागजी ही रहेंगी।

मिशन शक्ति के तहत

किया गया जागरूक

शुक्लागंज (उन्नाव), अमृत विचार। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'मिशन शक्ति फेज-5' के अंतर्गत 'सशक्त नारी, समृद्ध प्रदेश' अभियान के तहत गुरुवार को नगर क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक किया गया। एंटी रोमियो महिला पुलिस दल ने विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर महिलाओं को उनके अधिकारों एवं सुरक्षा से जुड़ी सरकारी सेवाओं की जानकारी दी। गंगाघाट कोतवाली की महिला सिपाही श्रद्धा सिंह, मधु यादव और पूजा पाल ने गंगाघाट रेलवे स्टेशन, मरहला चौराहा तथा नगर की विभिन्न बंकों में महिलाओं से संवाद स्थापित किया। इस दौरान महिलाओं ने नशेबाजी से बचाव आदि के बारे में भी जानकारी दी।



पौधरोपण करते बीएसए एवं अन्य।

अमृत विचार

प्राइमरी विद्यालय में किया पौधरोपण

उन्नाव, अमृत विचार। जिलाधिकारी गौरांग राठी के निर्देशानुसार जनपद के परिषदीय विद्यालयों में सहजन की फली को मध्याह्न भोजन में शामिल करने तथा प्रत्येक विद्यालय परिसर में सहजन का पौधा लगाने की पहल शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में बुधवार को जिला बेंसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार पाण्डेय ने नगर क्षेत्र के पुलिस लाइन स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहजन का पौधरोपण किया। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय संजय यादव भी उपस्थित रहे। बीएसए ने बच्चों को सहजन के पौष्टिक गुणों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह कैल्शियम, आयरन तथा विटामिन ए, सी और ई से भरपूर होता है। इसके नियमित सेवन से बच्चों की हड्डियां मजबूत होंगी, पाचन तंत्र बेहतर होगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी।

युवक ने लगाया फंडा

अस्पताल में भर्ती

शुक्लागंज (उन्नाव), अमृत विचार। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र की बालूघाट चौकी अंतर्गत श्रीनगर इलाके में बुधवार रात एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। समय रहते परिजनों की नजर पड़ने से उसकी जान बच गई। गंभीर हालत में युवक को कानपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। श्रीनगर निवासी मयंक तिवारी (22) पुत्र अजय तिवारी ने रात करीब साढ़े नौ बजे अपने कमरे में फांसी लगा ली। उस समय घर पर उसकी मां और लहान मौजूद थीं। कुछ आहत होने पर परिजनों ने कमरे में देखा तो युवक फंदे पर लटका मिला। उसे तत्काल तबड़े से उतारकर राजधानी मार्ग स्थित एक निजी अस्पताल ले गए।

शिक्षकों को चयन वेतनमान स्वीकृत किए जाने की मांग

कार्यालय संवाददाता, उन्नाव

अमृत विचार। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला उपाध्यक्ष अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल खंड शिक्षा अधिकारी हिलोली सुरेश कुमार से मिला। इस दौरान बेंसिक शिक्षा अधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए विकासखंड के उन सभी शिक्षकों को चयन वेतनमान स्वीकृत करने की मांग की गई, जिनकी सेवाएं 10 वर्ष पूर्ण कर चुकी हैं। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि बीएसए द्वारा मांगी गई जिज्ञासाओं को पूर्ण कर शीघ्र प्रेषित किया जाए, ताकि पात्र शिक्षकों को समय से चयन वेतनमान का लाभ मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने की स्थिति में संगठन को आगे की रणनीति बनाने के

जाँव फेयर में कंपनियों की गैर-मौजूदगी पर

भड़के दिव्यांग

उन्नाव, अमृत विचार। आईटीआई परिसर में दिव्यांगों को रोजगार देने के नाम पर आयोजित किया गया जाँव फेयर विवादों के घेरे में आ गया है। प्रशासन ने मेले में 16 प्रतिष्ठित कंपनियों के शामिल होने का दावा किया था, लेकिन हकीकत में केवल 2 कंपनियाँ ही पहुँचीं। इस कुप्रबंधन से नाराज दिव्यांगों ने जमकर हंगामा किया और सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया। दिव्यांग महाठगबंधन के प्रदेश प्रवक्ता तन्मय श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने विकलांग वर्ग को सिर्फ मजाक बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दूर-दराज से आए दिव्यांगों को केवल परेशान किया गया।

जाँव फेयर में कंपनियों

की गैर-मौजूदगी पर

भड़के दिव्यांग

उन्नाव, अमृत विचार। आईटीआई परिसर में दिव्यांगों को रोजगार देने के नाम पर आयोजित किया गया जाँव फेयर विवादों के घेरे में आ गया है। प्रशासन ने मेले में 16 प्रतिष्ठित कंपनियों के शामिल होने का दावा किया था, लेकिन हकीकत में केवल 2 कंपनियाँ ही पहुँचीं। इस कुप्रबंधन से नाराज दिव्यांगों ने जमकर हंगामा किया और सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया। दिव्यांग महाठगबंधन के प्रदेश प्रवक्ता तन्मय श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार ने विकलांग वर्ग को सिर्फ मजाक बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दूर-दराज से आए दिव्यांगों को केवल परेशान किया गया।



पौनी रोड तिराहे पर जाम में फंसे वाहन सवार।

अमृत विचार

अवैध टेंपो स्टैंड से लगा भीषण जाम

शुक्लागंज (उन्नाव), अमृत विचार। पौनी रोड तिराहे पर अवैध टेंपो स्टैंड लगातार जाम का कारण बन रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहां ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड व पुलिसकर्मी अक्सर वाइंट छोड़कर गायब हो जाते हैं, जिसके बाद ऑटो और ई-रिक्शा चालक मनमानी ढंग से वाहन खड़े कर देते हैं। परिणामस्वरूप क्षेत्र में बार-बार भीषण जाम की स्थिति बन जाती है। गुरुवार दोपहर करीब दो बजे पौनी रोड तिराहे पर आड़े-तिरछे खड़े ऑटो और ई-रिक्शों के कारण पौनी रोड तिराहे से लेकर टाकीज के सामने तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। इसी दौरान एक लोडर के पौनी रोड की ओर मुड़ने से यातायात पूरी तरह टप टप हो गया। लोडर के हटते ही वाहनों का दबाव बालूघाट मोड़ पर पहुंच गया, जहां फिर जाम लग गया।

आयोजन

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में हुआ मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

वर्तमान में लोग अनिद्रा की समस्या से पीड़ित

संवाददाता, शुक्लागंज (उन्नाव)

अमृत विचार। राजधानी बर्ग स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य विभाग उन्नाव से आई विशेषज्ञ टीम ने मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक परामर्श एवं उपचार संबंधी जानकारी दी।

कार्यक्रम में मनोविज्ञान काउंसलर सरस्वती रानी, बलीनिकल साइकोलॉजिस्ट आशा गौतम तथा कम्प्यूनिटी नर्स विजय कुमार उपस्थित



मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में जानकारी देती विशेषज्ञ।

अमृत विचार

रहे। काउंसलर ने बताया कि प्रत्येक माह के दूसरे सप्ताह के गुरुवार को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त मरीजों को समय पर परामर्श और

उपचार मिल सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में अधिकांश लोग अनिद्रा की समस्या से जूझ रहे हैं। पर्याप्त नींद न लेने से इसका सीधा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, जिससे

व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि डायबिटीज और हृदय रोग की तरह स्क्रीजोफ्रेनिया भी एक शारीरिक रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को वास्तविक और काल्पनिक अनुभवों में अंतर करने में कठिनाई होती है। भूत-प्रेत का साया महसूस होना, नौकरी जाने का डर, लगातार उदासी, किसी काम में मन न लगना, वजन में बदलाव, आत्महत्या के विचार, यौन इच्छा में कमी और एक ही विचार का बार-बार आना इसके प्रमुख लक्षण हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि ऐसे मरीजों को धरमने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका उपचार संभव है।

गंगाघाट कोतवाली में हुई

पीस कमेटी की बैठक

शुक्लागंज (उन्नाव), अमृत विचार। आगामी महाशिवरात्रि, रमजान माह एवं होली पर्व के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से गुरुवार को गंगाघाट कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी सुशील कुमार ने की। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट राजीव राज, उपजिलाधिकारी सदर क्षितिज द्विवेदी तथा क्षेत्राधिकारी नगर बिनी सिंह मौजूद रहीं। बैठक में धर्मगुरुओं, संभ्रांत नागरिकों, विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजकों एवं डिजिटल वाॉलंटियर्स से सम्बन्धित कार्य, सौहार्द एवं त्योहार के साथ मनाने की अपील की गई।

निष्काम भक्ति से ही मिलती है

आध्यात्मिक शांति व मोक्ष की प्राप्ति

संवाददाता शुक्लागंज (उन्नाव)

अमृत विचार। कंचन नगर स्थित मां वैष्णो जूनियर हाईस्कूल परिसर में श्री ममतामयी मंडल परिवार के तत्वावधान में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा के सातवें दिन गुरुवार को श्रद्धा और भक्ति का वातावरण चरम पर रहा। कथा व्यास श्री वल्लभचरणश्रित केशव देव भक्तमाली ने सुदामा चरित्र का मार्मिक वर्णन करते हुए कृष्ण-मुदामा की निस्वार्थ मित्रता और अनन्य भक्ति का भावपूर्ण प्रसंग सुनाया। कथा श्रवण कर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। व्यास जी ने श्रीमद्भागवत महात्म्य के माध्यम से सात दिनों की कथा का सार प्रस्तुत करते हुए जीवन में भक्ति, समर्पण और सत्कर्मा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति से ही मनुष्य को आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम में विधि-विधान से



कथा व्यास को स्मृति चिन्ह देते पालिकाध्यक्ष प्रतिनिधि।

व्यास पूजन एवं आरती की गई। श्रद्धालुओं ने व्यासपीठ का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा समापन पर श्री शुक्रदेव जी द्वारा राजा परीक्षित को मोक्ष प्रदान करने का प्रसंग सुनाया गया, जिसके बाद उनकी भावपूर्ण विदाई का वर्णन हुआ। अंत में भगवान के साथ फूलों की दिव्य होली खेली गई और आनंद उत्सव मनाया गया। पूरा परिसर भक्ति रस में डूबा नजर आया।

न्यूज़ ब्रीफ

जल निकासी व्यवस्था का लिया जायजा

सिद्धार्थनगर, अमृत विचार। जिलाधिकारी शिवशरणपण्ण जीएन ने अध्यक्ष नगर पालिका सिद्धार्थनगर गोविंद माधव, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका, अधिशासी अभियंता एन एच 730 आरके वर्मा के साथ नगर पालिका के काशीराम कालोनी में जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने काशीराम कालोनी से उसका मार्ग, केन्द्रीय विद्यालय एवं जिला उद्यान कार्यालय के सामने एन एच द्वारा नाला निर्माण कार्य को देखा। अधिशासी अभियंता एन एच 730 एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को समन्वय स्थापित करते हुए नाला निर्माण कराने का निर्देश दिया, जिससे काशीराम कालोनी में जल जमाव न हो सकारू रूप से पानी नाले में पहुँच जाए।

दुकान में आग से लाखों रुपये का नुकसान

संतकबीरनगर। शहर कोतवाली क्षेत्र के बरदहिया बाजार में बुधवार देर रात होजरी की दुकान में आग लग गई। आग की चपेट में आकर दुकान में रखा लाखों रुपये का कौमती कपड़ा और अन्य सामान जलकर राख हो गया। महुली थाना क्षेत्र के कुरसुरी गांव निवासी दुकान मालिक इसराइल के अनुसार घटना में करीब 20 से 25 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। दमकल की दो गाड़ियों ने करीब दो घंटे की कड़ी शपकत के बाद आग पर काबु पाया।

परिवार की इच्छा के विरुद्ध विवाह करने वाले दंपति की सुरक्षा राज्य का दायित्व

हाईकोर्ट ने अगस्त, 2019 के सरकारी आदेश का कड़ाई से पालन करने का दिया निर्देश

विधि संवाददाता,प्रयागराज।



अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिग दंपतियों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के मुद्दे पर स्पष्ट किया कि पारिवारिक इच्छाओं के विरुद्ध विवाह करने वाले बालिग दंपतियों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के 31 अगस्त, 2019 के सरकारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, जिसमें ऐसे दंपतियों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय निर्धारित हैं। उक्त आदेश न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की एकलपीठ ने सामिया व अन्य की ओर से दायित्व को आकलन कर और परिस्थिति की गंभीरता के अनुसार सुरक्षित आवास व पुलिस सुरक्षा सहित आवश्यक संरक्षण उपलब्ध कराए। मामले

के अनुसार दोनों दंपति हापुर जिले के निवासी हैं। मौजूदा याचिका में आरोप लगाया गया था कि आयु अंतर और पति की वैवाहिक स्थिति को लेकर संदेह के कारण महिला का पिता दंपति को लगातार धमका रहा है, जिससे उनके जीवन और स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न हो गया है। हालांकि कोर्ट ने पाया कि पूर्व में प्रदान की गई अंतरिम सुरक्षा के बाद अब कोई तात्कालिक खतरा शेष नहीं है। इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए स्पष्ट किया कि भविष्य में यदि वास्तविक और गंभीर खतरा उत्पन्न होता है तो दंपति संबंधित पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। अधिकारियों को 2019 के सरकारी आदेश और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्रवाई करनी होगी।

एफआईआर याचिका खारिज होने के विरुद्ध हाईकोर्ट में चुनौती

विधि संवाददाता,प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका दायित्व कर संभल न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कथित विवादोत्पन्न बयान के संबंध में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए हिंदू शक्ति दल की सिमरन गुप्ता द्वारा दायित्व मौजूदा याचिका में तर्क दिया गया है कि वर्ष 2025 में एआईसीसी

कार्यालय के उद्घाटन के दौरान गांधी द्वारा कथित रूप से दिए गए बयान "हम अब भाजपा, आरएसएस और स्वयं भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं" से देशभर में जनभावनाएं आहत हुई हैं। इसे प्राथमिकी दर्ज करने योग्य आधार न मानते हुए संभल की निचली अदालत ने पिछले वर्ष प्रथम दृष्टया एफआईआर दर्ज करने की मांग अस्वीकार कर दी। इसके विरुद्ध दायित्व पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी गई। इसके बाद याची ने हाईकोर्ट का रुख किया। मामला न्यायमूर्ति समित गोपाल की

एकलपीठ के समक्ष प्रस्तुत हुआ। अपर शासकीय अधिकारता ने तर्क दिया याचिका में चुनौती के स्पष्ट आधार नहीं दर्शाए गए हैं। इस पर याची के अधिवक्ता ने आधारों को स्पष्ट करते हुए पूरक हलफनामा दायित्व करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। अंत में कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि पूरक हलफनामा दायित्व होने पर कार्यालय उसे अभिलेख पर ले और अगली तिथि तब धुंजीकृत करें। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को निर्धारित की गई है।

बिना सुनवाई समन आदेश असंवैधानिक : हाईकोर्ट

विधि संवाददाता,प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), भदोही द्वारा पारित समन आदेश को प्रथम दृष्टया प्रक्रियागत विट्पूरी पाते हुए कड़ी नाराजगी जताई। कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223(1) के प्रथम प्रावधान के तहत आरोपी को सुनवाई का अवसर दिए बिना संज्ञान लेना विधि-विरुद्ध है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरी की एकलपीठ ने विशाल विश्वकर्मा उर्फ विशाल द्वारा बीएनएसएस की धारा 528 के तहत दायित्व याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका में 13.11.2025 के समन आदेश तथा आचार्य शिकायत वाद की कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की गई थी। बता दें कि बीएनएसएस की धारा 75, 76, 352 तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(द) व 3(1)(घ) के तहत पुलिस स्टेशन भदोही, भदोही में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। विवेचना के उपरांत पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। तत्पश्चात विशेष-पध दायित्व हुआ, जिसे परिवार के अन्य में ग्रहण कर लिया गया और बयान दर्ज करने के बाद याची को समन कर लिया गया, इसके खिलाफ मौजूदा याचिका दायित्व की गई।

विवाह या धर्म परिवर्तन से नहीं बदलती जाति

विधि संवाददाता,प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जाति निर्धारण के मुद्दे पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि जन्म के समय प्राप्त जाति व्यक्ति के साथ बनी रहती है, भले ही वह धर्म परिवर्तन कर ले या विवाह कर ले। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवाह के बाद भी महिला की जन्मजात जाति में कोई परिवर्तन नहीं होता। उक्त टिप्पणी न्यायमूर्ति अनिल कुमार (दशम) की एकलपीठ ने दिनेश व आठ अन्य द्वारा दायित्व आचार्यिक अपील को खारिज करते हुए की। अपील में अलीगढ़ के विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 506, 452, 354 तथा एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(र) के अंतर्गत मुकदमे की सुनवाई के दौरान तलब किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अपीलकर्ताओं ने उसके साथ मारपीट और दुर्यवहार किया तथा विवाह के दौरान जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। घटना में उसके सहित तीन लोगों के घायल होने का भी आरोप है। समन आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता जन्म से अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय से संबंधित है, लेकिन जाट समुदाय के व्यक्ति से विवाह के बाद उसने अपनी जातिगत स्थिति खो दी है।

तीसरी लाइन निर्माण को दी स्वीकृति

गोरखपुर, अमृत विचार। रेल मंत्री अशोक वैष्णव ने रू. 497.07 करोड़ की लागत से पूर्वोत्तर रेलवे के औडिहार-वाराणसी सिटी (31.36 किमी.) तीसरी लाइन निर्माण को स्वीकृति प्रदान की। यह परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं गाजीपुर जनपद में अवस्थित है। परियोजना के अन्तर्गत कार्य आरम्भ होने पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा।

औडिहार-वाराणसी दोहरी लाइन खंड पर बड़ी संख्या में यात्री एवं माल गाड़ियों का संचलन किया जाता है। औडिहार एक प्रमुख जं. स्टेशन है, जहां से देश के बड़े और महत्वपूर्ण शहरों के लिये ट्रेनों का आवागमन होता है, जिसके कारण इस मार्ग पर तीसरी लाइन की माँग थी, जिसको पूरा करते हुये रेल मंत्रालय द्वारा औडिहार-वाराणसी सिटी के मध्य तीसरी लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है।

कॉरिडोर को तेजी से पूरा करने के लिए निर्देश

नई दिल्ली, अमृत विचार। यह नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लगभग 2,100 किलोमीटर लंबा होगा। यह डाकूनिज से सूरत तक पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरेगा। इससे पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच माल ढुलाई तेज और आसान होगी। मालगाड़ियों का समय बचेगा और मौजूदा रेल मार्गों पर भीड़ कम होगी। डीएफसीसीआईएल के अधिकारियों को आधुनिक तकनीक के अनुसार बेहतर तकनीकी मानक तय करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें उच्च क्षमता की बिजली व्यवस्था, बिना किसी लेवल क्रॉसिंग के ट्रैक और 'कवच' जैसी आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली शामिल करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा बढ़े और अधिक माल ढुलाई हो सके।

कानूनी लड़ाई में रेलवे को मिली ऐतिहासिक जीत

नई दिल्ली, अमृत विचार। भारतीय रेलवे को सुप्रीम कोर्ट से एक ऐतिहासिक और निर्णायक जीत मिली है। लगभग 10 वर्षों से चली आ रही कानूनी लड़ाई में शीर्ष अदालत ने रेलवे प्रशासन के अधिकारों पर लगी न्यायिक आपराधिक कार्यवाही को पूरी तरह खारिज किया। भारतीय रेल यातायात सेवा (आईआरटीएस) की वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण गौड़ द्विवेदी से जुड़े इस मामले में आया फैसला न केवल रेलवे के संस्थागत हितों की रक्षा करता है, बल्कि भविष्य में रेलवे प्रशासनिक स्वायत्तता के लिए एक मजबूत कानूनी आधार भी तैयार करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णायक फैसले में निचली अदालतों के विवादित आदेशों को रद्द कर दिया और रेलवे अधिकारी के विरुद्ध चल रहे आपराधिक कार्यवाही को खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जहां रेलवे मजिस्ट्रेट अपने ही मामले में जज बनना चाहते हैं। अपीलकर्ता ने अपने आधिकारिक क्षमता से बाहर को काम नहीं किया था।

तिलौराकोट क्षेत्र में

बौद्ध मंदिर खोजा गया

ककरहवा, सिद्धार्थनगर, अमृत विचार। नेपाल के इतिहास में पहली बार अम्साइडल (अर्धचंद्राकार) शैली के बौद्ध मंदिर की खोज तिलौराकोट-कपिलवस्तु क्षेत्र में की गई है। पुरातत्व विभाग ने बुधवार को प्रेस वार्ता में इस महत्वपूर्ण खोज की आधिकारिक घोषणा की। यह खोज दक्षिण एशिया के प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के सर्वाधिक संरक्षित प्राचीन नगरों में शामिल तिलौराकोट क्षेत्र में हुई है। प्रेस वार्ता में पुरातत्व विभाग, लुम्बिनी विकास स्ट्रेट तथा यूके के उद्ग्रह विश्वविद्यालय से संबद्ध यूनेस्को के चेरर के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को संयुक्त टीम ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी साझा की। विशेषज्ञों के अनुसार अम्साइडल मंदिर दक्षिण एशियाई धार्मिक वास्तुकला की एक विशिष्ट शैली है, जिसकी प्रमुख पहचान इसका अर्धचंद्राकार पिछला भाग तथा सामने बना प्रवेश मंच होता है।

13 घंटे चले ईडी के छापे में नहीं

मिले आपत्तिजनक दस्तावेज

संवाददाता, संतकबीरनगर परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई तथा मोबाइल फोन व अन्य जरूरी कागजातों की पड़ताल की गई। वहीं, मौलाना की पत्नी सकलैन खातून और पुत्रवधू नसरिन जहां का बयान धर्म शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएएल) 2002 के तहत दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद टीम बिना किसी दस्तावेज की जल्दी के वापस लौट गई। मौलाना शमसुल हूदा खातून की पत्नी व पुत्रवधू दोनों ने ईडी के पूछताछ को पुष्टि भी की। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। आवास के बाहर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान तैनात रहे और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। संतकबीरनगर में कार्रवाई सहायक निदेशक प्रताप सिंह (ईडी, लखनऊ) के नेतृत्व में हुई।

फार्मर रजिस्ट्री प्रचार वाहन को डीएम ने किया रवाना

संतकबीरनगर, अमृत विचार। जनपद में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री अभियान को गति देने के लिए गुरुवार को जिलाधिकारी आलोक कुमार व पुलिस अधीक्षक सदीप कुमार मीणा ने प्रचार वाहन को इरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी जय प्रकाश भी मौजूद रहे। डीएम आलोक कुमार ने बताया कि प्रचार वाहन तीनों तहसीलों के सभी ब्लॉकों व न्याय पंचायतों में भ्रमण कर किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के प्रति जागरूक करेगा। किसानों को आधार व खतौनी के माध्यम से पोर्टल पर भूमि विवरण दर्ज कर गोल्डन कार्ड बनवाना है।

अमृत विचार

क्लासीफाइड

विज्ञापन हेतु अमृत विचार कार्यालय में सम्पर्क करें

सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा हाईस्कूल मुख्य परीक्षा सन-1985 अनुक्रमांक-1199020 का प्रमाण-पत्र वास्तव में खो गया है। MOHAMMAD SAIF (मोहम्मद सैफ) पुत्र AFZAL AHMAD (अफजाल अहमद), निवासी-म0रं0-107/44, बाइसी की मस्जिद, लखनऊ, उ0प्र0-226001

सूचना
मैंने अपना नाम MOHAMMAD SHAHAVAN से बदल कर SAHBAN रख लिया अब इसी नाम से जाना व पहचाना जाये। FATHER NAME -JIRFAN ADD-VILLAGE SARKATIYA POST AND PS-RUDAULLI DIST-AYODHYA-224120 (U.P.)

सूचना
सूचित हो कि पहले मेरा नाम CHANDRA PRAKASH GUPTA था से बदलकर CHANDRA PRAKASH रख लिया है। अब मुझे CHANDRA PRAKASH के नाम से जाना व पहचाना जाये। S/O-VISHVA NATH GUPTA, ADD-94/109, NEAR SA B A B A M A N D J R N A V A I Y A GANESHANJUR PARK ANMINABAD DIST-LUCKNOW-226018 (U.P.)

सूचना
सूचित हो कि पहले मेरा नाम MITHILESH KUMAR SHARMA था से बदलकर CHANDRA PRAKASH रख लिया है। अब मुझे MITHILESH SHARMA के नाम से जाना व पहचाना जाये। S/O- ISHWAR CHANDRA JAISWAL R/O- WARD NO 7 BILTHARA ROAD, PO- BILTHARA ROAD, DISTT- BALLIA UTTAR PRADESH- 221715

सूचना
सूचित हो कि पहले मेरा नाम TABREZ AHMAD KHAN था से बदलकर TABREZ AHMED KHAN रख लिया है। अब मुझे TABREZ AHMED KHAN के नाम से जाना व पहचाना जाये। S/O- SHABIR AHMED KHAN ADD- 314, SITALAPUR MANKAURA NUNGO SHITLAPUR DIST-BALRAMPUR-271208(U.P.)

सूचना
पहले मेरा नाम RAKESH KUMAR था अब मैंने बदलकर अपना नाम RAKESH KUMAR JAISWAL रख लिया है गतिव्य में मुझे RAKESH KUMAR JAISWAL के नाम से जाना व पहचाना जाये। S/O- ISHWAR CHANDRA JAISWAL R/O- WARD NO 7 BILTHARA ROAD, PO- BILTHARA ROAD, DISTT- BALLIA UTTAR PRADESH- 221715

Public Notice
Delisha Anwar daughter of Lt. Sabir Anwar Siddiqui is now to be known as Dalisha Anwar Siddiqui as her name has been corrected in the school records as it was a manual error done by her parents.

सूचना
मैं पिन्की गुप्ता पत्नी ललित कुमार गुप्ता निवासिनी 5/417, विकास नगर, लखनऊ, उ0प्र0, सर्वसाधारण को विवेदित करना है कि पिन्की सिंह, श्री ललित कुमार गुप्ता की पत्नी हैं। इनके नाम में पिन्की सिंह के स्थान पर पिन्की गुप्ता जाना जाए।

छात्र-छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा



कार्यक्रम में प्रतिभाग करती छात्राएं।

सिद्धार्थनगर, अमृत विचार।

जनपद स्तरीय प्रगति-स्वभिमान और सफलता की ओर 2.0 बाल उत्सव का आयोजन गुरुवार को उत्साहपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में जनपद के सभी 14 विकास खंडों से आए छात्र-छात्राओं ने भाग लेकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। पूरे आयोजन में बच्चों के चेहरे पर आत्मविश्वास और मंच पर प्रस्तुती की दृढ़ता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एंटी रोमियो दल की जिला प्रभारी साइत खान रहीं। उन्होंने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने प्रेरक संबोधन में उन्होंने कहा कि स्वभिमान, साहस और आत्मनिर्भरता जीवन की सफलता के मूल मंत्र हैं। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि डर और झिझक को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही सच्ची प्रगति है। आप सभी अपने परिवार, समाज और देश का भविष्य हैं। अपने अंदर की क्षमता को

बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की हुई समीक्षा

सिद्धार्थनगर, अमृत विचार। जिलाधिकारी शिवशरणपण्ण जीएन की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी बलराम सिंह की उपस्थिति में बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक सिद्धार्थ सभागार में संपन्न हुआ। जिलाधिकारी ने पीएम श्री स्कूल फेज वन एवं फेज टू में गैस के पैरामीटर की समीक्षा की। निष्पुण लक्ष्य के लिए जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

पहचानिए और उसे निखारने का निरंतर प्रयास कीजिए। उन्होंने बालिकाओं को विशेष रूप से आत्मनिर्भर बनने, शिक्षा को प्राथमिकता देने और किसी भी प्रकार के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का संदेश दिया। विशिष्ट अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण का सशक्त माध्यम है।

सांडों के हमले में युवक की

मौत, बुजुर्ग की हालत गंभीर

संवाददाता कुशीनगर

अमृत विचार: हाटा कोतवाली क्षेत्र के भिस्वां बाजार में छुड़ा सांडों के झुंड ने युवक पर हमला कर दिया, जिससे मल्लू (48) पुत्र भुवर प्रजापति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मल्लू को बचाने गये मिट्टु यादव (65) गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने बुजुर्ग को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा पहुंचाया जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। गुरुवार दोपहर बाद लगभग 5 बजे मल्लू अपना गेहूं खेत देखने बगीचे की तरफ निकला था, जहां एक दर्जन से अधिक सांडों के झुंड ने उस

पूर्वोत्तर रेलवे की टीम ने

प्रतियोगिता में दर्ज की जीत

गोरखपुर, अमृत विचार।

गाजीपुर में चल रहे राज्य स्तरीय महिला हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मैच में पूर्वोत्तर रेलवे की टीम ने उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम को हरा कर प्रतियोगिता जीत ली। पूर्वोत्तर रेलवे की सुमिता को प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एवं नंदनी को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। पूर्वोत्तर रेलवे की महिला हॉकी टीम की इस उपलब्धि पर महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे एवं संरक्षक/नरसा उदय बोरवणकर, अपर महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे विनोद कुमार शुक्ल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण एवं अध्यक्ष/नरसा अभय कुमार गुप्ता, मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक/पी.एम. एवं उपाध्यक्ष/नरसा विजय कुमार, मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी एवं महासचिव/नरसा चंक्रज अंधार सिंह, सहायक क्रीड़ाधिकारी चन्द्र विजय सिंह तथा नरसा पदाधिकारियों ने बधाई दी है।

छात्र-छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा

सिद्धार्थनगर, अमृत विचार। जनपद स्तरीय प्रगति-स्वभिमान और सफलता की ओर 2.0 बाल उत्सव का आयोजन गुरुवार को उत्साहपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में जनपद के सभी 14 विकास खंडों से आए छात्र-छात्राओं ने भाग लेकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। पूरे आयोजन में बच्चों के चेहरे पर आत्मविश्वास और मंच पर प्रस्तुती की दृढ़ता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एंटी रोमियो दल की जिला प्रभारी साइत खान रहीं। उन्होंने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने प्रेरक संबोधन में उन्होंने कहा कि स्वभिमान, साहस और आत्मनिर्भरता जीवन की सफलता के मूल मंत्र हैं। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि डर और झिझक को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही सच्ची प्रगति है। आप सभी अपने परिवार, समाज और देश का भविष्य हैं। अपने अंदर की क्षमता को

लिया जायजा

जलाभिषेक मार्ग और मेला क्षेत्र में सुरक्षा, पार्किंग व भीड़ प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा

कमिश्नर – डीआईजी ने किया निरीक्षण

संवाददाता, संतकबीरनगर



तामेश्वर नाथ धाम स्थित महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारी का जायजा लेते कमिश्नर बस्ती अखिलेश सिंह, डीआईजी संजीव त्यागी व अन्य अधिकारी।

अमृत विचार। आगामी महाशिवरात्रि पर्व को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बृहस्पतिवार को कमिश्नर बस्ती अखिलेश सिंह व डीआईजी संजीव त्यागी ने डीएम आलोक कुमार और एसपी सदीप कुमार मोना के साथ बाबा तामेश्वरनाथ धाम का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने मंदिर परिसर, जलाभिषेक मार्ग और मेला क्षेत्र में सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर

रूम स्थापित करने, अग्निशामक दल की तैनाती सुनिश्चित करने तथा वालंटियर्स की मदद लेने के निर्देश दिए। साथ ही खोया-पाया केंद्र संचालित करने, साफ-सफाई, पेंयजल, प्रकाश व्यवस्था और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

वहीं, डीआईजी बस्ती रेंज संजीव त्यागी ने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों, मंदिर के पुजारी/गोसाईं जी तथा स्थानीय ग्रामीणों के साथ बैठक कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। मंडलायुक्त व डीआईजी ने पर्व को आपसी प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनपद की शांतिपूर्ण परंपरा को बनाए रखते हुए कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को चेन स्टेजिंग, चोरी जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।



वर्ल्ड वीफ

पटना: नीट की छात्रा की मौत के मामले को सीबीआई ने संभाला

नई दिल्ली। पटना में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले की जांच सीबीआई ने स्थानीय पुलिस से अपने हाथ में ले ली है। जहानाबाद निवासी छात्रा 6 जनवरी को पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित महिला छात्रावास में बेहोश मिली थी। बाद में वह कोमा में चली गई और पांच दिन बाद निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद मचे हंगामे से बिहार सरकार ने 31 जनवरी को मामला सीबीआई को सौंप दिया। परिजनों ने पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। पीड़िता के परिवार ने अधिकारियों पर मामले को दबाने का भी आरोप लगाया।



केरल के तिरुचिरापल्ली में हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने रेल ट्रैक जाम कर दिया।

बजट सत्र : संसद के दोनों सदनों में पक्ष-विपक्ष के बीच घमासान जारी

सत्ता ने किया अर्थव्यवस्था मजबूत होने का दावा, विपक्ष बोला- कोई उपलब्धि नहीं

● **राज्यसभा में चर्चा के दौरान भाजपा ने कहा- सरकार का केवल विरोध करना है इसलिए बजट की आलोचना नहीं की जानी चाहिए**

नई दिल्ली, एजेंसी

आम आदमी के विकास को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए राज्यसभा में सत्ता पक्ष ने कहा कि भारत का दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना बताया है कि सरकार ने कितना काम किया है। वहीं विपक्ष ने दावा किया कि उपलब्धियों के नाम पर सरकार के खाते में कुछ भी नहीं है।

राज्यसभा में बजट पर हो रही चर्चा में भाजपा के मदन राठौर ने कहा कि यह पूर्ण बजट है और इसमें पिछले साल तक हुए सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। केवल विरोध करना है इसलिए बजट की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसके सकारात्मक पक्षों को भी देखना चाहिए। अगर कांग्रेस के कार्यकाल से तुलना की जाए तो यह बजट हर मायने में बेहतर है। कांग्रेस के जीसी चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार का ध्यान विज्ञापनों पर है, वह पुरानी योजनाओं को समाप्त कर रही है और कई का नाम बदल रही है। उपलब्धियों के नाम पर उसके खाते में कुछ भी नहीं है।

भाजपा के शंभुशरण पटेल ने कहा कि यह बजट 140 करोड़ देशवासियों के सपने साकार करने वाला बजट है। मर्याद नायक ने कहा कि हर मद में बजट बढ़ाया गया और कोई भी वर्ग उपेक्षा का दावा नहीं कर सकता। भाजपा के केसरदेव सिंह झाला ने कहा कि प्रदूषण की समस्या के हल को बजट में 20 हजार करोड़



औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक को विपक्ष ने मजदूर विरोधी बताया, भाजपा ने कहा- श्रमिक हितैषी, हड़ताल रुकेगी

नई दिल्ली। औद्योगिक क्षेत्र के तीन कानूनों की जगह लेने वाली औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में सरकार द्वारा पेश संशोधन पर लोकसभा में चर्चा करते हुए विपक्ष ने इसे उद्योगों के हित वाला तथा श्रमिक क्षेत्र के लिए असुरक्षा पैदा करने वाला कदम बताया, वहीं भाजपा ने कहा कि इसका मकसद सभी पक्षों के हितों की रक्षा करना है। प्रस्तावित कानून पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने कहा कि यह विधेयक सुधार वाला नहीं, बल्कि पीछे लौटने वाला है और इसका उद्देश्य क्रमबद्ध तरीके से पूर्ववर्ती संगम सरकार के समय के श्रमिक सुरक्षा सुधारों को समाप्त करना है। उन्होंने देशव्यापी श्रमिक संगठनों की हड़ताल का जिक्र करते हुए कहा कि यह सरकार के लिए घेतावनी है लेकिन सरकार संवाद के बजाय अपने प्रभुत्व में विधवा रखती है। भाजपा के सदस्य दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि इस संहिता का मकसद प्रगतिशील श्रमिक सुधारों को लागू करते हुए कर्मचारियों समेत सभी पक्षों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि यह संहिता न केवल अर्थव्यवस्था को सुधारेगी, बल्कि मजदूरों को आगे बढ़ाएगी इससे गैरकानूनी हड़ताल और तालाबंदी रुकेगी।

तय करना बेहतर कदम है। भाजपा के अमरपाल मौर्य ने कहा कि यह बजट देश के दीर्घकालिक निर्माण की नींव रखता है। सीमा द्विवेदी ने हर जोषों में महिला छात्रावास खोलने की सरकार की नीति को सराहनीय बताया। राजीव भट्टाचार्य ने कहा कि शिक्षा के बजट में 14.2 फीसदी की वृद्धि की गई है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संदोष कुमार पी ने कहा कि सरकार खुद बताए कि उसने आम आदमी के लिए इस बजट में क्या दिया है। शिवसेना (उबाटा) की प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बजट से 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग बजट में अपने लिए कुछ सुविधा की उम्मीद लगाए हुए थे लेकिन वह लोग निराश हो गए।

बंद : विपक्ष शासित राज्यों में जनजीवन ठप

केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत कई राज्यों में रहा पूरी तरह बंद

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं समेत कई और मुद्दों के विरोध में दस ट्रेड यूनियनों की ओर से गुरुवार को आहूत 24 घंटे के भारत बंद का देश भर में मिलाजुला असर देखने को मिला। इस हड़ताल ने विपक्ष शासित राज्यों, खासकर दक्षिणी राज्यों में जनजीवन और कारोबार को लगभग ठप कर दिया, दूसरी ओर बाकी भारत में जनजीवन काफी हद तक सामान्य रहा।

केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में पूरी तरह बंद रहा। विपक्षी पार्टियों का शासन वाले पश्चिम बंगाल, पंजाब और झारखंड में बंद आंशिक था, जिसका असर सिर्फ औद्योगिक इलाकों तक ही सीमित था। कई राज्यों की राजधानियों और



औद्योगिक केंद्रों में, मजदूरों ने भारत बंद के साथ एकजुटा दिखाते हुए आईएनटीयूसी, सीटू, एटक और एचएमएस जैसी बड़ी ट्रेड यूनियनों के बैनर तले मार्च और रैलियां निकालीं। इसमें औद्योगिक श्रमिक, किसान और बैंकिंग, बीमा और दूसरे संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ट्रेड यूनियन की हड़ताल की गूंज संसद की कार्यवाही में भी सुनाई दी, जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने

आंदोलन कर रहे श्रमिकों को अपना समर्थन दिया। राहुल गांधी ने कहा, देश भर में लाखों श्रमिक और किसान सड़कों पर हैं, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन्होंने सरकार पर उनके भविष्य पर असर डालने वाले फैसले लेते समय हितधारकों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। गांधी ने लिखा, श्रमिकों को डर है कि चार श्रम संहिताएं उनके हक को कमजोर कर देंगी। किसानों को चिंता है कि व्यापार समझौतों से उनकी रोजी-रोटी को नुकसान होगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि मनरेगा को कमजोर करने या बंद करने का कोई भी कदम ग्रामीण भारत पर बहुत बुरा असर डालेगा। अगर मनरेगा को कमजोर किया गया या खत्म कर दिया गया, तो गांवों के पास सहारे का आखिरी जरिया भी खत्म हो सकता है।

निशिकांत ने की राहुल के खिलाफ दिए नोटिस पर सदन में चर्चा की मांग

नई दिल्ली। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया और कांग्रेस नेता के खिलाफ दिये गए विशिष्ट नोटिस पर सदन में चर्चा कराने की मांग की। शून्य काल के दौरान, भाजपा सांसद ने राहुल पर सोरोस फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया।



● **सदस्यता रह दो और कभी चुनाव नहीं लड़ पाए**

उन्होंने आरोप लगाया, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करते हैं। भाजपा सदस्य ने दावा किया कि राहुल गांधी केवल देशद्रोहियों से मिलने वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन और थाईलैंड जाते हैं। दुबे ने यह भी आरोप लगाया, वह कभी निर्वाचन आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी लोकसभा अध्यक्ष पर, उच्चतम न्यायालय पर, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा, 'मेरा आग्रह है कि एक विशिष्ट प्रस्ताव पर राहुल गांधी पर चर्चा होनी चाहिए। उनकी सदस्यता रह होनी चाहिए और वह कभी चुनाव नहीं लड़ पाएं।

विशेषाधिकार हनन लाओ या मुकदमा करो किसानों के लिए लड़ंगा: राहुल

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर देश और किसानों को अमेरिका के हाथों बेचने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार उनके खिलाफ चाहे मुकदमा दर्ज करवाए या विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाए, वह किसानों को लड़ाई लड़ते रहेंगे।



● **मोदी ने अपने अरबपति मित्रों के लिए देश बेचा**

राहुल गांधी ने 'एक्स' और अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा, प्राथमिकी हो, मुकदमा दर्ज हो या विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएं, मैं किसानों के लिए लड़ंगा। कोई भी ऐसा व्यापार समझौता जो किसानों की रोजी-रोटी छीने या देश को खाद्य सुरक्षा को कमजोर करे, वह किसान-विरोधी है। किसान-विरोधी मोदी सरकार को अन्मदाताओं के हितों से समझौता नहीं करने देंगे। कहा, किसान विरोधी मोदी ने देश के अन्मदाताओं को, उनके खून-पसीने को ट्रंप के हाथों बेच दिया है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री पहले अपने अरबपति मित्रों के मुनाफे के लिए काले कानून लाए थे, अब अपने गले से अमेरिकी शिफ्टा बटाने के लिए ट्रंप के अमेरिका के सामने भारतीय खेती के दरवाजे खोल दिए।

अमरनाथ यात्रियों के लिए दुर्घटना बीमा राशि 10 लाख रुपये

जम्मू। दक्षिण कश्मीर में होने वाली वार्षिक अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में पंजीकृत यात्रियों, सेवा प्रदाताओं और पुजारियों के लिए दुर्घटना बीमा की राशि पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है। यह निर्णय जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई श्राइन बोर्ड (एसएसबी) की बैठक में लिया गया।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि बोर्ड ने 2026 की यात्रा के लिए प्रथम पूजा 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर करने की घोषणा की है। यात्रा के औपचारिक आरंभ की तिथि शीघ्र ही तय की जाएगी। प्रतिवर्ष देशभर से लाखों श्रद्धालु 3,880 मीटर ऊंचा पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से निर्मित हिम

शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। प्रवक्ता ने बताया कि बोर्ड ने बाबा बर्फानी को समर्पित लेजर और साउंड शो आयोजित करने को भी मंजूरी दी है, जो श्रीनगर और जम्मू में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा एसएसबी कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कदमों को भी मंजूरी दी गई।

एचएएल को आठ डॉर्नियर-228 विमानों का मिला आर्डर

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

अमृत विचार। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को नई दिल्ली में कानपुर स्थित हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के परिवहन विमान प्रभाग के साथ भारतीय तटरक्षक बल (आईसीबी) के लिए आठ डॉर्नियर-228 विमानों और परिचालन संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए 2,312 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह अनुबंध भारतीय उत्पाद खरीद (बाय) (इंडियन) श्रेणी के तहत किया गया। रक्षा मंत्रालय की ओर से अनुबंध पर रक्षा सचिव राजेश कुमार

सिंह ने हस्ताक्षर किए। डॉर्नियर 228 विमान उन्नत सेंसर और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस हैं, जिनमें पूर्ण ग्लास कॉकपिट, एकीकृत मिशन प्रबंधन प्रणाली तथा समुद्री निगरानी और टोही अभियानों के लिए विशेष इंतजाम शामिल किए गए हैं। इस अनुबंध से न सिर्फ एचएएल का उत्पादन तंत्र मजबूत होगा, बल्कि लघु एवं मध्यम उद्यमों के नेटवर्क को भी समर्थन मिलने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार भी सुजिक होगा। एचएएल की ओर से कहा गया है कि यह अनुबंध आत्मनिर्भर भारत और मेक-इन-इंडिया के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के साथ

भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना को भी मजबूत बनाएगा। इससे पहले पिछले माह के अंत में भारतीय तटरक्षक बल को दो डॉर्नियर- 228 विमान सौंपे गए थे। इन्हें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कानपुर स्थित ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवाइजन से तटरक्षक बल को दिया गया था। तटरक्षक बल ने इन विमानों का कई तरह के समुद्री अभियानों के लिए इस्तेमाल किए जाने की बात कही थी। इनमें तटीय निगरानी, प्रदूषण पर नजर, खोज और बचाव अभियान और रियल टाइम खुफिया जानकारी जुटाना शामिल था। डॉर्नियर-228 की

एअर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच जारी: एएआईबी

बंगलुरु, एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के अलंद शहर में लाडले मशाक दरगाह पर महाशिवरात्रि पूजा रोकने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया और पूजा जारी रखने की इजाजत दे दी। इस साल 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर दरगाह के भीतर मौजूद राघव चैतन्य शिवलिंग की पूजा होनी है। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसमें प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रतीत होता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह इस अनुच्छेद के तहत शीघ्र न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की पीठ ने



● **संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई थी याचिका, कोर्ट ने खारिज कीं दलीलें**

कहा कि संपत्ति या स्थानीय धार्मिक रीति-रिवाजों पर हर विवाद अनुच्छेद 32 के तहत नहीं आता। इसे उच्च न्यायालय या दूसरी प्रशासनिक इकाइयों के फैसलों का लांघने के लिए शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि पूजा की इजाजत देने से दरगाह का धार्मिक रूप बदल जाएगा, जिसे वक्फ घोषित किया गया था। उन्होंने उस जगह के

दरगाह में है संत राघव चैतन्य की समाधि

14वीं सदी के सूफ़ी संत लाडले मशाक के नाम पर बनी लाडले मशाक दरगाह में 15वीं सदी के हिन्दू संत राघव चैतन्य की समाधि भी है। उस जगह पर शिवलिंग ऐतिहासिक रूप से दोनों समुदायों के भक्तों को अपनी ओर खींचता रहा है। हिन्दू पारंपरिक रूप से वहां पूजा करते रहे हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने फरवरी 2025 में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सिर्फ 15 लोगों को महाशिवरात्रि पूजा करने की इजाजत दी थी, जबकि याचिका में 500 भक्तों के लिए इजाजत मांगी गयी थी।

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में हिंसा काबू में आई

नई दिल्ली। केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले साल 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा में भीड़ को उकसाने वाले मुख्य शख्स थे। केंद्र से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज ने कहा कि वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद हिंसा नियंत्रण में आ गई। नटराज ने पीठ को बताया कि वह हिंसा को मुख्य रूप से उकसाने वाले थे। हिरासत आदेश में स्पष्ट संबंध दिखाता है, इसमें सोची-समझी रणनीति का इस्तेमाल किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद आंदोलन और हिंसा नियंत्रण में आ गई। इसलिए वह साबित हो गया कि गिरफ्तारी का आदेश सटीक था जो उस स्थिति में उचित था। विधि अधिकारी ने कहा कि वांगचुक की हिरासत के लिए इन सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक पालन किया गया।

राकांपा के दोनों गुटों के विलय में शरद बने बाधा

मुंबई, एजेंसी

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में उसके संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार के ही दिवंगत अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा के साथ एकीकरण के मार्ग में बाधा बन जाने की सुगबुगाहट है। इस बीच शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा, हम जटिल ही दोनों गुटों के विलय के संबंध में घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा, हालांकि वह यह घोषणा गुरुवार को करने वाले थे लेकिन अब 16 या 17 फरवरी को करेंगे।

कहा जा रहा है कि अजीत पवार गुट के भीतर भी इस मुद्दे पर मोटे तौर पर दो धड़े हैं। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व वाला एक धड़ा भाजपा समर्थक है जो चाहता है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा का विलय अजीत पवार गुट में उन शर्तों पर हो जो भाजपा और मुख्यमंत्री देवेंद्र

मप्र: सिंगरौली में दो लोगों की दी गई बलि आरोपी गिरफ्तार

● **अजीत पवार के गुट में भी बने दो धड़े, सुनेत्रा पवार भी अनिश्चय में**

फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन सरकार के अनुकूल हों। तटकरे ने बुधवार को खुलकर यह बात कही। दूसरी ओर अजीत पवार गुट के अमोल मिटकरी और प्रमोद हिंदुराव समेत कई नेता भाजपा को लाभ पहुंचाने वाले विलय के विचार के प्रति खुश नहीं हैं, साथ ही दिवंगत अजीत पवार की 28 जनवरी को हुई विमान दुर्घटना में मृत्यु के बारे में खुलासे भी कर रहे हैं।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के प्रभाव में हैं, जो भाजपा के करीबी माने जाते हैं। उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हालिया बैठक ने मामलों को और अधिक जटिल बना दिया है।

सिंगरौली। मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में अंधविश्वास से जुड़े मानव बलि के मामले में गुरुवार को तड़के दो लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर लोहरा गांव के बैरिहवा टोल में 21 वर्षीय युवक को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बताया कि आरोपी ने फूलकुमारी सिंह गोड और कमल नारायण सिंह गोड को घर बुलाकर धारदार हथियार से उन पर हमला किया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। जब दो ग्रामीणों सुमित्रा सिंह और राम भजन सिंह ने हस्तक्षेप की कोशिश की तो आरोपी ने उन्हें घायल कर दिया। यह घटना सुबह चार से पांच बजे के बीच हुई और यह पूर्व नियोजित थी। हत्याओं को आरोपी के घर के बाहर आंगन के चबूतरे के पास अंजाम दिया गया। पुलिस को घटनास्थल से धार्मिक अनुष्ठानों की सामग्री मिली।

विपक्ष के आरोप

आधिकारिक समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के सभी छह छंद को राष्ट्रगान जन गण मन से पहले गाए जाने के केंद्र के निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तीखी राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने इस आदेश को रवींद्रनाथ टैगोर को कमतर दिखाने और चुनावी लाभ के लिए प्रतीकवाद बढ़ाने का प्रयास बताया, वहीं कांग्रेस को आरोपी के घर के बाहर आंगन के चबूतरे के पास अंजाम दिया गया। पुलिस को घटनास्थल से धार्मिक अनुष्ठानों की सामग्री मिली।

राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम् गाने के केंद्र के आदेश पर बंगाल में शुरू हुआ सियासी घमासान

चट्टोपाध्याय के गीत को पूरा सम्मान वापस दिलाने का प्रयास है। बुधवार को अधिसूचित इस आदेश में गृह मंत्रालय ने कहा कि जब राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान साथ-साथ गाए जाएं, तो वंदे मातरम् को जन गण मन से पहले गाया जाना अनिवार्य है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता

और राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रज्य बसु ने कहा कि पार्टी को बंकिमचंद्र के योगदान को उजागर करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह कदम टैगोर को कमतर दिखाने का प्रयास है। बसु ने कहा, इस बात पर जोर देकर कि वंदे मातरम् को जन गण मन से पहले गाया जाना चाहिए, वे एक श्रेणी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए रवींद्रनाथ का अपमान किया गया है। राज्य की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए याद दिलाया कि उन्होंने एक बार संसद में बंकिमचंद्र को बंकिम दा कहा था। उन्होंने कहा, क्या यह उस



शुक्रवार, 13 फरवरी 2026

महत्वाकांक्षी बजट

उत्तर प्रदेश सरकार का तकरीबन सवा नौ लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट संकेत देता है कि सरकार राज्य को 'ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था' के लक्ष्य पर अग्रसर है। बजट में बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक निवेश पर विशेष जोर है। एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर और औद्योगिक पार्क जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रावधान प्रशंसनीय हैं। इससे निवेश आकर्षित होगा और दीर्घकाल में रोजगार सृजन की संभावना बढ़ेगी। पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं क्षेत्रीय असमानता कम करेंगी।

सरकार ने कौशल विकास, स्टार्टअप और स्वरोजगार योजनाओं के लिए बजट बढ़ाया है, हालांकि प्रत्यक्ष सरकारी नौकरियों की बड़ी घोषणाएं सीमित हैं। रोजगार सृजन का भरोसा मुख्यतः निजी निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार पर आधारित है। चुनावी वर्ष की आहट को देखते हुए युवाओं के लिए लक्ष्य आधारित कार्यक्रम स्वागत योग्य हैं, लेकिन उनकी टोस समय सीमा और निगरानी तंत्र भी स्पष्ट होना चाहिए। सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने और डिजिटल शिक्षा पर खर्च बढ़ाने से मानव संसाधन विकास को बल मिलेगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी पार्क और अनुसंधान केंद्रों के लिए प्रावधान यह संकेत देते हैं कि राज्य तकनीक आधारित विकास मांडल अपनाता चाहता है। शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वेतन या स्थायीकरण संबंधी कोई स्पष्ट राहत न मिलना असंतोष का कारण बन सकता है। यह वर्ग लंबे समय से नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग कर रहा है। कृषि बजट में सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, फसल बीमा और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की घोषणाओं से उत्पादकता और लागत संतुलन में मदद मिल सकती है, किसानों को तकनीक आधारित सेवाओं और कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलना दीर्घकालीन सुधार का संकेत है, पर एमएसपी, गन्ना भुगतान या कृषि ऋा राहत जैसे मुद्दों पर कोई बड़ा और नया एलान भी अपेक्षित था। विधवा, वृद्ध और दिव्यांग पेंशन योजनाएं जारी हैं, परंतु वृद्धावस्था पेंशन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी न होना महंगाई के परिप्रेष्य में निराशाजनक माना जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा का दायरा विस्तारित हुआ है, पर राशि में बड़े इजाफे की उम्मीद पूरी नहीं हुई। 8वें वेतनमान की घोषणा न होना यह दर्शाता है कि सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखना चाहती है। वेतन व्यय पहले ही बजट का बड़ा हिस्सा लेता है, संभव है कि इस पर निर्णय केंद्र के संकेतों के बाद लिया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश परियोजनाओं में पिछली घोषणाओं का बड़ा हिस्सा लागू हुआ है, फिर भी कई सामाजिक योजनाओं का पूर्ण क्रियान्वयन अभी मूल्यांकन मांगता है। संभव है कि वर्ष के मध्य में अनुपूरक बजट आए, जिसमें छूटे क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए जाएं।

इस बजट में आम नागरिक को बेहतर सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार अवसर के रूप में अप्रत्यक्ष लाभ की उम्मीद है। मध्यम वर्ग को बुनियादी सेवाओं के विस्तार से फायदा होगा, पर तात्कालिक आर्थिक राहत सीमित दिखती है।

प्रसंगवश

रेडियो के वो सुहाने दिन बस यादें रह जाती हैं

आज विश्व रेडियो दिवस है। आज से करीब एक सौ बीस साल पहले रेडियो का आविष्कार हुआ था। रेडियो के आविष्कार ने वैश्विक संचार में अभूतपूर्व क्रांति ला दी थी। भारत में आवाज की इस अनोखी दुनिया को एक सौ तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। पिछली करीब एक सदी की शानदार यात्रा में रेडियो, भारत के जन-जन के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। नई संचार तकनीकी के अभ्युदय से पहले रेडियो ने भरोसेमंद जनसंचार के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

तरंगों के द्वारा आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संप्रेषित करने वाले रेडियो नाम के उपकरण को मूल रूप लेने में करीब चार दशक लगे। इस कालखंड में अनेक भौतिकविदों एवं अभियंताओं ने रेडियो के क्रमिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

1864 में एक अंग्रेज गणितीय भौतिकविद् जेम्स क्लर्क मैक्सवेल

ने पहली बार रेडियो तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। 1888 में एक जर्मन भौतिकविद हेनरिश हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों के अस्तित्व को तो स्वीकारा, लेकिन उन्होंने रेडियो तरंगों का दूर संचार में उपयोग की संभावनाओं को नकार दिया था। इसी दरम्यान एक अंग्रेज भौतिकविद् रदरफोर्ड ने तीन चौथाई मील दूरी तक रेडियो संकेत भेजकर हर्ट्ज की अवधारणा को गलत सिद्ध कर दिया। 12 दिसंबर, 1881 में इटली के विद्युत अभियंता मारकोनी ने एक स्थान से भेजी गई आवाज को सुनने और पुनः अपनी आवाज दूसरे स्थान पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन तब रेडियो का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में नहीं आ पाया था। 1904 में विद्युत अभियंता जॉन एम्प्रीज फ्लेमिंग और 1906 में अमेरिका के डी. फारेस्टर ने रेडियो के आविष्कार को आगे बढ़ाया। प्रारंभिक चरण में रेडियो का सबसे अधिक उपयोग समुद्री जहाजों द्वारा किया गया। समुद्री जहाज खतरे या दुर्घटना की स्थिति में एक-दूसरे जहाज या तट से सहायता प्राप्त करने के लिए रेडियो का उपयोग करते थे। 25 दिसंबर, 1906 की रात को अचानक जहाजियों ने तारयंत्र से पहले एक पुरुष की आवाज सुनी फिर उन्हें एक महिला का गीत और वायलन की धुन सुनाई दी, इसी के साथ रेडियो को अपना अस्तित्व मिल गया।

शुरूआती दौर में इंग्लैंड में रेडियो को वायरलेस कहा जाता था। अमेरिका में इसे रेडियो टेलीग्राफ कहते थे। बाद में अमेरिकी लोगों ने इसमें से टेलीग्राफ शब्द को छोड़कर सिर्फ रेडियो कहना शुरू कर दिया। 1920 में वेरिटींग हाउस कंपनी के एक इंजीनियर ने अमरीकी सरकार से रेडियो प्रसारण का लाइसेंस प्राप्त कर पिट्सबर्ग में दुनिया का पहला रेडियो प्रसारण केंद्र स्थापित किया। डॉ. फ्रैंक कॉनराड ने रेडियो में सांध्य कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रारंभ की। 23 फरवरी, 1920 को मारकोनी कंपनी ने चेम्सफोर्ड से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। नवंबर, 1922 में जॉन रीथ के निर्देशन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई। इसके साथ ही इंग्लैंड में रेडियो का नियमित प्रसारण शुरू हो गया।

1923 में रेडियो क्लब, मुंबई ने भारत में रेडियो का पहला प्रसारण शुरू किया। इसी वर्ष कोलकाता समेत अन्य महानगरों में भी रेडियो प्रसारण शुरू हुए। इसके बाद भारत में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का गठन हुआ। कंपनी ने 23 जुलाई, 1927 को मुंबई से रेडियो प्रसारण प्रारंभ कर दिया। 1936 में दिल्ली में रेडियो के केंद्रीय स्टेशन की स्थापना हुई। इसी वर्ष इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन वजूद में आई। 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। 1957 में आकाशवाणी।



प्रेम का उपहार दिया नहीं जा सकता, यह स्वीकार किए जाने की प्रतीक्षा करता है।

–रवींद्रनाथ टैगोर, साहित्यकार

लोकसभा अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव व विपक्ष की राजनीति

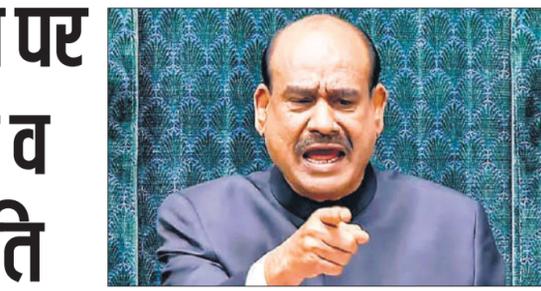


विवेक सक्सेना
अध्यक्ष

वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्षी सांसदों द्वारा पेश अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार के लिए न सही, पर देश की राजनीति के लिए भी चिंताजनक है। तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर इंडिया गठबंधन के करीब 120 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर वाले इस प्रस्ताव पर नौ मार्च को चर्चा होने की संभावना है। संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत अविश्वास प्रस्ताव का यह नोटिस 10 फरवरी को सौंपा गया था। विपक्षी दलों ने बिरला पर सदन में पक्षपात को आरोप लगाते हुए यह प्रस्ताव पेश किया है। विपक्ष ने अध्यक्ष पर लोकसभा में कुछ अप्रत्याशित कार्रवाई करने की बात करते हुए कांग्रेस सदस्यों के खिलाफ झूठे दावे करने का भी आरोप लगाया है।

तृणमूल ने बिरला को दो दिनों की मोहलत देने की पैरोकारी करते हुए हस्ताक्षर से परहेज किया। राहुल गांधी भी हस्ताक्षर नहीं हैं, हालांकि इस संदर्भ में तर्क दिया गया कि लोकसभा में नेता विपक्ष का संवैधानिक पद है और इसलिए संसदीय गरिमा-मर्यादा का ध्यान रखते हुए स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। सपा के कई सांसदों के तो हस्ताक्षर हैं, जिसमें डिंपल यादव भी शामिल हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने हस्ताक्षर से परहेज किया है। स्पीकर बिरला ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को आगे की प्रक्रिया के लिए लोकसभा सचिवालय को भेज दिया है। इस बीच बिरला ने फैसला किया है कि महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया खत्म होने तक सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। विपक्षी दलों के इस नोटिस के साथ ही लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं बोलने देने के विवाद ने सियासी संग्राम का नया रूख अख्तियार कर लिया है।

भारत में गठबंधन राजनीति की प्रकृति को देखते हुए, स्वतंत्रता के बाद से समय-समय पर अविश्वास प्रस्ताव आते रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव एक राजनीतिक संकेत का संकेत होता है, हालांकि ये प्रस्ताव



राजनीतिक चर्चा को जटिल बनाते हैं और विपक्ष को अपनी असहमति दर्ज कराने का अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन क्या ये प्रस्ताव संकेत के समाधान में सहायक होते हैं? जवाहरलाल नेहरू को अविश्वास प्रस्ताव का सामना 1963 में करना पड़ा, जो 1962 के भारत-चीन संघर्ष के बाद की स्थिति थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ 1973 में अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ था। इंदिरा को 1966 से 1977 के बीच अपने कार्यकाल में 12 अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा। राजनीति के आरोपों से घिरे मोरारजी देसाई के खिलाफ 1979 में संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया।

तीन साल के अंतराल के बाद जब इंदिरा गांधी 1980 में सत्ता में लौटीं, तो उन्हें तीन और अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा। 1993 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, हालांकि राव मामूली अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में आई, तो उन्हें लोकसभा का विश्वास खोने के कारण 13 दिनों के भीतर ही इस्तीफा देना पड़ा। वाजपेयी को अगस्त 2003 में जॉर्ज फर्नांडीस ने रक्षा मंत्री नियुक्त करने के लिए एक और अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा।

लोकसभा में दो फरवरी से ही व्यवधान प्रस्ताव नोटिस को आगे की प्रक्रिया के लिए लोकसभा सचिवालय को भेज दिया है। इस बीच बिरला ने फैसला किया है कि महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया खत्म होने तक सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे। विपक्षी दलों के इस नोटिस के साथ ही लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को धन्यवाद प्रस्ताव पर नहीं बोलने देने के विवाद ने सियासी संग्राम का नया रूख अख्तियार कर लिया है।

भारत में गठबंधन राजनीति की प्रकृति को देखते हुए, स्वतंत्रता के बाद से समय-समय पर अविश्वास प्रस्ताव आते रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव एक राजनीतिक संकेत का संकेत होता है, हालांकि ये प्रस्ताव

रहे हैं, पर अब उन्हें ज्यादा गंभीरता से इस प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। अब सत्ता पक्ष या लोकसभा सचिवालय को भी आंकड़ों के आधार पर बताना होगा कि संसद सत्र में विपक्षी दलों के सांसदों को कितना वक्त बोलने के लिए दिया गया है? विपक्षी दलों के सदस्यों को क्या बोलने से रोका गया है? सत्ता पक्ष की खामियों को उठाना विपक्षी सांसदों का काम है, पर इसको दर्ज कराते समय उससे जुड़े प्रामाणिक तथ्य रखना भी उनकी जिम्मेदारी है, हालांकि संविधान का अनुच्छेद 96 अध्यक्ष को सदन में अपना बचाव करने का अवसर देता है। सदन में अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किए जाने पर अध्यक्ष अपना मत डाल सकते हैं, लेकिन बराबर होने की स्थिति में मत नहीं डाल सकते।

संख्या बल में सरकार आगे है और ओम बिरला के पद पर किसी तरह का खतरा फिलहाल नहीं है, लेकिन इसकी बहल से संसद में कड़वाहट और टकराव कहीं अधिक तोखा होगा। इसका असर संसद की कार्यवाही पर भी पड़ सकता है, फिलहाल कहना कठिन है कि इस अविश्वास प्रस्ताव का क्या हश्र होगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कुछ समय पहले विपक्ष ने राज्यसभा के तत्कालीन सभापति जादवीप धनखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहल की थी। संख्या बल धनखड़ के पक्ष में था, लेकिन अंततः वह इतने कमजोर हो गए कि इस्तीफा देना पड़ा।

धनखड़ की तुलना में ओम बिरला को सदन चलाने का ज्यादा अनुभव है। देश में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में बलराम जाखड़ सर्वाधिक नौ वर्ष से ज्यादा समय तक पद पर रहे और उनके बाद ओम बिरला का ही स्थान है। पूर्व में तीन लोकसभा अध्यक्षों जीवी मावलंकर, हुकुम सिंह और बलराम जाखड़ के खिलाफ विपक्ष की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, मगर तीनों ही बार यह खारिज हो गया था। दुर्भाग्य है कि आज की राजनीति में यह निरंतर घट रहा है।



धमकी से लेकर घुटने टेकने तक पाक का ड्रामा



विवेक शुक्ला
पूर्व सूचना अधिकारी
सूडई एंबेसी

पाकिस्तान बीते कई दिनों से कह रहा था कि उसकी टीम भारत के खिलाफ आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप का आगामी 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले मैच का बहिष्कार करेगी। फिर उसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ (आईसीसी) के दबाव के आगे घुटने टेक दिए। अब उसने कहा है कि वह भारत के खिलाफ मैच खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और उससे जुड़े हलकों ने इस मामले पर जिस तरह से शर्तों और दबाव की भाषा अपनाई है, वह न सिर्फ अलत की मर्यादा के खिलाफ है, बल्कि खेतः उसकी विश्वसनीयता को भी कमजोर करती है। आईसीसी द्वारा पाकिस्तान की किसी भी शर्त को न मानना इस बात का संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाएं अब बंदर भभकी और राजनीतिक दबाव की रणनीति से प्रभावित नहीं होने वालीं।

पाकिस्तान लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 'विशेष रियायत' की अपेक्षा करता रहा है। कभी सुरक्षा का हवाला, कभी मेजबानी के अधिकार, तो कभी बहिष्कार की धमकी। इस बार भी कहानी कुछ अलग नहीं थी। भारत के साथ मुकाबले को लेकर पाकिस्तान ने परोक्ष रूप से यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर उसकी शर्तें नहीं मानी गईं, तो वह टूर्नामेंट या मैच से हट सकता है, लेकिन यह धमकी पहले से ही खोखली थी। वैश्विक क्रिकेट को पता है कि भारत-पाक मुकाबला आर्थिक, दर्शक संख्या और प्रसारण तीनों दृष्टि से टूर्नामेंट की रीढ़ होता है और इससे पीछे हटना पाकिस्तान के लिए आत्मघाती कदम होता।

आईसीसी का रुख इस बार स्पष्ट और स्वागतयोग्य रहा। उसने न तो अतिरिक्त

शर्तों को स्वीकार किया और न ही किसी का दबाव झेला। यह संदेश साफ है, क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय नियमों और तय ढांचे के अनुसार चलेगा, न कि किसी एक देश की अस्थिर राजनीति या घरेलू दबावों के हिसाब से। कोलंबो जैसे तटस्थ स्थल पर मैच कराने का निर्णय पहले से निर्धारित व्यवस्थाओं के अनुरूप था और इसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं था। इसके बावजूद पाकिस्तान का शोर-शराबा यह दर्शाता रहा कि वहां खेल प्रशासन अभी भी भावनात्मक प्रतिक्रिया और तात्कालिक राजनीति से बाहर नहीं निकल पाया है।

ऐसी बयानबाजी से न तो सम्मान मिलता है और न ही सहानुभूति। उल्टा, यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की गंभीरता पर सवाल खड़े करती है। खेल कूटनीति में दृढ़ता का मतलब यह नहीं कि हर बात पर अल्टीमेटम दिया जाए; दृढ़ता का अर्थ है नियमों के भीतर रहकर अपने हितों की रक्षा करना। भारत ने 'पूरे घटनाक्रम में अपेक्षाकृत संयम दिखाया। न उकसावे का खाबियाजा भुगतान पड़ा। क्रिकेटर्स में उलझा। यह परिपक्वता इस बात को रेखांकित करती है कि मजबूत पक्ष अक्सर शोर नहीं करता, वह व्यवस्था पर भरोसा करता है। आईसीसी का फैसला उसी तो वह टूर्नामेंट या मैच से हट सकता हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अब किसी एक बोर्ड की धमकियों से नहीं चलती, बल्कि सामूहिक नियमों और पारदर्शिता से संचालित होती है।

पाकिस्तान को आत्मसंयम की जरूरत है। क्या बार-बार विवाद खड़ा कर वह सचमुच अपने खिलाड़ियों और प्रशंसकों का भला कर रहा है? क्या हर बड़े मंच पर नकारात्मक सुर्खियां बटोरना, उसकी

क्रिकेट विरासत के अनुरूप है? खेल का मैदान प्रतिस्पर्धा के लिए होता है, बयानबाजी और धमकियों के लिए नहीं। अगर पाकिस्तान वास्तव में सम्मान और स्थिरता चाहता है, तो उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी। धमकी की जगह प्रदर्शन और राजनीति की जगह खेल भावना को प्राथमिकता देनी होगी।

कोलंबो में होने वाला यह मैच खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का अवसर है। दर्शक क्रिकेट देखना चाहते हैं। आईसीसी ने सही संदेश दिया है कि नियम सर्वोपरि हैं और कोई भी बोर्ड उनसे ऊपर नहीं। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान इस अनुभव से सबक लेगा और भविष्य में ऐसी बंदर भभकी से परहेज करेगा। आखिरकार, क्रिकेट की जीत इसी में है कि खेल खेला जाए, धमकियां नहीं। सबसे दुःखद बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में नुकसान पाकिस्तान के खिलाड़ियों और आम क्रिकेट प्रशंसकों का हुआ। उन्हें एक बार फिर अपने बोर्ड की नाकामी और गैर-जिम्मेदाराना रवैये का खाबियाजा भुगतान पड़ा। क्रिकेटर्स को मैदान पर अपनी मेहनत से पहचान बनानी चाहिए, न कि बोर्ड की बयानबाजी से। अगर पाकिस्तान वास्तव में क्रिकेट का भला चाहता है, तो उसे मेच्योर होना होगा। धमकियों से न सम्मान मिलता है, न सहानुभूति। सम्मान मिलता है प्रदर्शन से, अनुशासन से और नियमों के पालन से। बार-बार पीड़ित बनने की कोशिश करना अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काम नहीं आने वाला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालत उस बच्चे जैसी हो चुकी है जो हर बात पर जमीन पर लोटता है, लेकिन जब मां ध्यान नहीं देती तो खुद ही चुप हो जाता है।

सोशल फोरम

कहानी रोम के राजा की

न्यूमा पोपिलियस जब राजा बना, तो रोम के लोग हैरान थे। यह कैसा राजा था, जो तलवार नहीं उठाता? रोमुलस के जमाने में हर विवाद का फैसला खून से होता था, लेकिन न्यूमा के राज में हर फैसले के लिए 'बातचीत' और 'धर्म' का सहारा लिया जाने लगा। न्यूमा ने सबसे पहले रोम के लोगों को एक नई दिशा दी। उसने कहा,



कलम रंगदार
ब्लॉगर

'हम सिर्फ लड़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमें देवताओं को खुश रखना होगा।' उसने रोम में धर्म की नींव रखी। उसने पुजारियों का एक समूह बनाया जिसे 'पोटिफेक्स' (Pontifex) कहा जाता था। इनका काम था देवताओं और इंसानों के बीच पुल का काम करना। आज भी 'पोटिफ' शब्द का इस्तेमाल कैथोलिक चर्च के प्रमुख (पोप) के लिए किया जाता है, जिसकी जड़ें यहीं से जुड़ी हैं। न्यूमा ने रोम के लिए एक और खास चीज बनाई- 'वेस्टल वर्जिन्स' (Vestal Virgins)। ये कुंआरी लड़कियां थीं, जो देवी 'वेस्टा' (Vesta) के मंदिर में पवित्र आग की रक्षा करती थीं। रोमनों का मानना था कि जब तक यह आग जलती रहेगी, रोम सुरक्षित रहेगा। अगर आग बुझ गई, तो रोम का विनाश तय है। इन लड़कियों को समाज में बहुत ऊंचा दर्जा मिलता था, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत सख्त नियमों से बंधी थी। अगर उनसे कोई गलती हो जाती, तो सजा मौत से भी बदतर होती थी। उन्हें जिंदा दफना दिया जाता था, लेकिन न्यूमा का सबसे बड़ा योगदान कुछ और था। उस समय रोम का कैलेंडर बहुत अजीब था। साल में सिर्फ 10 महीने होते थे और सर्दियां कैलेंडर से गायब थीं। खेती-बाड़ी का कोई हिसाब नहीं था। न्यूमा ने देखा कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है। उसने चांद की चाल को देखा और हिसाब लगाया। उसने साल में दो नए महीने जोड़े- 'जेनुअरियस' (Januarius) और 'फेब्रुअरियस' (Februarius)। जी हां, जनवरी और फरवरी।

जेनुअरियस, जो 'जेनस' देवता के नाम पर था- दो चेहरों वाले देवता, जो एक साथ पीछे (अतीत) और आगे (भविष्य) देख सकते थे और फेब्रुअरियस, जो शुद्धिकरण का महीना था। न्यूमा ने साल को 355 दिनों का बना दिया (जो बाद में और सुधरा)। उसने दिनों को 'फास्टि' (Fasti-काम करने के दिन) और 'नेफास्टि' (Nefasti-छुट्टी/धार्मिक दिन) में बांटा। आज हम जो छुट्टी मनाते हैं, उसकी शुरुआत कहीं न कहीं न्यूमा की इसी सोच से हुई थी। न्यूमा ने रोम की सीमाओं को भी बदला, लेकिन युद्ध से नहीं। उसने खेतों की सीमाओं पर 'टर्मिनस' देवता की मूर्तियां लगाव दीं।

-फेसबुक वॉल से

सामयिकी



बेवजह के विवादों से प्रचार पार्टी फिल्में

फिल्मों को एक सुनियोजित रणनीति के तहत विवादों में परोसना और फिर उस पर विंटंडा खड़ा करके प्रचार पाना, अब कोई नयी बात नहीं रह गई है। दरअसल फिल्मकारों ने आस्था, भावना और मूल्यों के खिलाफ फिल्में बनाकर बेशुमार धन इकठ्ठा करने का एक चलन बना लिया है। भले ही इससे किसी जाति, धर्म आस्था और भावना को चोट क्यों न पहुंचती हो। ऐसी ही एक फिल्म 'घूसखोर पंडत' भी रुपहले पदें पर आने को तैयार है, जिसके टाइटल को लेकर विंटंडा उठ खड़ा हुआ है। देश के विभिन्न हिस्सों में इस फिल्म के टाइटल को लेकर विरोध-प्रदर्शन जारी है।

खुद फिल्म निर्माता संघ (एफएमसी) ने इस फिल्म को लेकर निर्माता नीरज पांडेय को नोटिस जारी किया है और कहा है कि फिल्म निर्माता ने नियमों के अनुसार शीर्षक के लिए अनिवार्य अनुमति प्राप्त नहीं की है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि फिल्म निर्माता ने जानबूझकर फिल्म को विवादों की परिधि में लाकर प्रचार पाने के लिए यह सारा उपक्रम किया था। अब जब विवाद चरम पर पहुंच गया है और फिल्म भी खूब प्रचार पा ली है, तो फिल्म निर्माता नीरज पांडेय और अभिनेता मनोज वाजपेई द्वारा सफाई दी जा रही है कि उनका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। वे अब विवादित प्रचार सामग्री को हटाने की भी दुहाई दे रहे हैं। सच तो यह है कि फिल्म निर्माता ने अपनी

फिल्म को विवादों के जरिए जितना प्रचार पाना चाहा था, उतना पा लिया। उनका मकसद पूरा हुआ। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे फिल्म निर्माताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, जो धन कमाने के निमित्त इस किस्म का धिनीने हथकंडा अपनाते हैं। कहना मुश्किल है, इसलिए इस किस्म के इस तरह के हथकंडे बार-बार अपनाया जा रहे हैं। अभी गत वर्ष पहले अनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म 'उड़ता पंजाब' विवादों के केंद्र में रहा। इस फिल्म का कथानक पंजाब में नशाखोरी के इर्द-गिर्द गढ़ा-बुना गया था। इसके कुछ दृश्यों और डॉयलाग को लेकर बवाल मचा। बेशक एक फिल्मकार को अधिकार है कि वह फिल्मों का निर्माण करे, लेकिन उसका उत्तरदायित्व भी है कि वह धर्म, संस्कृति और इतिहास को पढ़े-समझे और उसकी वास्तविकताओं एवं भावनाओं का ख्याल रखकर फिल्मों का निर्माण करे। उसे ध्यान रखना चाहिए कि फिल्मों के जरिए समाज के नैसर्गिक स्वभाव और आस्था पर बुरा असर न पड़े।

फिल्मकारों ने यह धारणा पाल रखी है कि फिल्मों पर जितना अधिक बवाल होगा उनकी कमाई में उतना ही इजाफा होगा। बेशक एक स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज में कहने-सुनने, लिखने-पढ़ने और दिखने-दिखाने की आजादी होनी चाहिए। विशेष रूप से कला के क्षेत्र में तो और भी अधिक, क्योंकि समाज में जो कुछ भी घटित होता है, उसे कला के जरिए पदें पर उकेरा जाता है, लेकिन कला और अभिव्यक्ति की आड़ लेकर अरबों कमाने की लालच में धर्म और आस्था पर प्रहार कहां तक उचित है?

एक वक्त था जब फिल्मों का कथानक समाज और राष्ट्र के जीवन में घेतना का संचार करता था। युवाओं को प्रेरणा देता था। आजादी की लड़ाई को धार देने से लेकर समाज के गुणसूत्र को बदलने-रचने में फिल्मों की अहम भूमिका रही है। आज भी कुछ फिल्में सामाजिक व राष्ट्रीय सरोकारों को उकेरती दिख जाती हैं, लेकिन अधिकांश फिल्में वास्तविकताओं से दूर अतिरंजित और फूहड़पन से लैस होती हैं। अगर किसी फिल्म के शीर्षक, कथानक या डॉयलाग से समाज का कोई वर्ग आहत होता है, तो संसर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह इसे पास न करे।

ऐसे हुआ मोबाइल का आविष्कार

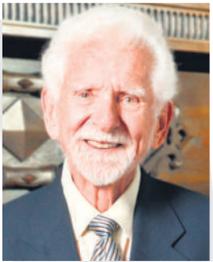
1970 के दशक में अमेरिका की प्रतिष्ठित शोध संस्था बेल लैब्स में एक ऐसी अवधारणा पर प्रयोग शुरू हुए, जिसने भविष्य की संचार दुनिया की दिशा ही बदल दी। पूरे देश को घटभुजाकार विशाल नेटवर्क से ढक दिया जाए। प्रत्येक सेल में एक बेस स्टेशन होगा, जो रेडियो आवृत्तियों के माध्यम से मोबाइल फोन से संदेश भेजेगा और प्राप्त करेगा। तकनीकी चतुराई यह थी कि दो आसन्न सेल अलग-अलग आवृत्तियों पर काम करें, ताकि सिग्नल हस्तक्षेप की समस्या न आए।

ये बेस स्टेशन रेडियो सिग्नलों को मुख्य दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ते थे और जैसे ही कोई उपयोगकर्ता एक सेल से दूसरे सेल में प्रवेश करता, उसका फोन स्वतः ही फ्रीक्वेंसी बदल लेता। इस निर्बाध हैंडऑफ की कल्पना उस समय क्रांतिकारी थी। 1970 के दशक के अंत तक बेल लैब्स का एडवांस्ड मोबाइल फोन सिस्टम (एएमपीएस) छोटे पैमाने पर सफलतापूर्वक चालू हो चुका था, जिसने व्यावहारिक सेलुलर नेटवर्क का रास्ता खोल दिया। इसी दौर में मोटोरोला में कार्यरत इंजीनियर मार्टिन कूपर एक अलग ही सपने को साकार करने में जुटे थे। वे टीवी सीरीज स्टार ट्रेक के कम्प्यूनिफेटर से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने एक ऐसा पोर्टेबल फोन बनाने का लक्ष्य तय कर लिया, जिसे हाथ में लेकर कहीं भी बात की जा सके। कूपर की टीम ने पहला हैंडहेल्ड मोबाइल फोन विकसित किया, जो बेल के एएमपीएस नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता था।

1984 में मोटोरोला ने इस सपने को 'डायनाटैक' के रूप में बाजार में उतारा। एक किलोग्राम से अधिक वजन वाले इस फोन को प्यार से 'द ब्रिक' कहा गया। कीमत आज के हिसाब से लगभग 10,000 डॉलर थी, इसलिए यह आम लोगों को पहुंच से बाहर रहा, लेकिन अमीर फाइनेंसरी और उद्योगियों के बीच यह जल्द ही स्टेटस सिंबल बन गया। 1987 की फिल्म वॉल स्ट्रीट ने डायनाटैक को धन और लालच के प्रतीक के रूप में अमर कर दिया, जब माइकल डगलस द्वारा निभाया गया गॉर्डन गेको समुद्र तट पर टहलते हुए इसी फोन पर बात करता नजर आया। यहीं से मोबाइल फोन सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि आधुनिक शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक भी बन गया।

वैज्ञानिक के बारे में

मार्टिन कूपर को भले ही दुनिया मोबाइल फोन के जनक के रूप में जानती हो, लेकिन उनकी निजी जिंदगी उतनी ही संतुलित, प्रेरक और मानवीय रही है। उनका जन्म 26 दिसंबर 1928 को अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ। एक यहूदी प्रवासी परिवार में पले-बढ़े कूपर ने बचपन से ही पढ़ाई और तकनीक में गहरी रुचि दिखाई। उनकी निजी जिंदगी में सबसे अहम भूमिका उनकी पत्नी आर्लीन हैरिस की रही। आर्लीन स्वयं भी एक प्रतिष्ठित इंजीनियर और उद्यमी हैं और उन्हें वायरलेस टेलीफोन सिस्टम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। मार्टिन कूपर का निजी जीवन दिखावे से दूर रहा। वे कभी भी केवल प्रसिद्धि या धन के पीछे नहीं भागे। उनका मानना था कि तकनीक का उद्देश्य मनुष्य को स्वतंत्र बनाना है, न कि उसे मशीनों पर निर्भर करना। यही सोच उनकी जीवनशैली में भी झलकती है, सादा जीवन, गहरी सोच और भविष्य को लेकर आशावादी दृष्टिकोण।



रही। आर्लीन स्वयं भी एक प्रतिष्ठित इंजीनियर और उद्यमी हैं और उन्हें वायरलेस टेलीफोन सिस्टम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। मार्टिन कूपर का निजी जीवन दिखावे से दूर रहा। वे कभी भी केवल प्रसिद्धि या धन के पीछे नहीं भागे। उनका मानना था कि तकनीक का उद्देश्य मनुष्य को स्वतंत्र बनाना है, न कि उसे मशीनों पर निर्भर करना। यही सोच उनकी जीवनशैली में भी झलकती है, सादा जीवन, गहरी सोच और भविष्य को लेकर आशावादी दृष्टिकोण।

मरीन लाइफ



सी पेन: समुद्र की गहराइयों में खड़ी एक जीवित कलम

सी पेन (Sea Pen) एक अत्यंत रोचक और कम चर्चित समुद्री जीव है, जो देखने में जितना साधारण लगता है, व्यवहार में उतना ही अनोखा है। यह जीव आमतौर पर एक ही स्थान पर स्थिर रहता है और बहुत अधिक हिलता-डुलता नहीं है। अपनी संरचना और जैविक बनावट के कारण यह समुद्री एनीमोन्स और कोरल से काफी मिलता-जुलता है। एनीमोन्स वही जीव है, जिनका नाम फिल्म फाईडिंग नीमो में नीमो ठीक से नहीं बोल पाता था। सी पेन का नाम उसके आकार से ही पड़ा है। यह बिल्कुल उस पारंपरिक कलम की तरह दिखता है, जिससे कभी लोग लिखते थे। नीचे एक मोटा आधार और ऊपर पंखनुमा फैलाव। वास्तव में सी पेन कोई एकल जीव नहीं होता, बल्कि यह सैकड़ों-हजारों सूक्ष्म जीवों (पॉलीप्स) की एक कॉलोनी होती है, जो मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। इसका निचला हिस्सा समुद्र की नरम मिट्टी में धंसा रहता है, जिससे इसे स्थिरता मिलती है। सी पेन दुनियाभर के उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण जलक्षेत्रों

में पाए जाते हैं। ये आमतौर पर समुद्र की गहराइयों में रहते हैं, जहां रोशनी कम और तापमान स्थिर होता है। हालांकि ये पूरी तरह समुद्र तल से चिपके नहीं रहते। जरूरत पड़ने पर ये अपना स्थान बदल सकते हैं और उन क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, जहां जलधाराएं तेज होती हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि तेज धारा के साथ प्लवक, जो इनका मुख्य और पसंदीदा भोजन है। सी पेन के पास पहुंच जाता है।

सी पेन की एक और खास विशेषता इसकी जैवदीप्ति है। कुछ प्रजातियां खतरे की स्थिति में हल्की रोशनी उत्पन्न करती हैं, जो समुद्र की अंधेरी गहराइयों में किसी जादुई दृश्य जैसा प्रतीत होती है। यह रोशनी शिकारियों को भ्रमित करने या डराने के काम आती है। कुल मिलाकर, सी पेन समुद्री दुनिया का एक शांत-स्थिर, लेकिन बेहद रहस्यमय जीव है, जो यह साबित करता है कि समुद्र की गहराइयों में आज भी प्रकृति के अनगिनत चमत्कार छिपे हुए हैं।

महासागरों की रहस्यमयी दुनिया

भूमंडल के 70 प्रतिशत भाग पर जलमंडल और 30 प्रतिशत भाग पर स्थल है। संपूर्ण भूमंडल का क्षेत्रफल 51.6 करोड़ वर्ग किमी है। इसमें 36.17 करोड़ वर्ग किमी पर जल और 14.89 करोड़ वर्ग किमी पर स्थल का विस्तार पाया जाता है। इस प्रकार महासागरों की दुनिया पृथ्वी से काफी बड़ी है। जलमंडल के अंतर्गत महासागर, सागर, खाड़ियां आदि सम्मिलित हैं। महासागरों में इतनी विशाल जलराशि है कि यदि इसे धरातल पर समतल रूप में फैला दिया जाए, तो पूरी पृथ्वी पर 4.8 किमी गहरा सागर लहराने लगेगा। महासागरों की तली धरातल की भांति ऊंची-नीची है। महासागर इतने गहरे हैं कि उसमें हिमालय जैसे अनेक विशाल पर्वत समा सकते हैं। धरती की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है, जबकि प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त की गहराई 11776 मीटर है। इस प्रकार महासागरों की दुनिया आज भी मानव के लिए एक अनबूझ पहेली बनी हुई है।

समुद्र केवल जलराशि के ही विशाल स्रोत नहीं, बल्कि यह खनिज सम्पदा, नमक, रत्न, मृगा, मोती, मछलियां, शंख, घोघा, सीप के भी विशाल भंडार हैं और मानव के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। यह जैविक संपदा के भी भंडार हैं। हमारे महासागरों और सागरों में मौजूद अपार जल संपदा के कारण ही पृथ्वी को 'वाटर प्लेनेट' भी कहा जाता है। जल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन है। समुद्रों की महत्ता को बताने और उसके संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। समुद्र के जल का बढ़ता तापमान पृथ्वी और मानवता के लिए शूभ संकेत नहीं है। आज पृथ्वी ही नहीं समुद्र के लिए भी सबसे बड़ा खतरा प्लास्टिक वेस्ट है। प्लास्टिक वेस्ट और समुद्र में हो रहे अंधाधुंध परमाणु विस्फोटों के कारण समुद्र का पानी उबल रहा है। इस वजह से तल में मौजूद समुद्री वनस्पतियां तेजी से खत्म होती जा रही हैं। यू.के. सरकार द्वारा हाल में जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली वेबसाइट 'इको वॉच' के अनुसार समुद्र में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण की वजह से प्रत्येक वर्ष 10 लाख से ज्यादा पक्षी एवं एक लाख से ज्यादा समुद्री जीवों की मौत हो रही है। पानी का तापमान बढ़ने से समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसके भयानक समुद्री तूफान आने की आशंका बनी हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार हम सब स्वांस लेने के लिए जिस ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, उसकी दस फीसदी मात्रा हमें समुद्र से ही प्राप्त होती है। समुद्र में मौजूद सूक्ष्म बैक्टीरिया



ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, जो पृथ्वी पर मौजूद जीवन के लिए बेहद जरूरी है। वैज्ञानिकों को अध्ययन में पता चला है कि समुद्र में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण की वजह से ये बैक्टीरिया पनप नहीं पा रहे हैं। इससे समुद्र में ऑक्सीजन की मात्रा भी लगातार घट रही है और पशु-पक्षियों समेत इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन 'वर्ल्ड वाइड फंड' द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक पृथ्वी पर प्लास्टिक प्रदूषण दोगुना हो जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र में 1950 से 2016 के बीच 66 वर्षों में जितना प्लास्टिक जमा हुआ है इतना केवल आगामी 10 सालों में जमा हो जाएगा। इससे महासागरों में प्लास्टिक कचरा 30 करोड़ टन तक पहुंच सकता है। समुद्र में 2030 तक प्लास्टिक दहन पर कार्बन

टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में मिल जाता है। 2050 तक समुद्र में मछली से ज्यादा प्लास्टिक के टुकड़े होने का अनुमान है। प्लास्टिक के मलबे से समुद्री जीव बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। कछुओं की दम घुटने से मौत हो रही है और व्हेल इसके जहर का शिकार हो रही है। प्रशांत महासागर में 'दा ग्रेट पैसिफिक गार्बेज बैच' समुद्र में कचरे का सबसे बड़ा ठिकाना है। यहां पर 80 हजार टन से ज्यादा प्लास्टिक जमा हो गया है। इस प्रकार प्लास्टिक वेस्ट समुद्र और समुद्री जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। समुद्र के जल का तापमान निरंतर बढ़ रहा है, जिससे समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही हैं। समुद्री तूफानों के आने की आशंका बनी रहती है। समुद्र मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। विश्व के लगभग एक तिहाई लोगों का मुख्य भोजन समुद्री मछलियां हैं। जापान, नावे, फिनलैंड, आयरलैंड तथा भारत के समुद्र तटीय प्रदेश अपनी आजीविका के लिए समुद्र तटीय प्रदेश अपनी आजीविका के लिए समुद्र पर ही निर्भर हैं। विश्व का 80 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। समुद्र, पृथ्वी पर होने वाली वर्षा का स्रोत है। समुद्र के जल से ही वाष्प बनती है, जिससे पृथ्वी पर वर्षा होती है। इस प्रकार समुद्र पृथ्वी पर जीवन का आधार है। समुद्र के जल में बढ़ता प्रदूषण पृथ्वी और मानवता के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा है। प्लास्टिक वेस्ट को समुद्र में जाने से रोककर ही हम समुद्र और पृथ्वी के अस्तित्व को बनाए रख सकते हैं।



सुरेश बाबू मिश्रा
लेखक



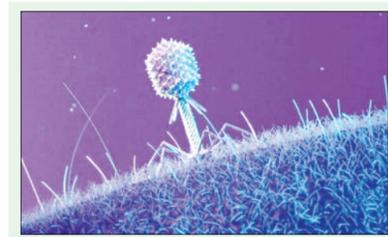
अंतरिक्ष में वायरस और बैक्टीरिया की जंग

नए रहस्य

वे बदलाव पृथ्वी से अलग 'ट्रेजेवटरी' (राह) पर होते हैं यानी स्पेस माइक्रोबियल इकोसिस्टम को नए तरीके से आकार देता है। उदाहरण के लिए स्पेस के फेज पृथ्वी पर दवा-प्रतिरोधी ई. कोलाई (जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पैदा करते हैं) के खिलाफ ज्यादा प्रभावी साबित हुए। इससे पता चलता है कि माइक्रोबिटी बैक्टीरिया-फेज की को-इवोल्यूशन (सह-विकास) को रोककर देती है, जो सूक्ष्मजीवों के अनुकूलन के बुनियादी सिद्धांतों को चुनौती देती है। यह रिसर्च पहली बार आईएसएस पर फेज-बैक्टीरिया की लंबी अवधि की डायनामिक्स को ट्रैक करती है, जो पहले की जमीन आधारित सिमुलेशंस से आगे जाती है।

एक नए अध्ययन में पाया गया कि पृथ्वी पर रहने वाले बैक्टीरिया-संक्रमित करने वाले वायरस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की लगभग वजन-रहित 'माइक्रोग्रेविटी' स्थिति में भी अपने ई. कोलाई होस्ट को संक्रमित करने में सफल रहे, लेकिन वायरस-बैक्टीरिया की आपसी लड़ाई पृथ्वी से काफी अलग थी। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन-मैडिसन के फिलहस और उनके साथियों के नतीजे बीती 13 जनवरी, 2026 को ओपन-एक्सेस जर्नल 'एलओएस बायोलॉजी' में प्रकाशित हुए। एक प्रयोग के दौरान जब वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भेजा, तो ये सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा नहीं किया।

माइक्रोग्रेविटी (कम गुरुत्वाकर्षण) में संक्रमण तो हुआ, लेकिन समय के साथ वायरस और बैक्टीरिया दोनों ही अलग-अलग तरीके से विकसित हुए। जेनेटिक बदलाव आए, जिनसे वायरस बैक्टीरिया से चिपकने का तरीका बदल गया और बैक्टीरिया ने खुद को बचाने के नए हथियार विकसित कर लिए। ये खोज फेज थेरेपी (वायरस से बैक्टीरिया को मारने की तकनीक) को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, खासकर दवा-प्रतिरोधी संक्रमणों के खिलाफ।



एक पृथ्वी, तो दूसरा अंतरिक्ष में

फेज यानी वो वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं और उनके होस्ट के बीच की लड़ाई सूक्ष्मजीवीय पारिस्थितिकी (माइक्रोबियल इकोसिस्टम) में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे अक्सर एक 'एवोल्यूशनरी आर्मर्स रेस' (विकास की हथियार दौड़) कहा जाता है, जहां बैक्टीरिया वायरस से बचने के लिए डिफेंस सिस्टम बनाते हैं और वायरस उन डिफेंस को तोड़ने के नए तरीके ईजाद करते हैं। पृथ्वी पर इस लड़ाई का अध्ययन हो चुका है, लेकिन माइक्रोग्रेविटी बैक्टीरिया की फिजियोलॉजी (शारीर क्रिया) और वायरस-बैक्टीरिया के टकराव की भौतिकी को बदल देती है, जिससे सामान्य इंटरैक्शन बिगड़ जाते हैं, अब पता चला है। फिर भी माइक्रोग्रेविटी में फेज-बैक्टीरिया की डायनामिक्स पर बहुत कम अध्ययन हुए हैं। इस कमी को दूर करने के लिए हस और उनके साथियों ने दो सेट बैक्टीरियल ई. कोलाई सैम्पल्स लिए, जिनमें टी-7 नाम का फेज संक्रमित किया गया, एक सेट पृथ्वी पर रखा और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर।

■ **संक्रमण की गति में बदलाव**- शुरुआत में संक्रमण धीमा हुआ, क्योंकि माइक्रोग्रेविटी बैक्टीरिया की फिजियोलॉजी (शारीर क्रिया) और फेज-बैक्टीरिया के टकराव की भौतिकी को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण की कमी से बैक्टीरिया की कोशिकाएं अलग-अलग तरीके से इकट्ठा होती हैं, जिससे फेज का लगाव (अटैचमेंट) मुश्किल हो जाता है।
■ **आनुवंशिक उत्परिवर्तन**- अंतरिक्ष के फेज में ऐसे उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन्स जमा हुए, जो उनकी संक्रमण क्षमता या बैक्टीरियल संग्राहक यानी रिसेप्टर्स से चिपकने की ताकत बढ़ाते हैं। वहीं, बैक्टीरिया ने बचाव और अंतरिक्ष में जीवित रहने के नए आनुवंशिक बदलाव विकसित किए। डीएनए म्यूटेशनल स्कैनिंग तकनीक से पता चला कि फेज का रिसेप्टर बाईंडिंग प्रोटीन (आरबीपी) स्पेस से अलग तरीके से बदलता है।
■ **अंतरिक्ष अन्वेषण में उपयोगिता**- अंतरिक्ष अन्वेषण में सूक्ष्मजीव एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वे अंतरिक्ष यान (स्पेसक्राफ्ट) को दूषित कर सकते हैं और कू को सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। यह रिसर्च इन रहस्यों से कई फायदे दे सकती है।
■ **कू हेल्थ प्रोटेक्शन**- लॉन्ग-टर्म मिशन (जैसे मंगल यात्रा) में माइक्रोग्रेविटी बैक्टीरिया को ज्यादा विरुलेंट (खतरनाक) बना सकती है, लेकिन फेज उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। अध्ययन दिखाता है

कि स्पेस में फेज बैक्टीरिया के साथ अनुकूलित होकर नए बचाव तरीके ईजाद करते हैं, जो स्पेस में माइक्रोबियल कंट्रोल के लिए नए टूल दे सकता है।
■ **ग्रहय सुरक्षा**- स्पेस में सूक्ष्मजीवों के अनुकूलन को समझने से हम अन्य ग्रहों (जैसे मंगल) पर पृथ्वी के जीवों को फैलाने से रोक सकते हैं। फेज रिसर्च से पता चलता है कि माइक्रोग्रेविटी बैक्टीरिया के जीनोम में बदलाव लाती है, जो स्पेसक्राफ्ट स्ट्रलाइजेशन के नए तरीके सुझा सकती है। भविष्य में यह ज्ञान हमारी ग्रहय सुरक्षा (प्लेनेटरी प्रोटेक्शन) के काम आएगा।
■ **भविष्य के मिशन**- नासा और ईएसए जैसे संगठन अंतरिक्ष में माइक्रोबायोलॉजी को समझने के लिए आईएसएस का इस्तेमाल कर रहे हैं। फेज रिसर्च अर्टेमिस या मंगल मिशन में कू को बैक्टीरियल संक्रमणों से बचाने के लिए फेज-आधारित थेरेपी विकसित करने में मदद करेगी। कुल मिलाकर, ये रहस्य अंतरिक्ष अन्वेषण को सुरक्षित और टिकाऊ बनाते हैं, क्योंकि सूक्ष्मजीव अंतरिक्ष में अप्रत्याशित तरीके से व्यवहार करते हैं।
■ **मानव स्वास्थ्य के लिए उपयोगिता**- पृथ्वी पर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक वैश्विक संकट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, 2050 तक इससे 10 मिलियन मौतें हो सकती हैं। यह शोध मानव स्वास्थ्य में क्रांति ला सकता है।

आइए जानते हैं
बेहतर फेज थेरेपी
स्पेस में हुए म्यूटेशन्स से फेज को इंजीनियर करके दवा-प्रतिरोधी बैक्टीरिया (जैसे एमडीआर ई. कोलाई) के खिलाफ ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। अध्ययन में पाया गया कि अंतरिक्ष के फेज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (यूटीआई) पैदा करने वाले स्ट्रेन्स को बेहतर तरीके से मारते हैं। इससे फेज थेरेपी को विलिनकल स्तर पर मजबूत किया जा सकता है, जो एंटीबायोटिक्स का विकल्प है।



नई अंतर्दृष्टि
माइक्रोग्रेविटी बैक्टीरिया की प्रतिरक्षा (इम्यूनिटी) और फेज की इवोल्यूशन को अलग तरीके से प्रभावित करती है, जो पृथ्वी पर संक्रमणों के माॉडल को सुधार सकती है।
व्यापक प्रभाव
यह रिसर्च जैव विज्ञाना उन्नति को बढ़ावा देगी, जैसे कैसर थेरेपी या वैक्सीन विकास में फेज का इस्तेमाल। शोधकर्ताओं का कहना है कि अंतरिक्ष-प्रेरित बदलावों से पृथ्वी पर 'फार सुपीरियर एंटीबिटी' वाले फेज बनाए जा सकते हैं। इससे अस्पतालों में सुपरबस से लड़ना आसान हो सकता है।

वैज्ञानिक फैक्ट



लेजर, पानी और भौतिकी का जादू

यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन लेजर किरण वास्तव में पानी की धारा के भीतर 'फंस' सकती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि भौतिकी की एक प्रसिद्ध और रोचक घटना है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection) कहा जाता है। यही सिद्धांत आज फाइबर ऑप्टिक्स और हाई-स्पीड इंटरनेट की नींव भी है। इस घटना को समझाने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक सरल, लेकिन प्रभावशाली प्रयोग किया। उन्होंने साफ पानी से भरे एक टैंक के एक सिरे पर लेजर लगाया। टैंक के दूसरे सिरे पर एक छोटा सा छेद बनाया गया, जिससे पानी बाहर निकलकर बाल्टी में गिर रहा था। जब लेजर किरण को बहती हुई पानी की धारा पर डाला गया, तो आश्चर्यजनक रूप से रोशनी पानी के बाहर नहीं फैली, बल्कि धारा के साथ-साथ मुड़ती चली गई। असल में, पानी और हवा के बीच अपवर्तनांक (Refractive Index) का अंतर इस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होता है। पानी में मौजूद भारी कण लेजर की गति को धीमा कर देते हैं। जब लेजर किरण एक विशेष कोण पर पानी और हवा की सीमा से टकराती है, तो वह बाहर निकलने के बजाय बार-बार अंदर ही परावर्तित होती रहती है। इसी कारण लेजर किरण पानी की धारा के भीतर 'केद' हो जाती है। इस प्रयोग के दौरान बहता हुआ पानी लाल रंग के चमकदार झरने जैसा दिखाई देता है, क्योंकि लेजर की लाल रोशनी पूरी धारा में फैल जाती है। खास बात यह है कि जब पानी का प्रवाह धीरे-धीरे कम किया गया, तब भी लेजर किरण धारा के भीतर बनी रही। जैसे ही पानी पूरी तरह बंद हुआ, लेजर किरण भी अचानक गायब हो गई। यह प्रयोग न केवल देखने में बेहद आकर्षक है, बल्कि हमें यह भी समझाता है कि आधुनिक संचार तकनीक, जैसे ऑप्टिकल फाइबर असल में प्रकाश को 'फंसाकर' ही सूचना को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है।

बाजार	संसेक्स ↓	निफ्टी ↓
बंद हुआ	83,674.92	25,807.20
गिरावट	558.72	146.65
प्रतिशत में	0.66	0.57

सोना 1,60,900 प्रति 10 ग्राम
चांदी 2,68,500 प्रति किलो

अमृत विचार

लखनऊ, शुक्रवार, 13 फरवरी 2026

www.amritvichar.com

कारोबार

बिजनेस ब्रीफ

आरसीएफ फॉस्फोरिक एसिड संयंत्र के लिए 865 करोड़ करेगी निवेश

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी राष्ट्रीय कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) महाराष्ट्र में फॉस्फोरिक एसिड संयंत्र लगाने के लिए 865 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। गुरुवार को एक नियामकीय सूचना में, कंपनी ने बताया कि उसके निदेशक मंडल (बोर्ड) ने महाराष्ट्र के अलीबाग में थाई युनिट में 300 टन प्रति दिन की प्रस्तावित क्षमता वाला एक नया फॉस्फोरिक एसिड संयंत्र लगाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस संयंत्र को लगाने के लिए कुल 865.25 करोड़ का निवेश जरूरी है और इसे ऋण और इक्विटी के जरिये पूरा किया जाएगा। आरसीएफ देश की सबसे बड़ी उर्वरक बनाने वाली कंपनियों में से एक है।

सेल का दो करोड़ टन बिक्री का लक्ष्य

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 2025-26 में दो करोड़ टन बिक्री दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। 2024-25 में यह 1.79 करोड़ टन रही थी। कंपनी भविष्य के विस्तार की तैयारी के तहत ऋण घटाने, लागत नियंत्रण और परिचालन दक्षता बढ़ाने पर जोर दे रही है। सेल के निदेशक (वित्त) डॉ. एके पंडा ने बताया कि अप्रैल-दिसंबर 2025 की नौ महीने की अवधि में कंपनी ने 5,000 करोड़ का ऋण चुकाया है। 31 दिसंबर 2025 तक कुल ऋण 24,852 करोड़ था जिसमें जनवरी 2026 में 2,000 करोड़ की और कमी आई। परिचालन दक्षता, लागत अनुकूलन और मजबूत कोष प्रबंधन आदि से वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और विकास निवेशों के लिए अवसर बने हैं।

एचयूएल का लाभ दोगुना होकर 6,603 करोड़

नई दिल्ली। हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) का एकीकृत लाभ सालाना आधार पर दोगुना होकर 6,603 करोड़ तक पहुंच गया। एचयूएल ने गुरुवार को शेयर बाजार को बताया कि कंपनी ने 2025-26 को अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में अपने असेसमेंट के अनुसार कुल वॉल्यूमेट्रिक बिक्री में 12% तक वृद्धि दर्ज की। नई श्रम संधिओं के क्रियान्वयन से तिमाही के दौरान 576 करोड़ रुपये के असाधारण गम (हॉन) दर्ज किए। कंपनी ने कहा कि शुद्ध लाभ 6,603 करोड़ रुपये रहे, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 121 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अधिक आयकर संग्रह मध्य वर्ग के आगे बढ़ने का सबूत

उच्च सदन में केंद्रीय वित्त मंत्री बोलीं- देश मजबूत वृद्धि के साथ निम्न बेरोजगारी दर के रास्ते पर

● सीतारमण ने कहा- मध्य वर्ग का दायरा बढ़ रहा है, उसे दबाया नहीं जा रहा

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि देश मजबूत वृद्धि के साथ निम्न बेरोजगारी दर के रास्ते पर है। रोजगार के बिना वृद्धि (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) संग्रह सरकार की कहानी थी, वर्तमान सरकार की नहीं। सीतारमण ने राज्यसभा में 2026-27 के बजट पर चर्चा का जवाब देते कहा कि मध्य वर्ग का दायरा बढ़ रहा है, उसे दबाया नहीं जा रहा। व्यक्तिगत आयकर का संग्रह का कॉरपोरेट कर से अधिक होने का मतलब यह नहीं है कि मध्य वर्ग पर बोझ डाला जा रहा है बल्कि यह मध्य वर्ग के आगे बढ़ने का सबूत है।

सीतारमण ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना अर्थव्यवस्था को मूत बनाने वाले उनके बयान को नकारात्मक करार देते हुए कहा कि वह देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, जो



बजट पर चर्चा का जवाब देतीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।

वास्तव में भारत के वृद्धि में अपना योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि बजट में उठाए गए कदम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार के संकल्प को बताते हैं। कल्याणकारी योजनाओं के लिए राशि में कटौती को लेकर विपक्ष की आलोचना पर सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार की राशि कोई मुफ्त भंडार नहीं है, जिसका मनमाने ढंग से उपयोग किया जा सके, बल्कि यह देश के प्रत्येक नागरिक का मेहनत

से कमाया हुआ योगदान है, जिसे बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। राशि तभी जारी की जाती है जब इसकी आवश्यकता होती है, न कि खर्च बढ़ाने के लिए।

मंत्री ने कहा कि सरकारी खर्च प्रक्रिया में अब पूर्ण पारदर्शिता है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भारत में मुद्रास्फीति कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है। उन्होंने कहा कि मैं इस तथ्य रखना चाहती हूँ कि वृद्धि दर उच्च होने के

आज कर योग्य आय वालों की संख्या अधिक

सीतारमण ने कहा कि आज कर योग्य आय वाले लोगों की संख्या अधिक है। अब संगठित क्षेत्र में अधिक आय दिखाई देती है। उन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था अब केवल कुछ गिने-चुने वर्ग तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें भागीदारी बढ़ी है। मध्यम वर्ग का दायरा बढ़ रहा है। 2013-14 और 2024-25 के बीच, करदाताओं की संख्या, यानी रिटर्न दाखिल करने वाले या टीडीएस कटवाने वालों की संख्या, 5.26 करोड़ से बढ़कर 12.13 करोड़ हो गई है। पिछले 11 वर्षों में, करदाताओं की संख्या दोगुनी हो गई है। यह संव्ययी रूप से सालाना 7.9 प्रतिशत की वृद्धि है। वित्त मंत्री ने कहा, यह इस देश में मध्यम वर्ग का सबसे बड़ा संरचनात्मक विस्तार है। इसलिए, अगर कर का दायरा बढ़ रहा है तो दबाव नहीं हो सकता। लोग कर देने के लिए आगे आ रहे हैं और वे इसलिए आगे नहीं आ रहे हैं क्योंकि हम दरे बढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इस विस्तार के बावजूद, आयकर सीमा सभी के लिए 12 लाख और वित्तभोगी वर्ग के लिए 12.75 लाख रुपये तक बढ़ाई गई है। अगर 12.75 लाख कमाने वाले वित्तभोगी वर्ग को कर नहीं देना पड़ता, तो फिर दबाव वाली बात कहां है? दूसरा, मानक कटौती भी बढ़ाई गई है। नई कर व्यवस्था ने कर रिटर्न भरने और जांच को सरल बना दिया है।

बावजूद मुद्रास्फीति ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर है। आज भारत में महंगाई का कोई संकेत नहीं है। स्थिरता और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण मुद्रास्फीति को काबू में लाया गया गया है।

सीतारमण ने कहा, रोजगार के बिना वृद्धि संग्रह सरकार की कहानी थी, वर्तमान सरकार की नहीं। विपक्ष के इस आरोप पर कि मध्यम वर्ग अधिक कर दे रहा है, सीतारमण

ने कहा, यह निष्कर्ष निकालना कि व्यक्तिगत कर संग्रह कॉरपोरेट करों से अधिक होने के कारण मध्यम वर्ग हाशिए पर धकेला जा रहा है, यह स्थिति का पूरी तरह से गलत विश्लेषण है। मध्यम वर्ग को दबाये जाने का कोई सबूत नहीं है। वास्तव में, पिछले दस साल में किए गए आर्थिक सुधारों के कारण ऐतिहासिक रूप से मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ है। इसके पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

देश को परिधान उद्योग में बांग्लादेश की तरह मिलेगा लाभ

नई दिल्ली, एजेंसी

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत को अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते के तहत अमेरिकी धागा और कपास से बने परिधान पर वही रियायती शुल्क का लाभ मिलेगा, जो बांग्लादेश को वर्तमान में मिल रहा है।

अमेरिका, बांग्लादेश की वस्तुओं पर जवाबी शुल्क घटाकर 19 प्रतिशत कर देगा, लेकिन वस्त्रों पर शुल्क शुल्क तभी लागूगा जब वे अमेरिकी कपास और कुत्रिम रेशों से बने हों। वर्तमान में बांग्लादेशी परिधानों पर 31% शुल्क लगता है (12% तराहीशी राष्ट्र शुल्क है और 19% जवाबी शुल्क) और यदि उनमें अमेरिकी रेशों का उपयोग किया जाता है, तो शुल्क घटकर 12% हो जाता है।

गोयल ने कहा, बांग्लादेश को जो

भारत-अमेरिका समझौता



● उद्योग मंत्री गोयल बोले- इसका भारतीय कपास किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा

मिला है, वही भारत को भी अंतिम समझौते में मिलने वाला है। अगर कोई भारतीय कंपनी अमेरिका से धागा और कपास खरीदकर परिधान बनाती है और उन्हें अमेरिका को निर्यात करती है, तो उन परिधानों को भी बांग्लादेशी कंपनियों की तरह अमेरिका में शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा। गोयल ने कहा कि यह बात अमेरिका-बांग्लादेश समझौते

घरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग को रियायती शुल्कों पर मिलेगा व्यापक बाजार

मेडिकल, इन्वेंशन और स्टार्टअप कार्यक्रम में गोयल ने कहा कि भारत के अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों से घरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग को रियायती शुल्कों पर व्यापक बाजार पहुंच प्रणामी। उन्होंने कहा कि कुछ मुक्त व्यापार समझौतों (फुफ्टीए) में भारतीय चिकित्सा उपकरणों को शुल्क में छूट भी मिलेगी। मंत्री ने कहा कि हम नौ एफ्टीए के माध्यम से विकसित बाजारों के लिए द्वार खोल रहे हैं, जिनमें 38 ऐसे देश शामिल हैं जहां की आबादी समूह है और प्रति व्यक्ति आय अधिक है। गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीसीडी) देश में चिकित्सा उपकरण इकाइयों के लिए 50 से 100 एकड़ भूमि आरक्षित करने पर विचार कर सकता है।

में लिखी है और हमारे समझौते में भी होगी। इसका भारतीय कपास किसानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मंत्री ने बताया कि अमेरिका में कपास का उत्पादन सीमित है। उसका निर्यात केवल 50 लाख अमेरिकी डॉलर है, जबकि भारत का लक्ष्य 50 अरब डॉलर है। भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले

चरण के लिए एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसे मार्च में लागू किए जाने की संभावना है। ये टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता पूरी तरह से आत्मसमर्पण है, जिसमें भारत की ऊर्जा सुरक्षा अमेरिका को सौंप दी गई है और किसानों के हितों से समझौता किया गया है।

इंटेल् पर 27.38 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली, एजेंसी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए बॉक्सड माइक्रो प्रोसेसर (बीएमपी) के संबंध में भारत के लिए एक अलग वारंटी नीति अपनाने को लेकर अमेरिकी कंपनी इंटेल् को 27.38 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इंटेल् अमेरिका की प्रमुख बहुराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर कंपनी है, जो कंप्यूटर प्रोसेसर और चिप विनिर्माण के लिए जानी जाती है।

आयोग ने गुरुवार को कहा कि इंटेल् ने भारत में बीएमपी के बाजार में अपनी दबदब की स्थिति का दुरुपयोग किया है। प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच में पाया गया कि भारत के लिए इंटेल् की अलग वारंटी नीति चीन, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों



● बीएमपी के संबंध में अलग वारंटी नीति पर सीसीआई ने की अमेरिकी कंपनी पर कार्रवाई

में लागू उसकी वारंटी नीतियों की तुलना में भेदभावपूर्ण थी। सीसीआई के अनुसार, अमेरिकी कंपनी की इस नीति ने उपभोक्ताओं और समानांतर आयातकों के विकल्प सीमित करने का काम किया, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। समानांतर आयात का मतलब

ऐसे वैध उत्पादों के आयात से है, जो किसी कंपनी के आधिकारिक वितरण चैनल के बाहर से खरीदे जाते हैं।

आयोग ने कहा कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के बीएमपी पर वारंटी संबंधी इंटेल् की यह नीति आठ वर्षों तक लागू रही। इसको ध्यान में रखते हुए नियामक ने इंटेल् के औसत प्रारंभिक कारोबार के आठ 8% के बराबर जुर्माना तय किया। 1 अप्रैल, 2024 से नीति वापस लेने को ध्यान में रखते हुए आयोग ने जुर्माने को घटाकर 27.38 करोड़ रुपये कर दिया। आयोग ने इंटेल् को निर्देश दिया है कि वह भारत-केन्द्रित इस विवादित वारंटी नीति को वापस लिए जाने का व्यापक प्रचार-प्रसार करे और इस पर अनुपालन रिपोर्ट भी पेश करे।

बीमा एक जरूरत पर अब भी बड़ी आबादी है दूर

भारत में हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस की जरूरत आज पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तेजी से बढ़ते मेडिकल खर्च, बीमारियों का खतरा और अनिश्चित आर्थिक परिस्थितियाँ हर परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा को जरूरी बना रही हैं। इसके बावजूद देश की बड़ी आबादी अब भी बीमा कवरेज से दूर है। आंकड़े बताते हैं कि जीवन बीमा कवरेज बेहद सीमित है और हेल्थ इंश्योरेंस भी सभी तक नहीं पहुंच पाया है। महंगे प्रीमियम, जटिल पॉलिसी शर्तें और समझ की कमी इसके प्रमुख कारण हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब बीमा सबकी जरूरत है, तो आखिर क्यों आबादी का बड़ा हिस्सा इससे वंचित है और इस दूरी को कैसे कम किया जा सकता है।

शर्तें बनाती हैं प्रक्रिया जटिल

बढ़ती स्वास्थ्य लागत, गंभीर बीमारियों का जोखिम और कमाई करने वाले पर निर्भरता ने हर परिवार के लिए बीमा को अनिवार्य बना दिया है। फिर भी वास्तविकता यह है कि देश की बड़ी आबादी बीमा सुरक्षा से बाहर है। जीवन बीमा कवरेज सीमित है और हेल्थ इंश्योरेंस की पहुंच भी सार्वभौमिक नहीं हो पाई है। इसकी बड़ी वजह महंगा प्रीमियम और जटिल पॉलिसी शर्तें हैं। जब बीमा उत्पादों में कई तरह के एड-ऑन, शर्तें और अपवाद जुड़े होते हैं, तो आम व्यक्ति के लिए उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। नतीजा यह होता है कि लोग फंसला टाल देते हैं या फिर न्यूनतम कवरेज पर ही रुक जाते हैं।



सरलीकरण में छिपा समाधान

विशेषज्ञों का मानना है कि समाधान प्रोडक्ट के सरलीकरण में छिपा है। आसान भाषा में तैयार की गई, सीमित लेकिन जरूरी कवरेज वाली योजनाएं नए ग्राहकों के लिए बेहतर एंटी पॉइंट हैं। कम प्रीमियम वाली योजनाएं लोगों में भरोसा पैदा करती हैं। जब ग्राहक को स्पष्ट होता है कि वह किस जोखिम के लिए भुगतान कर रहा है, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और आगे बढ़कर वह अधिक व्यापक कवरेज लेने के लिए भी तैयार होता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बीमा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ले आए हैं। ऑनलाइन तुलना, पारदर्शी शर्तें और तेज वेलम प्रोसेस ने भरोसा बढ़ाया है।

एसएमई के लिए योजनाएं

छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए अनुकूलित बीमा योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जरूरत आधारित कवरेज से गैर-जरूरी खर्च कम होते हैं और व्यवसाय अपने वास्तविक जोखिमों को बेहतर तरीके से कवर कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी आधारित अडरराइटिंग और वेलम मैनेजमेंट से समय और लागत दोनों की बचत होती है। बीमा को व्यापक बनाने को कंपनियों को कम पारतं, स्पष्ट कवरेज, किफायती प्रीमियम और सरल प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा। जब बीमा समझने में आसान, खरीदने में सरता और भरोसेमंद बनेगा, तभी एलीट प्रोडक्ट से निकलकर लोगों की जरूरत का साधन बन जाएगा।

डिजिटल भुगतान का दायरा बढ़ने का सिलसिला जारी : आरबीआई

मुंबई, एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गुरुवार को कहा कि देश में डिजिटल भुगतान का दायरा बढ़ने का सिलसिला अप्रैल-सितंबर, 2025 के दौरान भी जारी रहा। आरबीआई ने कहा कि उसका डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआई-डीपीआई) सितंबर, 2025 में 516.76 पर पहुंच गया, जो सितंबर, 2024 में 465.33 और मार्च, 2025 में 493.22 पर था।

देशभर में डिजिटल भुगतान के प्रसार और दायरे को मापने वाला यह सूचकांक जनवरी, 2021 से प्रकाशित किया जा रहा है और मार्च, 2018 को आधार वर्ष मानता है। आरबीआई ने कहा कि सूचकांक में वृद्धि का मुख्य कारण भुगतान प्रदर्शन और भुगतान सक्षम कारकों में

केसीसी का दायरा बढ़ाने को मसौदा संशोधन जारी

मुंबई। आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन और एकीकरण के लिए बहुरूपवित्तियार को मसौदा जारी किया जिसका उद्देश्य कवरेज का विस्तार, परिचालन प्रक्रियाओं का सरलीकरण और कृषि क्षेत्र की उभरती जरूरतों का ध्यान रखना है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि विनियमित संस्थाएं, आम लोग और अन्य हितधारक छह मार्च, 2026 तक मसौदे पर टिप्पणियाँ और सुझाव दे सकते हैं। आरबीआई ने केसीसी ऋण की स्वीकृति और पुनर्भुगतान कार्यक्रम में एकरूपता लाने के लिए फसल सत्रों की अवधि को मानकीकृत करने का प्रस्ताव भी रखा है। इसके तहत कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों को 12 माह के चक्र और लंबी अवधि वाली फसलों को 18 माह के चक्र के रूप में परिभाषित किया गया है। लंबी अवधि की फसलों के चक्र के अनुरूप ऋण अवधि तय करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की कुल अवधि छह वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया है।

उल्लेखनीय बढ़ोतरी है। आरबीआई-डीपीआई पांच प्रमुख मानकों पर आधारित है। इसमें भुगतान सक्षम कारक (25 प्रतिशत भार), मांग पक्ष का भुगतान ढांचा (10 प्रतिशत), आपूर्ति पक्ष का भुगतान ढांचा (15 प्रतिशत), भुगतान प्रदर्शन (45

समुद्री निगरानी, खोज और बचाव अभियान के साथ खुफिया मिशन में आया काम

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

अमृत विचार : रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को नई दिल्ली में कानपुर स्थित हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के परिवहन विमान प्रभाग के साथ भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के लिए आठ डोर्नियर-228 विमानों और परिचालन संबंधी उपकरणों की खरीद के लिए 2,312 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। यह अनुबंध भारतीय उत्पाद खरीद (बाय इंडियन) श्रेणी के तहत हुआ। अनुबंध पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने हस्ताक्षर किए। डोर्नियर 228 विमान उन्नत सेंसर और आधुनिक

विशेष इंतजाम

रक्षा मंत्रालय ने तटरक्षक बल के लिए उन्नत डोर्नियर-228 विमानों का किया अनुबंध

एचएएल को आठ डोर्नियर विमानों के लिए 2,312 करोड़ का आर्डर

● समुद्री निगरानी, खोज और बचाव अभियान के साथ खुफिया मिशन में आया काम



एवियोनिक्स से लैस हैं, जिनमें पूर्ण ग्लास कॉन्फिग, एकीकृत मिशन प्रबंधन प्रणाली तथा समुद्री निगरानी और टोही अभियानों के लिए विशेष इंतजाम शामिल किए गए हैं। इस अनुबंध से न सिर्फ एचएएल का उत्पादन तंत्र मजबूत होगा, बल्कि लघु एवं मध्यम उद्यमों के नेटवर्क को भी समर्थन मिलने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होगा। एचएएल ने बताया कि यह अनुबंध



आत्मनिर्भर भारत और मेक-इन-इंडिया के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के साथ समुद्री सुरक्षा संरचना को भी मजबूत बनाएगा। पिछले माह के अंत में भारतीय तटरक्षक बल को दो डोर्नियर- 228 विमान ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन से सौंपे गए थे। तटरक्षक बल तटीय निगरानी, प्रदूषण पर नजर, खोज और बचाव अभियान और रिजर्व टाइम खुफिया जानकारी जुटाना में



इसका प्रयोग करेगी। डोर्नियर-228 की शॉर्ट टेकऑफ और लैंडिंग क्षमता से इन्हें छोटे और दूरदराज के रनवे से भी उड़ाने जा सकता है। इससे द्वीपों और आगे के इलाकों में तटरक्षक बल की पहुंच बढ़ेगी। एचएएल कानपुर के परिवहन विमान प्रभाग ने 1983 में जर्मनी की मूल कंपनी के साथ प्रौद्योगिकी हस्तोत्तरण समझौते के तहत डोर्नियर विमानों का उत्पादन शुरू किया था।

अब तक यहाँ 124 से अधिक विमानों का निर्माण हो चुका है। यह विमान 19 यात्रियों या 2057 किग्रा तक माल ले जा सकते हैं। शार्ट टेक आफ एंड लैंडिंग परिचालन क्षमता वाले ये विमान छोटी तथा अविकसित हवाई पट्टियों और गमं वातावरण में भी उतरने और उड़ान भरने में सक्षम हैं। डोर्नियर-228 का इस्तेमाल भारतीय वायु सेना, नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा समुद्री गश्त और निगरानी के लिए किया जाता है। अब इसका उपयोग नागरिक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए भी हो रहा है। एयर इंडिया एसेट्स होल्टिंग की सहायक कंपनी एलायंस एयर ने एचएएल से अपना पहला सिविल डीओ-228 विमान खरीदा था। एचएएल अब इसका उन्नत नागरिक संस्करण "हिंदुस्तान 228" भी बना रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि है।

वर्ल्ड वीफ

भारत ने चुनाव में मदद के लिए उपहार में दिए नेपाल को 270 वाहन काटमांडू। भारत सरकार ने बृहस्पतिवार को नेपाल को बुनाव से संबंधित सहायता की तीसरी खेप के तौर पर 270 वाहन सौंपे। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने गृह मंत्रालय में आयोजित एक समारोह में यह तीसरी खेप नेपाल के गृह मंत्री ओम प्रकाश आर्याल को सौंपी। भारतीय दूतावास ने एक विज्ञापित में बताया कि इसमें 170 वाहन शामिल हैं, जिनमें 50 ट्रक नेपाल सेना के लिए हैं। साथ ही पांच भाव को होने वाले चुनाव की तैयारियों के लिए नेपाल की मांग के अनुरूप अन्य सामग्री भी सौंपी गई है। भारत सरकार को 310 से अधिक वाहन और अन्य सामग्री शामिल थीं। प्रेस विज्ञापित में कहा गया है कि आने वाले दिनों में कुछ अतिरिक्त सामग्री भी प्रदान की जाएगी।

व्हाट्सएप का आरोप, रूस ने की एप को ठप करने की कोशिश

मास्को। रूस ने देश में व्हाट्सएप पर पूरी तरह से रोक लगाये का प्रयास किया है। सोशल मीडिया कंपनी ने एक बयान में कहा कि यह ड्रैनेट पर नियंत्रण कड़ा करने के सरकार का नया प्रयास है। व्हाट्सएप के एक प्रवक्ता ने बुधवार देर रात बताया कि रूसी अधिकारियों की यह कार्रवाई 'उपयोगकर्ताओं को सरकार की स्वामित्व के निगरानी वाले ऐप की ओर धकेलने' के उद्देश्य से की गई है। यह रूसी सरकार समर्थित 'मेक्स' मैसेजिंग एप की ओर इशारा है, जिसे आलोचक एक निगरानी उपकरण मानते हैं। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने बताया, "यह 10 करोड़ से अधिक लोगों को निजी और सुरक्षित संचार से अलग करने का प्रयास है और इससे रूस में लोगों की सुरक्षा में ही कमी आएगी। हम लोगों को आपस में जोड़े रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।"

नेतन्याहू के साथ बैठक में ट्रंप का ईरान से वार्ता जारी रखने पर जोर वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेनजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और ईरान के साथ वार्ता जारी रखने पर जोर दिया। अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते को आगे बढ़ाना चाहता है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच यह मुलाकात व्हाट्सएप हाउस में हुई। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, यह मुलाकात बहुत अच्छी रही और दोनों देशों के बीच शानदार रिश्ते जारी रहेंगे। उन्होंने कहा, कुछ भी निश्चित नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि मैंने ईरान के साथ बातचीत पर यह देखने के लिए जोर दिया कि यह समझौता हो सकता है या नहीं।

कनाडा पर टैरिफ: पहली बार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति के विरोध में

वाशिंगटन। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कनाडा पर लगाए गए टैरिफ को पलटने के लिए मतदान किया जो व्हाइट हाउस के एग्जैड के एक दुर्लभ आलोचना है। बुधवार को इस प्रस्ताव के पक्ष में 219 और इसके खिलाफ 211 मत पड़े। ऐसा संभवतः पहली बार है जब रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाली प्रतिनिधि सभा ने किसी महत्वपूर्ण नीति को लेकर राष्ट्रपति का विरोध किया है। प्रस्ताव का उद्देश्य उस राष्ट्रीय आपात स्थिति को समाप्त करना है, जिसे ट्रंप ने टैरिफ लगाने के लिए घोषित किया है लेकिन इस नीति को

भारतीय छात्रा की मौत के मामले में 2.9 करोड़ डॉलर में समझौता

सिएटल, एजेंसी

अमेरिका के सिएटल शहर ने 2023 में एक पुलिस अधिकारी की तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर लगने से जान गंवाने वाली भारत की 23 वर्षीय छात्रा जाह्नवी कंदुला के परिवार के साथ 2.9 करोड़ डॉलर (262.65 रुपये)के समझौते पर सहमति जताई है। कंदुला को अधिकारी केविन डेव की गाड़ी ने उस समय टक्कर मारी थी, जब वह 40 किमी घंटे की सीमा वाले क्षेत्र में 119 किमी की रफ्तार से जा रहे थे। कंदुला सिएटल स्थित नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी परिसर में इन्फार्मेशन सिस्टम्स में मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाई कर रही थीं। कंदुला के परिवार के वकीलों ने तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों पक्षों ने पिछले शुक्रवार को किंग

सिएटल में तेज रफ्तार गाड़ी की चपट में आकर हुई थी मौत, आरोपी पुलिस अधिकारी बर्खास्त

काउंटी सुपीरियर कोर्ट में समझौते की सूचना दाखिल की। कंदुला की मौत के बाद व्यापक प्रदर्शन हुए थे। लोगों का आक्रोश इस बात पर भड़का जब एक अन्य अधिकारी के बॉडी कैमरा की रिकॉर्डिंग सामने आई, जिसमें वह हंसते हुए कंदुला के जीवन को मामूली बताते और यह कहते सुनाई दिया कि शहर को सिर्फ एक चेक लिख देना चाहिए। डेनियल ऑडरर नाम के इस अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया था। पुलिस विभाग ने वाहन चला रहे अधिकारी को भी बर्खास्त कर दिया और उसे 5,000 डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया।

यौन अपराधी खादी कहीं संत के चोले में

जोड़ी एस्टीन की फाइन्स सार्वजनिक होने के साथ उसके धिनीने अपराधों पर दुनिया में नए सिरे से एक बहस छेड़ी है लेकिन एस्टीन को छोड़ भी दिया जाते दुनिया का इतिहास क्रूर यौन अपराधों से भरा हुआ है। अपनी संस्कृति और संस्कारों की वजह से जाने जाने वाले भारत में भी ऐसे अपराधों की कमी नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स (एडीआर) की अगस्त 2024 में जारी रिपोर्ट ऐसे ही धिनीने सच का पर्दाफाश करती है जिसके मुताबिक देश के 151 से ज्यादा मौजूदा सांसदों और विधायकों पर यौन अपराधों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले दर्ज हैं। संत के चोले में भी तमाम यौन अपराधियों के क्रूर कारनामे जगजाहिर हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि समाज में दबदबा रखने वाले कई यौन अपराधियों के खिलाफ पुलिस के भ्रष्टाचार या राजनीतिक दबाव की वजह से पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया।

भारत के 'एस्टीन'



सफेदपोश यौन अपराधी

- देश के 151 मौजूदा सांसदों और विधायकों ने चुनावी हलफनामों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामलों की घोषणा की है।
- एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार इनमें 16 सांसद और 135 विधायक शामिल हैं। दो सांसद, 14 विधायकों पर बलात्कार के आरोप दर्ज हैं।
- भाजपा के सबसे अधिक 54 सांसदों और विधायकों पर ऐसे मामले दर्ज हैं। 123 के साथ कांग्रेस दूसरे 17 के साथ टीडीपी तीसरे स्थान पर है।
- पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 25 जन्मतिनिधि, आंध्र प्रदेश में 21 और ओडिशा में 17 जनप्रतिनिधियों पर यौन अपराधों के मामले दर्ज हैं।

बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं के बीच

13वें आम चुनाव के लिए हुआ मतदान मारी सुरक्षा तैनाती के बावजूद मतदान केंद्रों पर धमाके, देर शाम मतगणना शुरू

ढाका, एजेंसी

बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए लोगों ने बृहस्पतिवार को हिंसा की घटनाओं के बीच मतदान किया। जटिल 84 सूत्री सुधार पैकेज पर जनमत संग्रह के साथ हुए 13वें आम चुनाव में देश भर में 300 में से 299 संसदीय सीट के लिए सुबह साढ़े सात बजे मतदान शुरू हुआ जो शाम साढ़े चार बजे तक जारी रहा। मतदान पूरा होने के बाद ज्यादातर जगहों पर मतगणना भी शुरू कर दी गई। एक उम्मीदवार की मृत्यु होने के कारण एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान रद्द कर दिया गया है। हसीना की अब भंग हो चुकी अवामी लीग की गैरमौजूदगी में मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और उसकी पूर्व सहयोगी जमात-ए-इस्लामी के बीच है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने शोख हसीना की अवामी लीग को पिछले साल भंग कर दिया था और पार्टी के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। बांग्लादेश निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद के मुताबिक दोपहर दो बजे तक 48 प्रतिशत मतदान हुआ। देश भर में 299 निर्वाचन क्षेत्रों में 42,779 मतदान केंद्रों पर लगभग 12.7 करोड़ मतदाता पंजीकृत थे। बांग्लादेश की दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी पार्टियों के शीर्ष नेताओं के साथ मुख्य सलाहकार यूनुस ने शुरूआत में ही मतदान किया।



ढाका के एक मतदान केंद्र पर बृहस्पतिवार को अपना वोट डालकर लौटती महिलाएं।

कुल 50 राजनीतिक दलों के 1,755 उम्मीदवार और 273 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। बीएनपी के सर्वाधिक 291 उम्मीदवार हैं, चुनाव में 83 महिला उम्मीदवार हैं।

एक के बाद एक मतदान केंद्रों पर होते रहे बम के धमाके

मतदान के बीच कई जगहों से चुनावी हिंसा की खबरें आती रही। गोपालगंज में बम हमले में 13 वर्षीय लड़की सहित तीन लोग घायल हो गए। बृहस्पतिवार सुबह करीब नौ बजे निचुआडी स्थित रेशमा इंटरनेशनल स्कूल में बने मतदान केंद्र में विस्फोट हुआ। इस घटना में चुनाव सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अर्द्धसैनिक सहायक बल 'अंसार' के दो सदस्य भी घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। मतदान केंद्र के पीटीसीन अधिकारी जहिरुल इस्लाम ने बताया कि घायलों को मामूली चोट आई थी और मतदान थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो गया। एक अन्य घटना में भुशीगंज-3 निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र के बाहर सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए, जिससे मतदान अस्थायी रूप से बाधित हो गया। सुबह करीब 10 बजकर 15 मिनट पर म्हाती मुकुरचण हाई स्कूल में बने मतदान केंद्र के सामने विस्फोट हुए। अधिकारियों ने बताया कि 10 से 12 देसी बमों में धमाका हुआ। केंद्र पर मतदान कुछ देर के लिए रोक दिया गया। पीटीसीन अधिकारी मोहम्मद तितुमिर ने कहा कि विस्फोटों से मतदाताओं में दहशत फैल गई लेकिन कुछ देर बाद मतदान फिर से शुरू हो गया। इसके अलावा, खुलना में एक मतदान केंद्र के बाहर जमात-ए-इस्लामी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प के दौरान एक बीएनपी नेता की मौत हो गई। बीएनपी का कहना है कि जमात के एक नेता के धक्का देने की वजह से पेड़ से टकराकर वह घायल हो गए थे, जिससे उनकी मौत हुई।

ऐतिहासिक: हिंसा रोकने के लिए 10 लाख सुरक्षा कर्मी

निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर लगभग 10 लाख सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया जो देश के चुनावी इतिहास में सुरक्षाकर्मियों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके अलावा प्रशासन ने राजधानी के प्रमुख इलाकों में बखरबंद वाहन और त्वरित की बंद (आरएटी) तैनात किए हैं। पहली बार चुनाव सुरक्षा के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। करीब 81 स्थानीय संगठनों के 55,454 पर्यवेक्षकों ने चुनाव की निगरानी की, जबकि विदेशी चुनाव पर्यवेक्षकों की संख्या 394 रही। अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों में से 80 विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों की तरफ से हैं, जबकि बाकी अलग-अलग देशों से हैं, जिनमें स्वतंत्र यूरोपीय पर्यवेक्षक भी शामिल हैं।

धांधली और फर्जी मतदान की भी तमाम खबरें

उत्तर पश्चिमी जंयपुरहाट के कलाई इलाके में एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मतपत्रों की फोटोकॉपी वितरित करने के आरोपों पर पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा, उत्तर पूर्व सिलहट के बालागंज उप-जिले में मतपत्रों की हेराफेरी के आरोपों में जमात और बीएनपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जहां एक स्थानीय जमात नेता और कई अन्य लोग भी आधी रात के आसपास एक मतदान केंद्र में घुस गए तभी बीएनपी कार्यकर्ताओं ने उन पर धावा बोला, जिसके परिणामस्वरूप हाथापाई हुई जिस पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा।

सर्वाधिक चर्चित मामले

- पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते पूर्व सांसद प्रज्वल रेवना के यौन शोषण के हजारों वीडियो वायरल हुए थे। उसे अगस्त 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
- उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेनार को 2017 में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का दोषी पाया गया। उसे उम्रकैद की सजा दी गई।
- हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा पर एयरहोस्टेस गीतिका शर्मा के यौन उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उक्ताने का आरोप लगा, सुसाइड नोट में नाम आया।
- मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री पर उनके घरेलू पुरुष सहायक ने कुकर्म के आरोप लगाए थे, मामला सुर्खियों में आने के बाद उन्हें इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा था।

खौफनाक आंकड़ा

यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 37 करोड़ से अधिक लड़कियों और महिलाएं बलात्कार या यौन हमले का शिकार हुई हैं।

संतों के चोले में यौन अपराधी

- आसाराम बापू नाबालिग लड़कियों से बलात्कार पर जोधपुर और गांधीनगर की अदालत से उम्रकैद।
- डेरा सच्चा सोदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दो महिला अनुयायियों से बलात्कार पर 20 साल जेल।
- आसाराम के बेटे नारायण साई को भी शिष्या से बलात्कार के जुर्म में सूरत की अदालत से उम्रकैद।
- तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली स्थित आश्रम संचालक प्रेमानंद ने 13 महिलाओं से बलात्कार किया।
- केरल का स्वयंभू संत अमृता चैतन्य नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के मामले में दोषी पाया गया।

दुनिया के सबसे क्रूर

- जापान के जुंको फुरुता में 1988 में 17 वर्षीय छात्रा को अगवा कर 44 दिनों में 400 से अधिक बार बलात्कार किया गया, उसकी मृत्यु हो गई।
- ऑस्ट्रेलिया में नर्स अनीता कोबी का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर होश में रहते बेरहमी से उनकी गर्दन काट दी गई।
- दिल्ली में 2012 में चलती बस में छात्रा से हुई दरिदगी ने दुनिया को झकझोरा जिसकी मृत्यु हो गई। ये मामला निभेया कांड के नाम से मशहूर हुआ।

मतदान से पहले हिंदू मजदूर की हत्या

ढाका। पूर्वोत्तर बांग्लादेश के मौलवी बाजार इलाके में एक युवा हिंदू चाय बागान मजदूर का खून से लथपथ शव मिला जिसके हाथ-पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को मतदान से पहले यह लगातार दूसरे दिन किसी हिंदू व्यक्ति की हत्या का मामला है। पुलिस ने बुधवार को ढाका से लगभग 200 किमी उत्तर-पूर्व में स्थित मौलवी बाजार के कमलगांज उपजिले के एक चाय बागान से 28 वर्षीय रतन शुवो कार का शव बरामद किया। 'द डेलेरी स्टार' ने कमलगांज पुलिस थाने के प्रभारी अब्दुल अवाल के हवाले से खबर दी

कि मृतक रतन शुवो कार इस्लामपुर यूनिवर्स के अंतर्गत चंपारा चाय बागान में बतौर मजदूर काम करता था। लोगों ने बुधवार पूर्वाह्न करीब 10:00 बजे बागान में शव को देखा और अधिकारियों को सूचना दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक शव पर चोट के स्पष्ट निशान थे और वह खून से लथपथ था। रतन के बड़े भाई लक्ष्मण कार ने बताया कि परिवार मंगलवार रात से ही उसकी तलाश कर रहा था। उन्होंने बताया, बुधवार सुबह हमें सूचना मिली कि उसका शव बागान में पड़ा है। हम वहां गए और उसकी पहचान की। हमें नहीं पता कि उसकी हत्या क्यों की गई।

इतालवी तटों पर कड़ी नौसैनिक नाकाबंदी का विधेयक पारित

रोम। इटली की प्रधानमंत्री जिजोर्जिया मेलोनो के नेतृत्व वाली रूढ़िवादी सरकार ने अवैध आब्रजन से निपटने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है जिसके तहत इतालवी तटों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे प्रवासी पोतों के लिए नौसैनिक नाकाबंदी करने का प्रावधान भी शामिल है। विधेयक को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में चर्चा और मंजूरी के बाद प्रभावी होगा। इसमें सीमाओं पर कड़ी निगरानी और यूरोपीय एजेंसियों के साथ सहयोग का प्रावधान शामिल है। विधेयक प्रवासन और शरण संबंधी नए यूरोपीय संघ समझौते को मंजूरी दिए जाने के एक दिन बाद पारित किया गया है।

भारत के साथ समझौता ऐतिहासिक, विशाल ऊर्जा निर्यातक बनेंगे हम: ट्रंप न्यूयॉर्क/वाशिंगटन।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि अमेरिका भारत और उन देशों को कोयले का निर्यात बढ़ाएगा जिनके साथ उसने व्यापार समझौते किए हैं। ट्रंप ने 'वैशियन ऑफ कोल' शीर्षक वाले एक कार्यक्रम के दौरान कहा, हमारे नेतृत्व में हम एक विशाल ऊर्जा निर्यातक बन रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ही हमने जापान, कोरिया, भारत और अन्य के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौते किए हैं ताकि हमारे कोयला निर्यात को बढ़ाया जा सके। अमेरिका और भारत ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि वे व्यापार पर एक अंतरिम समझौते की रूपरेखा पर पहुंच गए हैं जिसके तहत नई दिल्ली सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं, खाद्य एवं कृषि उत्पादों के एक व्यापक श्रृंखला पर शुल्क समाप्त करेगी या घटाएगी और अगले पांच साल में 500 अरब अमेरिकी डॉलर के अमेरिकी उत्पादों की खरीद करेगी।

ऊर्जा, अक्सर-चन्या पर रूस के हवाई हमले, यूक्रेन में बिजली-पानी ठप

कीव। रूसी हवाई हमलों ने यूक्रेन के कई इलाकों में ऊर्जा अवसंरचनाओं को निशाना बनाया जिससे बिजली और पानी की आपूर्ति में बड़े पैमाने पर रुकावट आई है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने रात भर में 24 बैलिस्टिक मिसाइल, एक निर्देशित एयर-लॉन्च मिसाइल और 219 हमला करने वाले ड्रोन लॉन्च किए। यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली ने 213 निशानों को रोक लिया, लेकिन नौ मिसाइल और 19 ड्रोन 13 जगहों पर हमला करने में कामयाब रहे जिससे अवसंरचना को नुकसान हुआ।

ब्रिटिश शाही सेना के पायलटों को प्रशिक्षण देगी भारतीय वायुसेना

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना पहली बार ब्रिटेन की शाही वायुसेना के पायलटों को प्रशिक्षण देने जा रही है। यह निर्णय बृहस्पतिवार को ब्रिटेन-भारत वायुसेना वार्ता में लिया गया। ब्रिटेन के मुताबिक, नवीनतम समझौते के तहत, भारतीय वायुसेना तीन योग्य उड़ान प्रशिक्षकों को ब्रिटेन में शाही वायुसेना ली में तैनात करेगी जो ब्रिटिश लड़ाकू विमानों के पायलटों के लिए प्रशिक्षण केंद्र है। यह पहली बार है कि भारतीय योग्य उड़ान प्रशिक्षक अरएएफ वेली में ब्रिटिश पायलटों को लड़ाकू विमानों का प्रशिक्षण देंगे। यह घटनाक्रम जनवरी में भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी की शाही वायुसेना महाविद्यालय क्रैवेल में प्रशिक्षक के रूप में पहली बार तैनाती के टिक बहा हुआ है।

आज का भविष्यफल -श.कालिका कुम्हार हिंदी आज की ग्रह स्थिति: 13 फरवरी, शुक्रवार 2026 संवत् -2082, शक संवत् 1947 मास-फाल्गुन, पक्ष-कृष्ण पक्ष, एकादशी 14.25 तक तत्पश्चात द्विदशी।

आज का वाराण

शु.	बु.	गु.	घ.
11	10	9	8
12	मं.	1	2
	1	7	
	10	4	6
2	3	गु.	5
		के.	

दिशाशुल - पश्चिम, ऋतु - शिशिर। चन्द्रबल - मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ, मीन। ताराबल - अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, रेवती। नक्षत्र - मूल 16.12 तक तत्पश्चात पूर्वाषाढा।

आज मन में असंतोष का भाव रह सकता है। धार्मिक लोगों से सलाह लेना उत्तम होगा। प्रेम संबंधों को लेकर भावुक हो सकते हैं। आर्थिक निवेश को लेकर सावधान रहें। अनैतिक कार्यों से दूरी बनाकर रखें। सर्दी-खांसी से आपको परेशानी हो सकती है।

आज ऊंचाई वाली जगहों से दूरी बनाकर रखें। जीवनसाथी के प्रति आसक्ति का भाव बढ़ेगा। संतान से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आप अपने मित्रों की काफ़ी सहायता करेंगे। अविवाहित लोगों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं।

आज आपका दिन विशेष उन्नतिकारक रहेगा। आय की दृष्टि से भी दिन बहुत ही अच्छा है। दोपहर तक कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपके स्वभाव में विनम्रता बढ़ेगी। आप चुनौतियों को आसानी से निपटा लेंगे। अधूरे पड़े कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं।

आज पुराने लोन को चुकाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपके भीतर स्नेह और वास्तव्य की भावना रहेगी। पाचन तंत्र की सेहत का ध्यान करें। कार्यक्षेत्र में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। आप काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे।

आज अवानक घन लाभ होने के योग बन रहे हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। घर के सदस्यों को महत्व दें। वाणी में संयम रहें। रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें। किसी पुराने मित्र से आपका हो सकता है।

आज जीवन की सच्चाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपको कारोबार में अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। आपको यात्रा कम से कम करनी चाहिए। भावनात्मक उतार-चढ़ाव पर नियंत्रण रखें। अपने स्वभाव में लचीलापन बनाकर रखें।

आज प्रतियोगिता और परीक्षा में आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आपको पिछले अनुभवों का लाभ प्राप्त होगा। उच्च-अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे। व्यापार में बदलाव करने की योजना बना सकते हैं।

आज आप अपनी आय बढ़ाने के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील रहेंगे। परिवार में छोटों की चिंता रहेगी। प्रियजनों के व्यवहार को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे। जीवनसाथी आपका मनोबल बढ़ाएगा। लोगों पर आपका प्रभाव काफी अच्छा पड़ेगा।

आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहना वाला है। प्रेमीजन से अपने मन की बातें शेयर कर सकते हैं। आप दूसरों की सहायता करेंगे। नए कार्यों में आप रुचि ले सकते हैं। उच्च अधिकारी आपका सहयोग कर सकते हैं।

आज के दिन आपको तनाव का सामना करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट हो सकती है। कुछ लोग आपको तरक्की से ईर्ष्या कर सकते हैं। मेडिकल सेवा से जुड़े लोगों को परेशानी हो सकती है। अनावश्यक खर्चों को कम करने का प्रयास करें।

आज दार्शनिक लोगों के विचारों से आप प्रभावित रहेंगे। लोगों की बातों को अधिक महत्व न दें। जीवनसाथी की सलाह का अनुसरण करें, इससे आपको लाभ होगा। नया वाहन खरीद सकते हैं। व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। पुराने लोन को चुकाने में आसानी होगी।

आज आपको शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ सकता है। सरकारी कार्यों में ध्यान देने का प्रयास करें। गंभीरता से परिस्थितियों का अवलोकन करें। घर के वास्तु में कुछ परिवर्तन करने का विचार बना सकते हैं। पिता की सलाह से काम करना हितकर होगा।

आज प्रतियोगिता और परीक्षा में आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आपको पिछले अनुभवों का लाभ प्राप्त होगा। उच्च-अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे। व्यापार में बदलाव करने की योजना बना सकते हैं।

आज आप अपनी आय बढ़ाने के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील रहेंगे। परिवार में छोटों की चिंता रहेगी। प्रियजनों के व्यवहार को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे। जीवनसाथी आपका मनोबल बढ़ाएगा। लोगों पर आपका प्रभाव काफी अच्छा पड़ेगा।

आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहना वाला है। प्रेमीजन से अपने मन की बातें शेयर कर सकते हैं। आप दूसरों की सहायता करेंगे। नए कार्यों में आप रुचि ले सकते हैं। उच्च अधिकारी आपका सहयोग कर सकते हैं।

आज के दिन आपको तनाव का सामना करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट हो सकती है। कुछ लोग आपको तरक्की से ईर्ष्या कर सकते हैं। मेडिकल सेवा से जुड़े लोगों को परेशानी हो सकती है। अनावश्यक खर्चों को कम करने का प्रयास करें।

आज दार्शनिक लोगों के विचारों से आप प्रभावित रहेंगे। लोगों की बातों को अधिक महत्व न दें। जीवनसाथी की सलाह का अनुसरण करें, इससे आपको लाभ होगा। नया वाहन खरीद सकते हैं। व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। पुराने लोन को चुकाने में आसानी होगी।

आज आपको शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ सकता है। सरकारी कार्यों में ध्यान देने का प्रयास करें। गंभीरता से परिस्थितियों का अवलोकन करें। घर के वास्तु में कुछ परिवर्तन करने का विचार बना सकते हैं। पिता की सलाह से काम करना हितकर होगा।

आज प्रतियोगिता और परीक्षा में आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आपको पिछले अनुभवों का लाभ प्राप्त होगा। उच्च-अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे। व्यापार में बदलाव करने की योजना बना सकते हैं।

आज आप अपनी आय बढ़ाने के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील रहेंगे। परिवार में छोटों की चिंता रहेगी। प्रियजनों के व्यवहार को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे। जीवनसाथी आपका मनोबल बढ़ाएगा। लोगों पर आपका प्रभाव काफी अच्छा पड़ेगा।

आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहना वाला है। प्रेमीजन से अपने मन की बातें शेयर कर सकते हैं। आप दूसरों की सहायता करेंगे। नए कार्यों में आप रुचि ले सकते हैं। उच्च अधिकारी आपका सहयोग कर सकते हैं।

आज के दिन आपको तनाव का सामना करना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट हो सकती है। कुछ लोग आपको तरक्की से ईर्ष्या कर सकते हैं। मेडिकल सेवा से जुड़े लोगों को परेशानी हो सकती है। अनावश्यक खर्चों को कम करने का प्रयास करें।

आज दार्शनिक लोगों के विचारों से आप प्रभावित रहेंगे। लोगों की बातों को अधिक महत्व न दें। जीवनसाथी की सलाह का अनुसरण करें, इससे आपको लाभ होगा। नया वाहन खरीद सकते हैं। व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। पुराने लोन को चुकाने में आसानी होगी।

आज आपको शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ सकता है। सरकारी कार्यों में ध्यान देने का प्रयास करें। गंभीरता से परिस्थितियों का अवलोकन करें। घर के वास्तु में कुछ परिवर्तन करने का विचार बना सकते हैं। पिता की सलाह से काम करना हितकर होगा।

हुड्डूकू -60

सुडोकू एक तरह का तर्क वाला खेल है, जो एक वर्ग पहेली की तरह होता है। जब आप इस खेल को खेलना सीख जाते हैं तो यह बहुत ही सरलता से खेला जा सकता है। सुडोकू खेल में बॉक्स में 1 नंबर से 9 नंबर तक आने वाले अंक दिए हैं। इसमें कुछ बॉक्स खाली हैं, जिन्हें आपको भरना है। कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। एक सीधी लाइन और एक खड़ी लाइन तथा बॉक्स में नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए।

		6		5	
3	8		2	7	
		4	7		1
8			5	1	
1					9
	2		7		
	3		9		
1	2			3	8
			8		

सुडोकू - 59 का हल

5	3	1	2	8	4	9	7	6
8	9	4	6	3	7	2	1	5
2	6	7	5	1	9	8	3	4
6	5	2	9	7	3	4	8	1
4	7	9	1	2	8	6	5	3
3	1	8	4	6	5	7	9	2
1	4	3	7	9	6	5	2	8
9								

